राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शनिवार • 21 सितम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

अत्याचार और अनाचार को सिर झुका कर वे ही सहन करते हैं, जिनमें नैतिकता और चरित्र का अभाव होता है।

-कमलापति त्रिपाठी

कश्मीर में बदलाव की शुरुआत

जम्मू-कश्मीर के लिए नागरिकों के लिए बुधवार, 18 सितम्बर विशेष महत्त्व का रहा। 2019 में संविधान का अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहली बार हो रहे विधानसभा के चुनावों में लोगों ने भारी उत्साह के साथ मतदान किया। सात जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर पहले चरण के चुनाव का वोटिंग पैटर्न और बिहेवियर राज्य की सियासत में महत्त्वपूर्ण बदलाव के संकेत दे रहे हैं। उम्मीद है कि दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में लोग और ज्यादा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे। एक दशक बाद हो रहे विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में 61.08 फीसद मतदान हुआ। यह प्रतिशत 2009, 2014 और 2024 के लोक सभा और 2008 एवं 2014 के विधानसभा चुनावों की तुलना में बहुत ज्यादा है जो बताता है कि मतदाताओं ने चुनाव के बहिष्कार,

अलगाववाद और आतंकवाद को सिरे से खारिज किया है। राज्य प्रशासन और सुरक्षा बलों की विशेष सतर्कता के कारण पड़ोसी देश भी चुनाव में किसी तरह की अशांति फैलाने में नाकाम रहा। अब वहां के एक मंत्री यह बयान देकर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका दल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विचारों से सहमत है कि अनुच्छेद 370 बहाल किया जाना चाहिए। उनके बयान से सियासत गरमा गई है। कटरा की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोरदार ढंग से कहा कि मैं यहां पाकिस्तान का एजेंडा लागू नहीं होने दूंगा। दुनिया की कोई ताकत अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती। जाहिर है कि पाकिस्तान के मंत्री का बयान चुनाव सभाओं में उठाया ही जाएगा। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को अपने बचाव में बयान देना पड़ा है कि मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान क्या कह रहा है क्योंकि मैं पाकिस्तानी नहीं, भारतीय नागरिक हूं। यह सच है कि इस चुनाव में अनुच्छेद 370 की बहाली और राज्य का दर्जा प्रमुख मुद्दों के रूप में छाया रहेगा। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने पर केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। बुलेस्पतिवार को एक सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को आश्वासन भी दिया कि जम्मू-कश्मीर जल्द पूर्ण राज्य बनेगा। वस्तुतः इस पर्वतीय राज्य के नागरिक करीब चार दशकों से आतंकवाद और अलगाववाद के दंश की पीड़ा झेल रहे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि चुनावों के बहिष्कार से कुछ नहीं मिला। वे ऐसी सरकार चाहते हैं जो राजनीति की गतिशीलता को बदले और उनकी अधिकारों की रक्षा करे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बदलाकारी राजनीति में अनुच्छेद 370 की समाप्ति महती भूमिका निभाएगी।

सवाल फैसले पर

सुप्रीम कोर्ट ने स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत किसी मामले में जमानत देने को बहुत गंभीर मसला कहा है। पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह बताने का निर्देश दिया कि वह एक मामले में चार आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने के लिए विचार कर रही है क्या? याचिकाकर्ता के अनुसार मामले के छह आरोपियों में से चार को गिरफ्तारी पूर्व जमानत दी गई है जबकि उनमें से एक नियमित जमानत पर है। पीठ ने आश्चर्य जताया कि इस मामले में अग्रिम जमानत के बारे में कभी नहीं सुना गया। अदालत ने कहा हम राज्य को सह-आरोपी को दी

गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करने का निर्देश दे सकते हैं। याचिका में आरोपी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती है जिसमें अक्टूबर, 2023 में दर्ज मामले में नियमित जमानत की मांग वाली उसकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। हाई कोर्ट का कहना था, नमूनों की जांच सकारात्मक है जो संकेत है कि जब्त सामग्री प्रतिबंधित है। इसमें गांजा की व्यावसायिक मात्रा एनडीपीसी अधिनियम की धारा 37 में प्रतिबंधों को आधार बनाते हुए अदालत ने जमानत खारिज की थी। 2021 में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह चुका है कि गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की तरह एनडीपीएस भी एकपक्षीय जमानत दिए जाने और प्रथम दृष्टया संतुष्टि के बिना कि आरोपी निर्दोष है और भविष्य में उसके द्वारा अपराध करने की संभावना नहीं है, जमानत दिए जाने से रोकता है। अदालतें विवेक और साक्ष्यों के आधार पर एक जैसे मामलों में अलग-अलग फैसले देती रही हैं। हालांकि जैसा कि शीर्ष अदालत ने नाराजगी जताई कि छह में से चार आरोपियों को पूर्व जमानत और उक्त याचिकाकर्ता पर सख्ती संदेह पैदा करती है वरना सह-अभियुक्तों की जमानत तत्काल खारिज की जानी चाहिए। मामला अदालत में है, जब तक सजा नहीं सुना दी जाती। कोई कानूनी पेचीदगी आड़े नहीं आती तो कड़ी शर्तों के साथ उसे भी कुछ दिनों की जमानत देने का रास्ता निकालना नामुमकिन नहीं लगता।

कटाक्ष/ कबीरदास

गाली दो, गोली लो!

विरोधी झूठ बोल रहे हैं। नड्डा साहब ने कभी नहीं कहा कि गाली का जवाब गोली है। उल्टे नड्डा साहब ने तो खरगे जी की शिकायती चिट्ठी का जवाब शिकायती चिट्ठी से दिया है। उल्टे चिट्ठी से जवाब देने में गजब की उदारता भी दिखाई है। खरगे ने चिट्ठी लिखी पीएम मोदी को और नड्डा साहब ने बीच में ही चिट्ठी लपक कर जवाब भी दे दिया। वह भी एक पन्ने की चिट्ठी का जवाब तीन पन्ने में। और क्यों न हो, लोक सभा में उनकी पार्टी के सदस्य भी तो खरगे की पार्टी से दाई गुना हैं। जवाबी चिट्ठी का ढाई गुना वजन तो वैसे भी बनता है। और चिट्ठी के जवाब में चिट्ठी में, गाली के जवाब में गोली की बात कहां से आ गई? राहुल गांधी के लिए या किसी और के लिए, गोली की बात तो किसी भगवा नेता कही ही नहीं।

दिल्ली वाले तलविंदर सिंह मारवाह साहब ने तो सिर्फ इतना कहा है कि राहुल गांधी का वही हश्र होगा, जो उनकी दादी का हुआ था। माना कि इंदिरा गांधी के हश्र में चौंतीस गोलियां खाना शामिल है, मगर मजाल है जो बंदे ने अपने मुंह से एक बार गोली शब्द निकलने भी दिया हो। रही महाराष्ट्र के विधायक के राहुल गांधी की जीभ काटने के ऑफर की बात तो, बेचारे विधायक जी ने तो गोली-वारूद का कोई जिक्र ही नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ जीभ काटने की सुपारी का ऐलान किया है, और वह भी ठीक ग्यारह लाख रुपये की सुपारी। सुपारी में भी गिनती के शुभ होने न होने का ख्याल रखने वाले संस्कारी बंदे पर, गोली की हिंसक बात करने का इल्जाम कैसे लगाया जा सकता है? प्रभु नरेन्द्र को कभी किसी की दी गाली को याद कर, गोली की बात करने का ही इल्जाम हो, तब भी नहीं। रही बात केंद्र के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और यूपी के मंत्री, रघुराज सिंह की तो, उन्होंने तो सिंपली राहुल गांधी को आतंकवादी नंबर वन कहा है। मंत्री लोग आतंकवादी को नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा। पर गाली हो न हो, गोली का जिक्र हॉरंजि नहीं है। पता नहीं क्यों फिर भी लोग मोदी जी पर राहुल की सुरक्षा खतरे में डालने का इल्जाम लगा रहे हैं। वह बेचारे तो सिर्फ दूसरी तरफ की गालियों का हिसाब रखते हैं, अपनी तरफ की गोलियों का नहीं।

क्यों बन जाता है जल-ग्राम

गुरुग्राम

पंकज चतुर्वेदी

बीते तीन साल में सौ करोड़ खर्च हो गए लेकिन हर बारिश की पुकार के साथ दुनिया में मशहूर औद्योगिक शहर गुरुग्राम के दरिया बनने की दिक्कत गहराती गई। इस साल तो गुरुग्राम अभी तक ग्यारह बार पानी भरने से बेसुध हो चुका है। चौड़ी सड़कें, गगनचुंबी इमारतें और दमकती रोशनी उस समय निढाल हो जाती है जब कोई बादल बरसने पर हाथीडुबाव पानी का ठहराव लाचारी का भाव देता है। हर बार कुछ घंटे के जाम में कई सौ सौ करोड़ का घाटा गुरुग्राम को उठाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का इस शहर के प्रति विश्वास डगमगाता है, वह अलग।

इसमें कोई शक नहीं कि बीते एक दशक में गुरुग्राम में ढेर सारे फ्लाईओवर, अंडरपास, चौड़ी सड़कें बनीं, लेकिन ड्रेन की थोड़ी सी कृपा इंजीनियरों के तकनीक कौशल पर कालिख पोत देती है। बूंद-बूंद पानी को तरसने वाले गुरुग्रामवासी बरसात की आशंका से ही कांप जाते हैं। इस साल जलभराव के कारण कोई ग्यारह बार गुरुग्राम में कई-कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। महकमे इसके निदान के लिए और अधिक निर्माण करने की सिफारिश करते हैं, लेकिन समस्या के मूल में प्रकृति से छेड़छाड़ पर बात करने से बचते हैं।

अचानक तेज और अप्रत्याशित बरसात हो जाना या नाले-सीवर साफ न होना जैसे कारण तो देश के हर शहर को बरसात में लज्जित कर ही रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम के डूबने का असल कारण तो यहां के कई नदी-नालों को गुम कर वहां कंक्रीट का जंगल खड़ा करना है। असल में इस जलजमाव और उससे उपजे जाम का कारण गुड़गांव की बेशकीमती जमीन और उसे हड़पने के लोभ में कब्जाई गई वे जमीनें हैं, जो असल में बेतहाशा बरसात में भी पानी को अपने में समा कर नजफगढ़ झील तक ले जाने का प्राकृतिक रास्ता हुआ करती थीं। एमसीआर में यमुना नदी के बाद सबसे बड़े जल क्षेत्र को हमने कुछ ही दशकों में सुखा दिया और उस पर सीमेंट के जंगल रोप दिए, फिर जो लोग बसे उनके घर और रोजगार के ठिकानों से निकला गंदा पानी भी इसमें ही जुड़ता गया। अब सरकार खुद

दिल्ली-गुड़गांव अरावली पर्वतमाला के तले है और अभी सौ साल पहले तक इस पर्वतमाला पर गिरने वाली हर एक बूंद 'डाबर' में जमा होती थी। 'डाबर' यानी उत्तरी-पश्चिम दिल्ली का वह निचला इलाका जो पहाड़ों से घिरा था। इसमें कई अन्य झीलों और नदियों का पानी आकर भी जुड़ता था। इस झील का विस्तार एक हजार वर्ग किलोमीटर हुआ करता था जो आज गुड़गांव के सेक्टर 107, 108 से ले कर दिल्ली के नये हवाई अड्डे के पास पप्पनकलां तक था। इसमें कई प्राकृतिक नहरें और सरिता थीं, जो दिल्ली की जमीन, आबोहवा और गले को तर रखती थीं। आज दिल्ली के भूजल के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक बना नजफगढ़ नाला कभी जयपुर के जीतगढ़ से निकल कर अलवर, कोटपुतली, रेवाड़ी और रोहतक होते हुए नजफगढ़ झील और वहां से दिल्ली में यमुना से मिलने वाली साबी, साहिबी या रोहिणी नदी हुआ करती था। इस नदी के जरिए नजफगढ़ झील का अतिरिक्त पानी यमुना में मिल जाया करता था।

1912 के आसपास दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ आई और अंग्रेजी हुकूमत ने नजफगढ़ नाले को गहरा कर उससे पानी निकासी की जुगाड़ की। उस दौर में इसे नाला नहीं, बल्कि 'नजफगढ़ लेक एस्केप' कहा करते थे। नजफगढ़ नाले में पानी बढ़ने और दूसरी ओर यमुना में उफान के हालात में गुरुग्राम के फारूखनगर, दौलताबाद में यमुना के 'बैकवॉटर' से बाढ़ के हालात बन जाते हैं, और यह पानी इलाके के खेतों में महीनों जमा रहता है। समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव बड़े शहरों को जकड़ेंगे ही और इसी जूझने के लिए प्रकृति की तरफ लौटना और कुदरत के प्रति अपनी गलतियों को सुधारना ही निदान होगा, न कि और निर्माण कर देना। हमारी चिंता बस कुछ घंटों का जाम तो खुल जाने तक है, लेकिन जन लें कि जिस जल को बांध कर यह जाम उपजाया जा रहा है, वह बेशकीमती है, और उसका मार्ग रोकने का अर्थ है सौभाग्य का रास्ता बाधित करना। यदि गुरुग्राम को बाढ़ और सूखाड़ दोनों से बचाना है तो नदी-नालों के पारंपरिक मार्गों को तलाश कर उन्हें उनके नैसर्गिक रूप में लौटाना अनिवार्य है।

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

से निकल कर कोटकासिम के रास्ते घासेड़ा के रास्ते बहरोड़, तिजारा, पटौदी, झज्जर के रास्ते नजफगढ़ झील तक आती थी यह नदी।

इस नदी का प्रवाह नये गुरुग्राम में घाटा, ग्वालपहाड़ी, बहरामपुर, मेराबास, नगली होते हुए बादशाहपुर तक था। कई जगह नदी का पाट एक एकड़ तक चौड़ा था। आश्चर्य है कि इस नदी का गुरुग्राम की सीमा में कोई राजस्व रिकॉर्ड ही नहीं रहा। दस साल पहले हरियाणा विकास प्राधिकरण यानी हुडा ने नदी के जल ग्रहण क्षेत्र को आर जोन में घोषित कर दिया। इससे पहले यहां नदी के 'रीवर बेड' की जमीन कुछ किसानों के नाम लिखी थी। आर जोन में आते ही पचास लाख प्रति एकड़ की जमीन विल्डरों की निगाह में आई और इसके दाम पंद्रह करोड़ एकड़ हो गईं। जहां नदी थी, वहां सेक्टर 58-65 की कालोनियां और बहुमंजिला आवास तन गए। अब बरसात तो पहले भी होती थी और उसका पानी इस नदी के प्रवाह के साथ नजफगढ़ के विशाल जल-क्षेत्र में समा जाता था। जब नदी के रास्ते में भवन बन गए तो पानी भवनों के करीब ही जमा होना लाजिमी है। थोड़ी सी बरसात में ही गुरुग्राम के पानी-पानी होने और और फिर साल भर बेपानी रहने का असल कारण केवल साबी नदी का लुप्त होना मात्र नहीं है, जमीन के लालच में कई नाले भी समाज गटक गया। डीएलएफ फेज तीन से सिकंदरपुर, सुचारली से पालम विहार और बादशाहपुर से खांडसा होते हुए नजफगढ़ वाला नाला या साबी नदी का हिस्सा भी गुम हो गया। तीनों की जल-ग्रहण क्षमता कई हजार घन मीटर जल की थी।

कहने की जरूरत नहीं कि यह सारा पानी कारखानों, सड़कों पर तो जमा होना ही है। दिल्ली-गुड़गांव अरावली पर्वतमाला के तले है और अभी सौ साल पहले तक इस पर्वतमाला पर गिरने वाली हर एक बूंद 'डाबर' में जमा होती थी। 'डाबर' यानी उत्तरी-पश्चिम दिल्ली का वह निचला इलाका जो पहाड़ों से घिरा था। इसमें कई अन्य झीलों और नदियों का पानी आकर भी जुड़ता था। इस झील का विस्तार एक हजार वर्ग किलोमीटर हुआ करता था जो आज गुड़गांव के सेक्टर 107, 108 से ले कर दिल्ली के नये हवाई अड्डे के पास पप्पनकलां तक था। इसमें कई प्राकृतिक नहरें और सरिता थीं, जो दिल्ली की जमीन, आबोहवा और गले को तर रखती थीं। आज दिल्ली के भूजल के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक बना नजफगढ़ नाला कभी जयपुर के जीतगढ़ से निकल कर अलवर, कोटपुतली, रेवाड़ी और रोहतक होते हुए नजफगढ़ झील और वहां से दिल्ली में यमुना से मिलने वाली साबी, साहिबी या रोहिणी नदी हुआ करती था। इस नदी के जरिए नजफगढ़ झील का अतिरिक्त पानी यमुना में मिल जाया करता था।

1912 के आसपास दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ आई और अंग्रेजी हुकूमत ने नजफगढ़ नाले को गहरा कर उससे पानी निकासी की जुगाड़ की। उस दौर में इसे नाला नहीं, बल्कि 'नजफगढ़ लेक एस्केप' कहा करते थे। नजफगढ़ नाले में पानी बढ़ने और दूसरी ओर यमुना में उफान के हालात में गुरुग्राम के फारूखनगर, दौलताबाद में यमुना के 'बैकवॉटर' से बाढ़ के हालात बन जाते हैं, और यह पानी इलाके के खेतों में महीनों जमा रहता है। समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव बड़े शहरों को जकड़ेंगे ही और इसी जूझने के लिए प्रकृति की तरफ लौटना और कुदरत के प्रति अपनी गलतियों को सुधारना ही निदान होगा, न कि और निर्माण कर देना। हमारी चिंता बस कुछ घंटों का जाम तो खुल जाने तक है, लेकिन जन लें कि जिस जल को बांध कर यह जाम उपजाया जा रहा है, वह बेशकीमती है, और उसका मार्ग रोकने का अर्थ है सौभाग्य का रास्ता बाधित करना। यदि गुरुग्राम को बाढ़ और सूखाड़ दोनों से बचाना है तो नदी-नालों के पारंपरिक मार्गों को तलाश कर उन्हें उनके नैसर्गिक रूप में लौटाना अनिवार्य है।

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

भारत में
मंकीपॉक्स
के फैलाव की आशंका कम

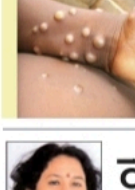

(फोटो : सोशल मीडिया)

- आईसीएमआर की एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में मंकीपॉक्स के फैलाव की संभावनाएं कम हैं, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है
- मंकीपॉक्स की शुरुआत अफ्रीकी देश कांगो से हुई थी। कोरोना महामारी की तरह यह संक्रमण विमान यात्रा और ट्रैवलिंग के दूसरे साधनों से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में फैल रहा है
- यह वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस फैमिली का मेंबर है, जो चेचक (स्मॉलपॉक्स) के लिए भी जिम्मेदार है। फिलहाल, भारत में मंकीपॉक्स की जांच के लिए 22 लेबोरेटरी हैं

भक्तगण को गाय और सुअर की चर्बी, फिश ऑयल से तैयार प्रसादम खिलाया गया। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आपराधिक कृत्य अक्षम्य है। किन शब्दों में गुस्सा जताएं। जो कोई भी भगवान तिरुपति के भक्तों की भावनाओं पर आघात करने का जिम्मेदार है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। माफी का कोई मतलब नहीं।

प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद, शिवसेना (उद्धव)
@priyankac19

व्यापकत्व की दिशा और संभावनाएं

विद्यालयी शिक्षा | प्रो. सरोज शर्मा

वैश्विकपूर्ण सामाजिक ताने-बाने में 'सभी के लिए शिक्षा' का स्वरूप व्यापक है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार स्कूली स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रति कटिबद्ध है। शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है, और इसके लिए अनेक रूपों में हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) इस दृष्टिकोण को परिपुष्ट करती है। इसके तहत 'सर्व शिक्षा अभियान' और 'समग्र शिक्षा' जैसे पहलुओं को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 3-18 वर्ष की आयु तक विस्तारित किया गया है।

शिक्षित नागरिक मजबूत लोकतंत्र की नींव होते हैं। इसलिए सभी बच्चों के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाना वास्तव में समय की मांग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करने और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के अनेक चिंतन बिंदु निर्दिष्ट किए गए हैं, जो निश्चित ही आगे के लिए पथप्रदर्शक बनेंगे। स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा में वापस लाने के लिए ब्रिज कोर्स और वोकेशनल ट्रेनिंग उपयोगी होंगे जिससे वे रोजगार योग्य कौशल हासिल कर सकते हैं। गौरतलब है कि अनेक शैक्षिक संस्थान इस मिशन को पूरा करने में निरंतर अग्रसर हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, जो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है, तथा अन्य स्टेट ओपन स्कूलों को इस दिशा में कार्य करना चाहिए। इस संस्थान में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के प्रवेश और अन्य प्रक्रियाओं के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल बनाया गया है। यह पोर्टल स्कूल न जाने वाले बच्चों को पंजीकृत करने, ट्रैक करने और प्रमाणित करने में मदद करता है। पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया राज्य शिक्षा विभाग के माध्यम से होती है। इस वेब पोर्टल पर राज्य शिक्षा विभाग के माध्यम से पंजीकृत प्रत्येक बच्चे को स्थायी आईडी दी जाती है, जो एनआईओएस से पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद भी शिक्षार्थी की पहचान करने में सहायक होती है। यह संस्थान प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में राज्य शिक्षा विभागों के साथ मिल कर व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है।

प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के स्कूल न जाने वाले बच्चों को स्कूली शिक्षा के अनेक स्तरों, जैसे-कक्षा 3, 5, 8,10 और 12 पर एनआईओएस में पंजीकृत करने का प्रयत्न किया जा रहा है। लचीलेपन से युक्त शैक्षिक कार्यक्रम में विद्यार्थी अपने समय-सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। इस संस्थान में शैक्षणिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था है। ये पाठ्यक्रम बच्चों को विभिन्न प्रकार के कौशल सिखाते हैं, जिससे वे रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उदाहरण के लिए सिलाई, बुनाई, कंप्यूटर ऑपरेशंस, इलेक्ट्रीशियन आदि पाठ्यक्रम शामिल हैं। दिव्यांग शिक्षार्थियों की शिक्षा भी चिंतनीय विषय है जिसके लिए एक मानक स्थापित करना जरूरी है। 'भारतीय सांकेतिक भाषा' को विषय के रूप में प्रसारित किया जाए और विभिन्न विषयों के वीडियो भारतीय सांकेतिक भाषा में तैयार किए जाएं।

डेजी प्रारूप में बोलती पुस्तकों का भी निर्माण किया जाए जो विशेष रूप से देखने में अक्षम, दृष्टिबाधित तथा डिस्लेक्सिया सहित 'प्रिंट डिसएबिलिटी' वाले शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी हों। हालांकि एनआईओएस और एनसीईआरटी जैसी संस्थाएं इस दिशा में कार्यरत हैं परंतु अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। भारतीय ज्ञान परंपरा को नये रूप में प्रस्तुत करने के लिए अनेक पाठ्यक्रमों का निर्माण जरूरी है। वैदिक शिक्षा, संस्कृत भाषा एवं साहित्य, भारतीय दर्शन तथा प्राचीन भारतीय ज्ञान के अन्य विभिन्न क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित विषयों के पठन-पाठन की व्यवस्था हो, जिसमें शिक्षार्थियों को माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक, दोनों स्तरों पर वेद अध्ययन, संस्कृत व्याकरण, भारतीय दर्शन तथा संस्कृत साहित्य जैसे विषय उपलब्ध कराए जाएं। देश के जांबाज सैनिकों को शिक्षा के लिए भी अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में अग्निवीरों को पढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं। ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षा के लिए विविध योजनाएं हैं। संतोष और उत्साह का विषय है कि बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भी मुक्त शिक्षा की लचीली व्यवस्था का लाभ उठाया है, और खेल में विशिष्टता प्राप्त करने के साथ-साथ स्कूली शिक्षा भी बेहतर ढंग से पूरी की है। ये खिलाड़ी अपनी सुविधानुसार अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। भविष्य में भी आशा है कि बहुत से खिलाड़ी और अन्य क्षेत्रों के लोग भी वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था का लाभ उठाएंगे और सभी तक शिक्षा पहुंचाने की संकल्पबद्धता को साकार करेंगे।

शांति | संत राजिन्दर

आज हम दुनिया में देखते हैं कि चारों ओर हिंसा और नफरत का माहौल है। एक देश दूसरे देश पर कब्जा करना चाहता है। इसी तरह सामाजिक तौर पर भी उच्च पद को पाने के लिए लोग एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी हम एक-दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में अपने अंदर नफरत और हिंसा की भावना पैदा कर लेते हैं।

ऐसे ही एक परिवार में भी सदस्य एक-दूसरे के विचारों से सहमत न होने के कारण आपस में लड़ते-झगड़ते रहते हैं। संतों-महापुरुषों की शिक्षा के अनुसार अगर हमें किसी को अपना बनाना है, तो प्रेम के गुण को अपने अंदर ढालना होगा। अब हमने देखना यह है कि हम अपने बच्चों और पोते-पोतियों को उपहार में क्या देना चाहते हैं? क्या उन्हें हिंसा और युद्ध की दुनिया में छोड़ना चाहते हैं? या हम उनके लिए शांति, प्रेम और एकता की दुनिया की कामना करते हैं? चुनाव हमें करना है। आज दुनिया में बच्चे काफी हिंसा से भरपूर माहौल देख रहे हैं, जिस करके उन्होंने अपने परिवार के अनेक सदस्यों को खो दिया है। समय आ गया है कि हम खुद पर एक सख्त नजर डालें। समय आ गया है कि 'हिंसा' को न कहने के लिए हम अपने अंदर परिपक्वता और बुद्धि का विकास करें। आइए, हम अपनी ऊर्जा का उपयोग एक शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण में करें। हर कोई दुनिया में शांति चाहता है। हम सब अपने महाद्वीपों, देशों, शहरों और अपने घर-परिवारों में शांति चाहते हैं। इन सबसे बढ़ कर हम अपने भीतर शांति चाहते हैं। फिर भी आज हम दुनिया भर में हो रहे अत्याचारों, हिंसा और अपराधों को देखते हैं। हमें देखना यह है कि विश्व में शांति की स्थापना के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस समस्या का हम एक समाधान निकाल सकते हैं, जिसे जानकर हमें आश्चर्य होगा कि हमने इसे क्यों अनदेखा कर दिया? एक शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण पहले नींव के पत्थर से शुरू होता है 'स्वयं' से। विश्व शांति की स्थापना में योगदान करने के लिए हमें पहले स्वयं शांति प्राप्त करनी चाहिए। आप पूछ सकते हैं: 'मैं अकेला व्यक्ति, व्यक्तिगत आंतरिक शांति प्राप्त करके विश्व शांति के लिए क्या योगदान दे सकता हूं?' ऐसा करके हम अपने द्वारा किए गए कार्यों से न सिर्फ पूरी मानवता, बल्कि अने वाली पीढ़ियों के लिए फर्क ला सकते हैं।

रीडर्स मेल

कश्मीरी पंडितों की हो घरवापसी

जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। अनुच्छेद 370 एवं 35 ए की समाप्ति के उपरांत जम्मू-कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव है। कुछ क्षेत्रीय दल आम जनता को अनुच्छेद 370 की वापसी का दिवास्वप्न दिखा रहे हैं। पहले चरण के मतदान में लगभग साठ फीसद मतदाताओं की उत्साहपूर्वक भागीदारी ने लोकतंत्र की जड़ को मजबूती प्रदान की है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। आतंकवाद की वजह से कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। सरकार को प्राथमिकता के आधार पर कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का अभियान चलाना चाहिए।

हिमांशु शेखर, गया

पेजर विस्फोट चिंताजनक

लेबनान में पेजर धमाकों और एक दिन बाद ही देश के कई हिस्सों में वॉकी-टॉकी, सोलर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लगातार धमाकों में कई निरीह लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। आंतक का यह एक नया और बीभत्स तरीका पहली बार सामने आया है, जिसमें विज्ञान और एआई तकनीक का इस्तेमाल करके आंतक फैलाया गया। भय पैदा हो गया है कि इस तकनीक का प्रयोग आगे कहीं मोबाइल, लेपटॉप, कंप्यूटर, एसी, स्मार्ट टीवी आदि से आंतकवादी गतिविधियों में न होने लगे। ऐसा हुआ तो दुनिया में शांति से जीना मुश्किल होगा, जिस विज्ञान और एआई तकनीक का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खुशहाली के लिए होना चाहिए, उसका इस तरह नरसंहार में उपयोग सोचनीय विषय है, सुदूर अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों पर बस्ती बसाने की कल्पना करने से पहले इसी धरती को आंतकरहित बनाने की कल्पना जरूरी है।

सोनू राज, ई-मेल से

आम सहमति जरूरी

एक साथ चुनाव या 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' खर्च कम करने और शासन में व्यवधान कम करने के लिए विचारणीय है। इससे प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा और मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी। हालांकि, इससे क्षेत्रीय स्वायत्तता और संघवाद के मुद्दे भी सामने आते हैं। क्या इसके परिणामस्वरूप सत्ता का एकीकरण होगा और राज्य सरकारें गिर जाएंगी? क्षेत्रीय दलों के हितों का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाएगा? चुनाव प्रणाली में इस बड़े बदलाव को लागू करने से पहले केंद्र को इन मुद्दों को संबोधित करना चाहिए और इच्छुक दलों के बीच सहमति को बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि विपक्षी पार्टियां इस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया को संघवाद पर चोट करार देते हुए इसकी आलोचना कर रही हैं। उनका कहना है कि मात्र वित्तीय कारण गिन कर 'एक देश, एक चुनाव' को लागू किया जाना लोकतंत्र के तकाजे पूरे करने वाला साबित नहीं हो सकता। फिर, लोक सभा चुनाव के जो मुद्दे होते हैं, वे विधानसभा के नहीं होते और निकाय चुनाव तो पूरी तरह नाली-खड़ंजों जैसे बेहद स्थानीय मुद्दों के आधार पर लड़े जाते हैं। ऐसे में एक साथ चुनाव कराते में राजनीतिक दलों की कवायद बढ़ जाएगी और उन्हें अपनी बात और मंतव्य मतदाता तक पहुंचाने में खासी परेशानी होगी।

अंशु भारती, बेगूसराय, बिहार

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काजरी द्वारा सहारा प्रिंटिंग यूनिट कम्युनिकेशन टावर, बी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा से मुद्रित तथा 705-706, सहारा हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
- समूह संपादक - श्री. विजय राय। स्थानीय संपादक - रविन्द्र सिंह*।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23362368, 23362369, 23362371, 23362372, फैक्स - 23362370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 38
आर.एन.आई. नं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त सामग्री के चयन एवं संपादन तथा कानूनी बाध्यताओं के लिए उत्तरदायी

चिंतन

तिरुमला तिरुपति लड्डू मामले की जांच जरूरी

आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति प्रसादम 'लड्डू' विवाद में दूध का दूध व पानी का पानी होना चाहिए। यह करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। प्रसादम 'लड्डू' बनाने में प्रयुक्त होने वाले घी में कथित मिलावट का मामला सामने आया है। आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी टीडीपी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम द्वारा उपलब्ध कराए गए घी के नमूनों में मिलावट की पुष्टि गुजरात स्थित नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा की गई है। टीडीपी ने कथित प्रयोगशाला रिपोर्ट दिखाई, जिसमें स्पष्ट रूप से नमूने में गोवंशीय पशुओं की चर्बी, सूअर की चर्बी और मछली के तेल की मौजूदगी की पुष्टि की गई है। नमूना प्राप्ति की तारीख 9 जुलाई थी व प्रयोगशाला रिपोर्ट 16 जुलाई की थी। इस दावे के बाद से समूचे मंदिर प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं, राजनीति तेज हो गई है। मंदिर को लड्डू की आपूर्ति पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसी के नेता की एजेंसियों से होती है। कुछ दिन पहले ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लड्डू बनाने में उपयुक्त घी में मिलावट का मुद्दा उठाया था। अब जब इस मामले ने शुक्रवार को तूल पकड़ा है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को सरकार से तिरुपति लड्डू मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले की भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से जांच कराने की बात कही है। एफएसएसएआई केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है। युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने कहा है कि मुख्यमंत्री नायडू राजनीतिक लाभ के लिए 'घृणित आरोप' लगा रहे हैं। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रसादम लड्डू की आपूर्ति करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ने सफाई दी है कि मंदिर निकाय को घी आपूर्ति करने वालों ने आंतरिक मिलावट की जांच सुविधा की कमी का फायदा उठाया। टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामल राव ने बताया कि प्रयोगशाला परीक्षणों में चयनित नमूनों में पशु चर्बी और लार्ड (सूअर की चर्बी) की मौजूदगी का पता चला है। श्यामल राव की नियुक्ति हाल ही में चंद्रबाबू सरकार ने की है। यहां सवाल है कि प्रसादम लड्डू बनाने में प्रयुक्त घी में अगर पशु चर्बी की मिलावट है, तो यह गंभीर चिंता की बात है। घी आपूर्तिकर्ता के मन में यह कतई भय व श्रद्धा नहीं है कि लड्डू का प्रयोग प्रसाद के लिए होगी। इस मामले की बारीकी से जांच होनी चाहिए। इस लड्डू को बनाने की परंपरा 300 वर्ष पुरानी है। ऐसे में आस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह विदित है कि भारत में अधिकांश खाद्य उत्पादों में मिलावट है। सरकारी नियामक के काम करने के बावजूद पैक्ड फूड की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। सभी कंपनियों के दूध, घी व अन्य डेयरी उत्पादों की जांच होनी चाहिए। सभी मंदिरों के प्रसाद की भी जांच होनी चाहिए। सरकार को मालूम है कि देश में दूध व घी के उत्पादन मांग के मुकाबले कम है, ऐसे में सिंथेटिक दूध, मिलावटी दूध व घी, मिलावटी डेयर उत्पादों की आपूर्ति की प्रवृत्ति बढ़ी है। मिलावटी व खराब खाद्य पदार्थ के चलते हर वर्ष करोड़ों लोग बीमार पड़ते हैं, अनेक की जान चली जाती है। मिलावटी खाद्य गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। तिरुमला तिरुपति लड्डू मामले की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और राजनीति के लिए वेंकटेश्वर मंदिर की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करना चाहिए।

डिजिटल सुविधा
प्रमोद भार्गव

जनगणना में स्व-गणना की सुविधा

जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते संभव नहीं हो पाई। अब इस ऑनलाइन गणना के साथ आगे बढ़ाने की पहल की जा रही है, जिससे भारतीय नागरिकों की गिनती जल्द हो सके। यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो संभव है 2031 की गणना पूरी तरह ऑनलाइन हो? इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑनलाइन प्रयोग अद्वितीय है। लेकिन जनता के स्थायी और गतिशील पंजीकरण के दृष्टिगत जरूरी है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जनगणना की जवाबदेही सौंप दी जाए। यह नवाचार जहां 10 साला जनगणना की बोझिल परंपरा से मुक्त होगा, वहीं देश के पास प्रतिमाह प्रत्येक पंचायत स्तर से जीवन और मृत्यु की गणना के सटीक व विश्वसनीय आंकड़े मिलते रहेंगे।

ई बाजार, ई-आवेदन, रेल व बस में आरक्षण ई-भुगतान के बाद अब ई-जनगणना की भी देश में शुभ शुरुआत होने जा रही है। इसमें जन्म और मृत्यु दोनों डिजिटल जनगणना से जुड़े होंगे। हर जन्म के बाद डिजिटल जनगणना खुद ही अद्यतन हो जाएगी और जब किसी की मृत्यु होगी तो उसका नाम खुद ही डाटा से डिलीट हो जाएगा। सेंसर रजिस्टर यानी जनगणना में बच्चे के जन्म, माता-पिता, जाति और जन्म स्थान की जानकारी समेत 31 प्रश्नों के उत्तर दर्ज हो जाएंगे। बालक जब 18 साल का होगा तो खुद ही उसका नाम चुनाव आयोग के पास चला जाएगा। नतीजतन उसका मतदाता पहचान पत्र बनने के साथ मतदाता सूची में भी नाम स्वमेव दर्ज हो जाएगा। इस तरह से जनगणना का डाटा हमेशा खुद अद्यतन होता रहेगा।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्र (एनपीआर) की प्रक्रिया पर करीब 12000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। डिजिटल जनगणना की घोषणा 1 फरवरी 2021 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। जनगणना-2021 में नागरिकों को गणना में शामिल होने की एक बेहतर और अनूठी ऑनलाइन सुविधा दी गई है। जनगणना (संशोधन)-2022 के अनुसार परंपरागत तरीके से तो जनगणना घर-घर जाकर सरकारी कर्मचारी करेंगे ही, लेकिन अब नागरिक स्व-गणना के माध्यम से भी अनुसूची प्राप्त भर सकता है। इसके लिए पूर्व नियमों में 'इलेक्ट्रॉनिक फार्म' शब्द जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत मीडिया, मैग्नेटिक, कंप्यूटर जनित माइक्रोचिप या इसी तरह के अन्य उपकरण में तैयार कर भेजी या संग्रहित की गई जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक फार्म में दी गई जानकारी माना जाएगा। यानी एनरायड मोबाइल से भी अपनी गिनती दर्ज की जा सकेगी। याद रहे यह जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते संभव नहीं हो पाई। अब इस ऑनलाइन गणना के साथ आगे बढ़ाने की पहल की जा रही है, जिससे भारतीय नागरिकों की गिनती जल्द हो सके। यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो संभव है 2031 की गणना पूरी तरह ऑनलाइन हो? इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑनलाइन प्रयोग अद्वितीय है। लेकिन देश की जनता के स्थायी और निरंतर गतिशील पंजीकरण के दृष्टिगत अब जरूरी है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जनगणना की जवाबदेही सौंप दी जाए।

गिनती के विकेंद्रीकरण का यह नवाचार जहां 10 साला जनगणना की बोझिल परंपरा से मुक्त होगा, वहीं देश के पास प्रतिमाह प्रत्येक पंचायत स्तर से जीवन और मृत्यु की गणना के सटीक व विश्वसनीय आंकड़े मिलते रहेंगे। जनगणना की यह तरकीब अपनाना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि तेज भागती यांत्रिक व कंप्यूटरीकृत जिंदगी में सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक बदलाव के लिए सर्वमान्य जनसंख्या के आकार व संरचना का दस साल तक इंतजार नहीं किया जा सकता? वैसे भी भारतीय समाज में जिस तेजी से लैंगिक, रोजगारमूलक और जीवन स्तर में परिवर्तन आ रहे हैं, उसकी बराबरी के प्रयासों के लिए भी जरूरी है कि हम जनगणना की परंपरा में आमूलचूल परिवर्तन लाएं? जनसंख्या के आकार, लिंग और उसकी आयु के अनुसार उसकी जटिल संरचना का कुछ ज्ञान न हो तो आमतौर पर अर्थव्यवस्था

के विकास की कालांतर में प्रगति, आमदनी में वृद्धि, खाद्य पदार्थों व पेयजल की उपलब्धता, आवास, परिवहन, संचार, रोजगार के संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा के पर्याप्त उपायों के इजाफे के पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में ही लोकसभा और विधानसभा सीटों को परिसीमन के जरिए बढ़ाया जाता है। जनगणना में निरंतरता इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि देश व दुनिया में जनसंख्या वृद्धि विस्फोटक बताई जा रही है। धरती पर जितनी तेजी से मानव समुदायों की आबादी उन्नीसवीं सदी में बढ़ी है, उतनी तेजी से बढ़ोतरी पहले कभी दर्ज नहीं हुई। जनसंख्या वृद्धि दर का आकलन करने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में प्रति वर्ष एक करोड़ 60 लाख आबादी बढ़ जाती है। इस दर के अनुसार हमें अपने देश की करीब एक अरब 40 करोड़ लोगों की एक निश्चित जनसंख्या प्राक्रय में गिनती करनी है, ताकि व्यक्तियों और संसाधनों के समतुल्य आर्थिक व रोजगारमूलक विकास का खाका खींचा जा सके।

जनसंख्या का यह आंकड़ा अज्ञात भविष्य के विकास की कसौटी पर खरा उतरे, उसका मूलाधार वैज्ञानिक तरीके से की गई सटीक जनगणना ही है। हरेक दस साल में की जाने वाली जनगणना में करीब 20 लाख कर्मचारी जुटते हैं। छह लाख ग्रामों, पांच हजार कस्बों, सैकड़ों नगरों और दर्जनों महानगरों के रहवासियों के द्वार-द्वार दस्तक देकर जनगणना का कार्य करना कर्मचारियों के लिए जटिल होता है। यह काम तब और बोझिल हो जाता है जब किसी कर्मचारी-दल को उसके स्थानीय दैनंदिन कार्य से दूर कर उसे दुरोचल गांव में भेज दिया जाता है। ऐसे हालात में गिनती की जल्दबाजी में वे मानव समूह छूट जाते हैं, जो आजीविका के लिए मूल निवास स्थल से पलायन कर जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि जनगणना की प्रक्रिया के वर्तमान स्वरूप को बदलकर एक ऐसे स्वरूप में लब्दील किया जाए, जिससे इसकी गिनती में निरंतरता बनी रहे। केवल गिनती की केन्द्रीयकृत जटिल पद्धति को विकेन्द्रीकृत करके सरल करना है।

गिनती की यह तरकीब ऊपर से शुरू न होकर नीचे से शुरू होगी। देश की सबसे छोटी राजनीतिक व प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है, हमें करना सिर्फ इतना है कि तीन प्रतियों में एक जनसंख्या पंजी पंचायत कार्यालय में रखनी है। इसी पंजी की प्रतिलिपि कंप्युटर में फीड जनसंख्या प्राक्रय पर भी दर्ज हो। परिवार को इकाई मानकर सरपंच, सचिव और पटवारी को यह जवाबदेही सौंपी जाए कि वे परिवार के प्रत्येक सदस्य का नामकरण व अन्य जानकारियां जनसंख्या प्राक्रय के अनुसार इन पंजियों में दर्ज करें। गांव में किसी भी शिशु के पैदा होने की जानकारी और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी तुरंत पूरे गांव में फैल जाती है, अतः इस जानकारी को अविलंब पंजी में दर्ज किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत पर एकत्रित होने वाली गन जानकारी प्रत्येक माह एक निश्चित तारीख को विकास खण्ड स्तर पर पहुंचाकर पंजी की एक प्रति विकासखण्ड कार्यालय में रखी जाए। सभी विकास खण्डों की यह जानकारी जिला स्तर पर बुलाई जाए और यहां इसका एकीकरण कर इस गिनती को कंप्युटर में फीड किया जाए। इस तरह सभी विकास खण्डों के आंकड़ों की गणना कर जिले की जनगणना प्रत्येक माह होती रहेगी। जिलावार गणना के डाटा को प्रदेश स्तर पर और प्रदेश जनसंख्या के आंकड़ों को देश की राजधानी में जनसंख्या कार्यालय में संग्रहीत कर प्रत्येक माह देश की जनगणना का वैज्ञानिक व प्रामाणिक आंकड़ा मिलता रहेगा। नगरों में वार्ड वार जनगणना के लिए गिनती की उपरोक्त प्रणाली ही अपनाई जाए। इस गिनती में जितनी पारदर्शिता और शुद्धता रहेगी, उतनी किसी अन्य पद्धति से संभव नहीं है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

विश्व शांति दिवस

डॉ. एस.डी. वैष्णव

वैश्विक शांति में प्रासंगिक है टॉलस्टॉय का साहित्य

विश्व में शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रों और लोगों के बीच अहिंसा, शांति और युद्ध विराम के आदर्शों को बढ़ावा देना ही विश्व शांति दिवस का ध्येय रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अहिंसा व संघर्ष विराम के माध्यम से शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए समर्पित दिन के रूप में घोषित किया है। आज वैश्विक शांति के सामने नस्लवाद, जनसंख्या, शरणार्थी संकट, अराजकता, महामारी, जलवायु संकट और राष्ट्रों की वर्चस्ववादी विस्तारवाद वाली नीतियां भी प्रमुख चुनौतियों के रूप में खड़ी हैं। अधिकांश देशों की साम्राज्य विस्तार की यही नीतियां युद्ध को जन्म देती हैं। बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के कारण देशों के बीच भरोसे दरक रहे हैं। इस कारण हर देश ने अपने विरोधी देश की ओर मिसाइलें तान रखी हैं और बॉर्डर पर लाखों सैनिक खड़े कर रखे हैं। मनुष्यता दांव पर लगी है, लेकिन इन लोगों के लिए मनुष्यता का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन यह भी सनद रहे कि कितना भी शक्तिशाली राष्ट्र या व्यक्ति क्यों न हो, युद्ध जीतकर भी एक दिन वह हार ही जाता है। युद्ध की विभीषिका ऐसी होती है कि हर सभ्य समाज युद्ध से किनारा करना चाहेगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकता है वह क्या है? युद्ध, हथियार? नहीं! वह है- शांति। लेकिन इसके विपरीत हम एक युद्ध की नींव पर दूसरे युद्ध की इमारत खड़ी कर रहे हैं।

विश्व में शांति स्थापित करने में विश्वभर के साहित्यकारों ने भी अपने-अपने तरीकों से योगदान दिया है। यूक्रेन- रूस और मिडिल-ईस्ट में हो रहे युद्धों से जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, निश्चित रूप से हमें विचलित करने वाली हैं। ऐसे समय में हमें याद आते हैं, उन्नीसवीं सदी के सर्वाधिक सम्मानित, रूस के चर्चित लेखक-

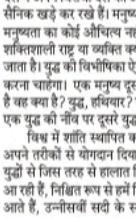

लियो टॉलस्टॉय। काश! साम्राज्य विस्तार की चाह रखने वाले शासकों ने टॉलस्टॉय को कभी ठीक से पढ़ा होता। रूस के यास्नाया पोलीना में एक संपन्न परिवार में जन्मे टॉलस्टॉय ने रूसी सेना में भर्ती होकर क्रीमियाई युद्ध में भाग लिया। युद्ध के पश्चात उन्होंने लाशों के जो ढेर देखे, उन्हें देखकर उनका मन विचलित हुआ और उन्होंने सेना की नौकरी ही छोड़ दी।

इस युद्ध के पश्चात टॉलस्टॉय ने साहित्य जगत को अपनी क्लासिक रचना 'वार एंड पीस' दी। लगभग डेढ़ सौ साल पहले लिखी इस रचना की प्रासंगिकता आज भी है। विचार के तल पर युद्ध की विभीषिकाओं के समानांतर मनुष्य सभ्यता के लिए शांति के महत्व को सामने लाना ही इस कृति का उद्देश्य रहा है। टॉलस्टॉय के इन्हीं विचारों के कारण गांधीजी भी उनकी ओर खिंचे चले गए। अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधीजी ने टॉलस्टॉय के साहित्य का विशद अध्ययन किया और मानवता की रक्षा के लिए उन्होंने अहिंसा को विरोध का शस्त्र बनाया। टॉलस्टॉय के जीवन के अंतिम दिनों में दोनों के मध्य पत्राचार भी हुआ। टॉलस्टॉय का मानना था कि युद्ध होना अच्छी बात नहीं है। मानव जीवन की सभ्यता इसी में है कि हमेशा विश्व में शांति बनी रहे। शांति ही तरक्की का द्योतक है। उनका यह भी मानना था कि अगर कभी युद्ध की स्थिति बन जाए, तो फिर परिणाम निर्णायक हो, अन्यथा युद्ध हो ही नहीं। युद्ध में कोई भी हारे या जीते, नुकसान तो मनुष्यता का ही होगा। बहरहाल, हमें उन बुनियादी सिद्धांतों के साथ, उस प्रेमवर्क में लौटने की आवश्यकता है, जिसकी नींव पर मनुष्यता और आने वाली पीढ़ी के सपनों को जिंदा रखा जा सके। आज जिस तरह से देशों के मध्य खून- खराबा हो रहा है और मनुष्यता बौनी नजर आ रही है, ऐसे में टॉलस्टॉय और उनकी रचनाएं बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं। 'वार एंड पीस' ही नहीं, बल्कि उनकी छोटी-छोटी कहानियां भी हमें भीतर तक झकझोरती हैं।

लियो टॉलस्टॉय एक ऐसे साहित्यकार थे जो धन-दौलत और संपन्न परिवार में पैदा होकर भी गरीब, असहाय लोगों के बीच रहकर दुनिया को अलविदा कह गए। उनके साहित्य की अनुगूंज ने विश्व साहित्य को नई ऊंचाइयां दीं। इधर अब आप भी उनके साहित्य से वाबस्ता हो लें। उन्हें पढ़ने की लगन ऐसी कि हाय! अब छोड़े ना छूटे।

(लेखक कवर्धा में शिक्षक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को देवता का दर्जा

संकलित
दर्शन

प्रदूषण की विनाशलीला को देखते हुए भारतीय ऋषियों ने कदम-कदम पर मानव को सजग किया है। चूंकि मनुष्य पंचमहाभूतों का समन्वय रूप है इसलिए सबसे पहले आध्यात्मिक महापुरुषों ने इसे जन्म से लेकर मृत्यु तक के अलग-अलग संस्कारों के साथ जोड़ दिया, ताकि मां के गर्भ में आने से लेकर सौ वर्ष तक वह अदैन्य भाव में जी सके। सबसे पहले भारतीय ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम् की जो परिकल्पना की, उसमें नख से लेकर शिख तक पूरा शरीर एक वसुधा (धरती) के समान है। शरीर के किसी भी हिस्से में तकलीफ है तो वह शरीर रूपी विश्व को प्रभावित करेगी। इसके अलावा मनुष्य के जीने के जितने भी स्नेत हैं, वे सभी कुटुंब के सदस्यों की तरह हैं। जिसे 'क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा' से समझा जा सकता है। शरीर का आंतरिक हिस्सा चूंकि अधम है इसलिए बाह्य प्रकृति से उत्तमोत्तम पदार्थ ग्रहण कर उसके स्वरूप को और अधिक विकृत होने से बचाया जाना नितांत जरूरी है। इसीलिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सबको देवता का दर्जा दिया गया। द्वापर युग के महानायक भगवान श्रीकृष्ण का पूरा जीवन ही प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष और जन जागरण का है। उम्र की परवाह न कर वह यमुना के प्रदूषित तत्व कालिया नाग का वध, प्रदूषित अग्नि लगाने वाले प्रलंबासुर का वध, अंतरिक्ष को शुद्ध करने के लिए व्योमासुर का वध, धरती की शुद्धता के लिए गो पालन करते हैं। त्रेता युग में रावण ने भी खर और दूषण नामक पर्यावरण-शत्रु तैनात किया था। श्रीराम ने इनसे धरती माता को मुक्त किया।

लक्ष्मी जी कहाँ निवास करतीं हैं

संकलित
प्रेरणा

एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकान्त स्थान पर गधे के रूप में छिपे हुए थे। देवराज इन्द्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूँढ रहे थे। एक दिन इन्द्र ने उन्हें खोज निकाला और उनके छिपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया। साथ ही उन्हें तत्वज्ञान का बोध कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूपात्मा स्त्री निकली। उसे देखकर इन्द्र ने पूछा: दैत्यराज! यह स्त्री कौन है? देवी, मानुषी अथवा आसुरी शक्ति में से कौन-सी शक्ति है? राजा बलि बोले: देवराज! ये देवी तीनों शक्तियों में से कोई नहीं हैं। आप स्वयं पूछ लें। इन्द्र के पूछने पर वे शक्ति बोलीं: देवेन्द्र! मुझे न तो दैत्यराज बलि जानते हैं और न ही तुम या कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं। जैसे- श्री, लक्ष्मी आदि। इन्द्र बोले: देवी! आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? लक्ष्मी जी बोलीं: देवेन्द्र! मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डिगा नहीं सकता है। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती-जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है मैं उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ। अर्थात मैं समयानुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास निवास करती हूँ। इन्द्र बोले: देवी! आप असुरों के यहाँ निवास क्यों नहीं करतीं? लक्ष्मी जी बोलीं: देवेन्द्र! मेरा निवास वहीं होता है जहाँ सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हों, व्रत और दान देने के कार्य होते हों।

अंतर्मन

आज की पाती

टैक्नोलॉजी न बने मानव जाति का काल

हाल ही में सेन्स. जो बि. लेबानन की राजधानी है, में एक हैरतअंगेज़ धमाह सामने आई है। खबर के अनुसार वहां पहले पेजर, जिसका प्रयोग टैक्सट मैसेज भेजने के लिए किया जाता है और इसके बाद वहीं वॉकी-टॉकी में अचानक धमाके हुए, इनमें कुछ लोगों की जान भी गई और कुछ घायल भी हुए। यह धमाके अलग शरारती तत्वों ने इन चीजों को हैक करके किए हैं, तो यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए क्योंकि ऐसे तो आने वाले समय में यह खतरनाक तत्व और भी टैक्नोलॉजी की चीजों का दुरुपयोग कर सकते हैं। यह सारी दुनिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। सारी दुनिया के देशों को इस पर काम करना चाहिए और सभी वैज्ञानिकों को कोई ऐसा तरीका खोजना चाहिए, ताकि टैक्नोलॉजी मानव जाति के लिए खतरा न बने। - मुकेश वाधवा, विशेषज्ञ

ट्रेंड

नक्सलवाद की क्रूरता

नक्सलवाद की एक ही विशेषता है विनाश और हिंसा। सुकमा सहरुद की आड़ में अपने लिए ही सोशल बटेरना नक्सलियों की रणनीति रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए के विकास इन लोगों के जरूरत नक्सलवाद की अमानवीयता और क्रूरता के जीवंत प्रतीक हैं। -अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

हैरिस को जिताएं

कमाला हैरिस ने अपना जीवन उन लोगों के लिए लड़ते हुए बिताया है जिन्हें एक आवाज और एक प्रेसीडेंट की जरूरत है। वह राष्ट्रपति बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, आइए उन्हें निर्वाचित होने में मदद करें। - बराक ओबामा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति

उत्कृष्ट साझेदारी

अफ्रिका और अहेना की उत्कृष्ट साझेदारी गेम-चेंजर रही है। दोनों के जादू की हमें जरूरत थी। उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से बारी को भारत के पक्ष में बार दिया है। एक असाधारण प्रदर्शन! -सुरेश रैना, क्रिकेटर

अंतरिक्ष अन्वेषण जरूरी

ये बहुत ही आश्चर्यजनक खबर है। अतिथि सिर्फ नई सीमा नहीं है, यह नई अर्थव्यवस्था है। भारत को आगे रहने के लिए अतिथि अन्वेषण अत्यंत आवश्यक है। -शेखर कपूर, फिल्म निर्माता

करंट अफेयर

गुरु नानक की पुण्यतिथि के लिए करतारपुर में जुटे श्रद्धालु

सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 485वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पूरी दुनिया से आए सिख श्रद्धालु पाकिस्तान के करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब में शुक्रवार को जमा हुए। बड़ी संख्या में स्थानीय और विदेशी सिख श्रद्धालु शुक्रवार से शुरू हो रहे तीन दिवसीय अनुष्ठानों में शामिल होने के लिए आए हैं। भारतीय श्रद्धालु करतारपुर गलियारे के माध्यम से अनुष्ठानों में शामिल होंगे। करतारपुर परियोजना प्रबंधन इकाई के उप सचिव सैफुल्लाह खोखर ने बताया कि करीब 500 सिख श्रद्धालु कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप सहित विभिन्न देशों से आए हैं। भारत से करीब 1500 श्रद्धालुओं के करतारपुर गलियारे के माध्यम से आने की उम्मीद है। खोखर ने बताया, बाबा गुरु नानक के पहले मुस्लिम अनुयायी भाई मरदाना की आदमकद प्रतिमा गुरुद्वारा दरबार साहिब के करीब स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया कि आने वाले सिख श्रद्धालुओं को गुरुनानक उद्यान में लगे खजूर और अन्य फलों से तैयार प्रसाद दिया जाएगा। तीन दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत 'आरंभ श्री अखंड पाठ साहिब' से होगी और शनिवार को 'नगर कीर्तन' का आयोजन किया जाएगा।

ऑफ बीट

दर्द क्यों थकाऊ होता है? यांत्रिक रूप से हमें रोकता है

ब्रिटेन में दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त लोगों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि दर्द और थकान, सक्रिय और सार्थक जीवन जीने में दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं। लेकिन लंबे समय तक दर्द इतना थका देने वाला क्यों होता है? इसका एक संकेत दर्द की प्रकृति और हमारे विचारों और व्यवहारों पर उसका शक्तिशाली प्रभाव है। अल्पकालिक पीड़ा आपको बचा सकती है, दर्द के बारे में सोचने के आधुनिक तरीके इसके सुरक्षात्मक प्रभाव पर जोर देते हैं। क्योंकि इस तरह से यह आपका ध्यान आकर्षित करता है और शरीर के किसी हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए आपको अपना व्यवहार बदलने के लिए मजबूर करता है। इसे आजमाएं। अपनी त्वचा पर चिकोटी काटिए। जैसे-जैसे आप दबाव बढ़ाएंगे, आप महसूस करेंगे कि जब तक कि एक समय ऐसा न आ जाए कि यह दर्दनाक हो जाए, भावनाएं बदलती हैं। यह दर्द ही है जो आपको ज्यादा दबाने से रोकता है, है न? इस तरह, दर्द हमारी रक्षा करता है। जब हम चोटिल होते हैं, ऊतक क्षति या सूजन के कारण हमारा पीड़ा तंत्र अधिक संवेदनशील हो जाता है। यह दर्द हमें क्षतिग्रस्त ऊतक को ठीक होने के दौरान यांत्रिक रूप से दबाव डालने से रोकता है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

287.4 लाख लीटर प्रतिदिन सीवरेज शोधन की क्षमता वाले 35 एसटीपी स्थापित हैं दिल्ली में 20 स्थानों पर, जबकि यहां प्रतिदिन लगभग 350 लाख लीटर सीवरेज निकलता है।

लालजी जायसवाल
लोकनीति विश्लेषक

आजकल

सबके हित में है एक साथ चुनाव

देश में लोकसभा से लेकर राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ करवाने की कवायद लंबे समय से की जा रही है। इसमें सुधार के उद्देश्य से मोदी सरकार ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी सप्ताह एक राष्ट्र-एक चुनाव पर इस समिति की संस्तुतियों को मंजूरी दे दी है। ऐसे में देश के सभी राजनीतिक दलों और संबंधित संस्थाओं को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए

भारत में निरंतर होने वाले चुनाव से अनेक प्रकार के नुकसान भी देखने में आ रहे हैं। ऐसे में एक साथ चुनाव कराने पर काफी समय से चर्चा चल रही है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र-एक चुनाव पर राम नाथ कोविन्द समिति की संस्तुतियों को मंजूरी दे दी है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को सौंप दी थी। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा की गई और सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी गई। इसका उद्देश्य लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव कराना है। फिलहाल अभी इसकी राह इतनी आसान नहीं दिख रही है। इसे लागू करने के लिए सरकार को एक नहीं, बल्कि दो-दो संविधान संशोधन विधेयकों को पास कराना होगा, जिसके तहत संविधान में कई बदलाव करने पड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले ही एक देश-एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट पेश की गई थी। हालांकि अब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिल गई है। इसे आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही, विभिन्न दल इस पर अपनी एकजुट राय पेश करेंगे।

लाभ : एक देश एक चुनाव के अनेक फायदे हैं, जो देश की प्रगति को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। देश में बार-बार चुनावों से खर्च होने वाली धनराशि बचेगी जिसका उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कार्यों में खर्च किया जा सकता है। एक साथ चुनाव से आर्थिक बोझ कम होगा, क्योंकि वर्ष 2009 लोकसभा चुनाव में 1,100 करोड़ रुपये और वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर यह चार हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वहीं सेंटर फार मीडिया स्टडीज (सीएमएस) की एक रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इसी प्रकार, राज्य विधानसभाओं के चुनाव में भी यही स्थिति नजर आती रही है। इसलिए पूरे देश में एकसाथ चुनाव कराने से चुनावी खर्च का आंकड़ा घटेगा। साथ ही बार-बार चुनाव के कारण आचार संहिताओं से राज्यों को दो चार होना पड़ता है, जिससे सभी प्रकार के विकास कार्य बाधित होते हैं। इससे शिक्षा क्षेत्र भी अत्यधिक दुष्प्रभावित होता है और अलग-अलग चुनाव से काले धन का अत्यधिक प्रवाह भी होता है। यदि एक साथ चुनाव होगा तो काले धन के प्रवाह पर निश्चित ही रोक लग सकेगी। साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने से आपसी सौहार्द बढ़ेगा, क्योंकि चुनाव में बार-बार जाति-धर्म के मुद्दे नहीं उठेंगे और आम आदमियों को भी तनाम परेशानियों से मुक्ति मिल सकेगी।

दो चरणों में चुनाव पर विचार : गौरतलब है कि सारे चुनाव एक साथ कराने के बजाय दो चरणों में कराने के फार्मूले पर काम करे, तो यह बहुत आसान हो जाएगा। अमेरिका में दो चरण में सारे चुनाव होते हैं। एक बार राष्ट्रपति का चुनाव होता है और फिर मध्यावधि चुनाव होते हैं। इस फार्मूले पर भारत में लोकसभा के साथ आधे राज्यों के चुनाव हो सकते हैं और उसके बाद दूसरे चरण में आधे राज्यों के चुनाव करवाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के साथ या उससे छह महीने आगे पीछे अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव से एक साल पहले कर्नाटक विधानसभा का और लगभग नौ महीने बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है। इन चुनावों को लोकसभा के साथ वाले चरण में लाया जा सकता है। इसका एक फायदा यह भी है कि अगर किसी कारण से राज्यों में सरकार गिरती है तो दोबारा चुनाव के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। जो नजदीकी चरण होगा, उसमें उसका चुनाव हो जाएगा।

लेकिन एक साथ चुनाव में बड़ी समस्या है। इसमें विधानसभा के बीच में भंग नहीं होने का कानून भी बनाना होगा। अगर ऐसा कानून नहीं बनता है तो विधानसभाओं का कार्यकाल छोटा होगा या जोड़-तोड़ की सरकार बनेगी या राज्यों को राष्ट्रपति शासन में रहना पड़ेगा। इसलिए सरकार को सहमति और तार्किक पद्धति की ओर बढ़ना चाहिए और सभी दलों से मिलकर सहमति बनाकर किसी भी निर्णय पर पहुंचना चाहिए।

चुनौतियां : एक चुनाव देश के हित में विकास को परिलक्षित करता है। लेकिन इससे कुछ समस्याओं का सामना भी करना होगा। एक चुनाव से क्षेत्रीय पार्टियों पर संकट आ सकता है और उनके क्षेत्रीय संसाधन सीमित हो सकते हैं। क्षेत्रीय मुद्दे भी खत्म हो सकते हैं और चुनाव परिणाम में देरी भी हो सकती है। साथ ही, अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता होगी। अतः इनकी भारी संख्या में नियुक्ति की जरूरत पड़ेगी। एकसाथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम की पर्याप्त आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान में 12 से 15 लाख ईवीएम का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब एक चुनाव होंगे तो उसके लिए लगभग 30 लाख ईवीएम की आवश्यकता होगी। इसके सथ वीवीपैट भी लगाने होंगे। इन सब को पूरा करने के लिए चार से पांच हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। निश्चित ही पूंजीगत खर्च बढ़ेगा, लेकिन वहीं एक साथ चुनाव से से सार्वजनिक धन की बचत भी होगी। दूसरी ओर प्रशासनिक सेटअप और सुरक्षा बलों पर भार भी कम होगा तथा सरकार की नीतियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा और यह भी सुनिश्चित होगा कि प्रशासनिक मशीनरी चुनावी गतिविधियों में संलग्न रहने के बजाय विकासात्मक गतिविधियों में लगी रहे।

सभी स्तरों के चुनाव एक साथ करवाने के अनेक लाभ हैं, परंतु इसकी राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। फाइल

दूर होंगी नीतिगत निर्णय लेने की अड़चनें

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

अनेक असमानताओं, विसंगतियों और विरोधाभासों के बावजूद भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र से बंधा है। निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्र को एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था देती है, जिससे भिन्न स्वभाव वाली राजनीतिक शक्तियों को केंद्रीय एवं प्रांतीय सत्ताओं में भागीदारी का अवसर मिलता है। परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक प्रक्रिया गतिशील रहती है, जो देश की अखंडता एवं संप्रभुता के प्रति जवाबदेह है। देश में मानव संसाधन सबसे बड़ी पूंजी है। लिहाजा यदि बार-बार चुनाव की स्थितियां बनती हैं तो मनुष्य का ध्यान बंटता है और समय एवं पूंजी का क्षरण होता है। इस दौरान आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण प्रशासनिक शिथिलता दो-ढाई महीने तक बनी रहती है, फलतः विकास कार्य और जन-कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होती हैं।

एक साथ चुनाव के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि देश प्रत्येक छह माह बाद चुनावी मूड में आ जाता है। ऐसे में सरकारों को नीतिगत फैसले लेने में तो अड़चनें आती हैं, दूसरे नीतियों को कानूनी रूप देने में अतिरिक्त विलंब भी होता है। यह तर्क अपनी जगह जायज है। वैसे भी राजनीतिक दलों की महत्ता तभी है, जब वे नीतिगत निर्णयों को अधिकतम लोकतांत्रिक बनाने के लिए अपने सुझाव दें एवं उन्हें विधेयक के प्रारूप का हिस्सा बनाने के लिए नैतिक दबाव बनाएं। ऐसा नहीं है कि एक साथ चुनाव का विचार कोई नया विचार है। वर्ष 1952 से लेकर 1967 तक चार बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव पूरे देश में एक साथ ही हुए। इंदिरा गांधी का केंद्रीय सत्ता पर वर्चस्व कायम होने के बाद राजनीतिक विद्वेष व बेजा हस्तक्षेप के चलते इस व्यवस्था में बदलाव आना शुरू हो गया। इंदिरा गांधी को राज्यों में विपक्ष की जो सरकार पसंद नहीं आती थी, उसे वह कोई न कोई बहाना ढूंढकर राष्ट्रपति से बर्खास्त करवा देती थीं। इससे मध्यावधि चुनावों की परिपाटी पड़ती चली गई।

चूंकि संविधान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का उल्लेख तो है, लेकिन दोनों चुनाव एक साथ कराने का हवाला नहीं है। संविधान में इन चुनावों का निश्चित जीवनकाल भी नहीं है। वैसे यह कार्यकाल पांच वर्ष के लिए होता है, लेकिन बीच में सरकार के अल्पमत में आ जाने के कारण या किसी अन्य कारण के चलते सरकार गिर या गिराई जा सकती है। केंद्रीय विधि आयोग ने 2018 में केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया था कि पांच साल के भीतर यदि सरकार के भंग होने की स्थिति बने तो 'रचनात्मक अविश्वास' मत हासिल किया जाए। मसलन, किसी सरकार को लोकसभा या विधानसभा के सदस्य अविश्वास मत से गिरा सकते हैं, तो इसके विकल्प में जिस दल या गठबंधन पर विश्वास हो या जिसे विश्वास मत हासिल हो जाए, उसे बतौर नई सरकार की शपथ दिला दी जाए। कुछ विपक्षी दल एक साथ चुनाव के पक्ष में शायद इसलिए नहीं हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि ऐसा होने पर जिस दल ने अपने पक्ष में माहौल बना लिया तो केंद्र व ज्यादातर राज्य सरकारें उसी दल की होंगी?

बार-बार चुनाव की स्थितियां निर्मित होने के कारण सत्ताधारी राजनीतिक दल को यह भय बना रहता है कि उसका कोई नीतिगत फैसला ऐसा न हो जाए कि दल के समर्थक मतदाता नाराज हो जाएं। लिहाजा सरकारों को अनेक प्रकार के लोकलुभावन फैसले भी लेने पड़ते हैं। वर्तमान में अमेरिका सहित अनेक ऐसे देश हैं, जहां एकसाथ चुनाव बिना किसी बाधा के संपन्न होते हैं। गोया, भारत में भी यदि एकसाथ चुनाव की प्रक्रिया यदि वर्ष 2029 से होती है तो केंद्र और राज्य सरकारें बिना किसी दबाव के देश व लोकहित में फैसले ले सकेंगी। सरकारों को पूरे पांच साल विकास और सुशासन को सुचारु रूप से लागू करने का अवसर मिलेगा।

खरी-खरी

देश को बाबा मिलने का प्रबल योग

रेखा शाह आरबी

चतुरी जी को जब-जब अपने बेरोजगार होने का आभास होता है, तो उनका झुकाव ईश्वर की तरफ होने लगता है। इस दुनिया में मन की शांति ही सबसे बड़ी चीज है। जवानी में चतुरी जी को बहुत अफसोस था कि भगवान ने कैसा मां-बाप दिया है। परंतु समय के सथ सबको जवाब मिल जाता है। चतुरी जी को सारे सवालों का जवाब अब उन्हें अपने बच्चों के द्वारा मिल रहा है। सबसे मजे की बात यह है कि उनके मां-बाप भी निकम्मे थे और वह भी अपने बच्चों के निकम्मे मां-बाप हैं।

अखिरकार करें तो क्या करें कि रोजी रोजगार में लगें। एक बड़ा पाव का ठेला डालने में भी 50 हजार से कम का खर्च नहीं है। चतुरी जी के लिए यह बहुत बड़ी रकम है। ऐसे में वह टीवी पर म्यूजिक चैनल के बजाय भक्ति चैनल सुन कर ही सुकून मिलता है। लोभ-मोह-धन-संपत्ति सब मोह माया है। सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। भले ही यह सुनाने वाला खुद लग्जरी कारों में चलता है। हवाई जहाज में सफर करता है और आलीशान भवन में रहता है।

लेकिन कहा जाता है न कि किसी भी चीज को बहुत ध्यान से देखिए सुनिए, तो उसकी बारीकियां समझ में आती हैं। ऐसे ही चतुरी जी भक्ति चैनलों को देखते-देखते आधे बाबा तो बन ही चुके थे। अभी पूरे नहीं बने थे, इसलिए मोह माया बाकी था। उनके मन में विचार आया, सबसे अच्छा काम बाबा बनना ही है।

तब जाकर चतुरी जी को समझ में आया कि देश में बाबाओं की संख्या क्यों बढ़ रही है। क्यों बाबाओं की बाढ़ आई हुई है। अब यही एक धंधा ऐसा रह गया है जो किसी भी सीजन में मंदा नहीं चल रहा है। वरना और सारे धंधे में तो टैक्स भर भर के व्यापारियों के प्राण के पलीते लग रहे हैं। अब चतुरी जी ने पूरी तैयारी के साथ मन बना लिया है। अब वह बाबा बनेंगे, उन्हें बाबा बनने में ही अपना और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल नजर आ रहा था। पूरी संभावना है कि देश को एक नया नवेला बाबा फिर मिल जाएगा। ऐसा प्रबल योग दिखाई दे रहा है। जो लोगों को मोह माया से मुक्ति के ओर ले जाने में मदद करेगा।

पोस्ट

हाई स्पीड वाली सड़कों पर उलटी दिशा में आने वाली गाड़ियों को जरूर कर लेना चाहिए और उनका लाइसेंस हमेशा के लिए रद हो। ऐसी सख्ती नहीं होगी तो फिर लोगों की जान जाती रहेगी।
उमाशंकर सिंह@umashankarsingh

दिलजीत दोसांझ के शो की टिकटें घंटों में बिक जाती हैं। आइफोन के लिए लोग भीड़ में लाइन लगाए खड़े हैं। घाटे में चल रही कंपनियां आइपीओ लाकर कई गुना रकम पा चुकी हैं। गांव में सड़क किनारे की जमीन का रेट शहर के रेट की बराबरी करने को बेताब है। पता नहीं देश का हैपीनेस इंडेक्स नापने वाले कहां घूम रहे हैं। अतुल कुमार राय@AuthorAtul

तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट अत्यंत ही राक्षसी कृत्य है। इसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। करोड़ों भक्तों की श्रद्धा को पशुओं की चर्बी और तेल मिलाकर नष्ट-भ्रष्ट कर दिया पापियों ने। आस्था कौशिक@ASTHAKAUSHIIK

तिरुपति प्रसाद प्रकरण यह रेखांकित करता है कि लोगों को राजनीतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विभाजनों से ऊपर उठकर हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए मुहिम चलानी चाहिए।
तहसीन पूनावाला@tehseenp

जागरण जनमत कल का परिणाम

जम्मू-कश्मीर का मतदान प्रतिशत वहां कानून व्यवस्था में सुधार का परिणाम है?

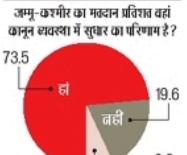

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या तिरुपति मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट सर्वरण के पाठकों का मत है।

जनपथ

इजरायलने दे दिया इतना तगड़ा डोज,
दहशतमें दुनिया जिये दिनो रात हर रोज।
दिनो रात हर रोज कहीं कब क्या फट जए,
काल बनी तकनीक आज भगवान बचाए!
गुफ्तुगू बटन दबाय कियेहज्जारो घायल,
अरे बाप रे बाप बढ़ा बेढब इजरायल!!
- ओमप्रकाश तिवारी

अरुण अशेष
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बिहार

बिहार डायरी

हंस और गुलाब से सबक लेने की जरूरत

बिहार में इस समय कई इलाकों में बाढ़ है। वहीं दूसरी ओर, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव का नाम भी नौकरी के बदले जमीन मामले से जुड़ गया है। लेकिन, इन दोनों की चर्चा नहीं है। चर्चा में हैं हंस और गुलाब। इसलिए कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोनों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पकड़ में आ गए हैं। संजीव हंस भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। गुलाब यादव राजद के पूर्व विधायक हैं। बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने झंझारपुर से चुनाव लड़ा था। पहले विकासशील इंसान पार्टी से टिकट लेना चाहते थे। बातचीत पक्की हो गई थी। शगुन भी दे दिया गया था। परंतु बीच में दूसरे आकर टिकट झपट ले गए। वहां से निराश हुए तो बहुजन समाज पार्टी ने टिकट थमा दिया। गुलाब की पत्नी अंबिका गुलाब यादव मधुबनी स्थानीय क्षेत्र प्राधिकार से विधान परिषद की सदस्य हैं। पुत्री बिंदू गुलाब यादव मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। यह सब विवरण देखने से लगता है कि गुलाब यादव की राजनीति में गहरी पकड़ है। इसलिए उन्हें और स्वजनों को इस क्षेत्र में सफलता मिल रही है। गुलाब ने कभी किसी राजनीतिक दल से अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की। उन्हें अपने धन पर भरोसा था। यह भरोसा लोकसभा चुनाव में बसपा का टिकट मिलने तक कायम रहा। अब टूटा दे रहा है। संजीव हंस और गुलाब यादव की दौरती थी चर्चा में हैं।

दरअसल ईडी की प्रारंभिक जांच में दोनों के पास अकूत संपत्ति मिली है। पटना, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, और हिमाचल प्रदेश में जमीन-मकान मिले हैं। छापे के दौरान 87 लाख की नकदी मिली। संजीव हंस बिहार में जिलाधिकारी और कई विभागों के सचिव रहे हैं। उनकी असली कमाई बिजली कंपनी के सर्वेसर्वा रहने के दौरान हुई। ईडी के अनुसार स्मार्ट मीटर आपूर्ति करने वाली एक कंपनी ने हंस को उपहार में मर्सीडीज कार दी थी। प्रायः सभी निकटस्थ संबंधियों के नाम से उन्होंने चल-अचल संपत्ति अर्जित की है। अभी इन दोनों की कुल संपत्ति का आकलन होना शेष है। यदि संपत्ति का आंकड़ा हजार करोड़ पार करता है तो यह कुख्यात पशुपालन घोटाले के समकक्ष पहुंच जाएगा। पशुपालन घोटाला मामला अभी तक चल रहा है। इसी ने बिहार के सबसे बड़े कद वाले राजनेता लालू प्रसाद की संसदीय राजनीति को तबाह कर दिया। संजीव हंस और गुलाब यादव की अंतिम परिणति क्या होगी, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। प्रश्न यह है कि क्या संजीव हंस ने इतनी बड़ी संपत्ति एक दिन में जुटा ली? ऐसा नहीं है। वह जिस किसी विभाग में रहे, चर्चा में रहे। इन्हें धन लेने और देने में कभी संकोच नहीं हुआ। इसलिए किसी सक्षम व्यक्ति को हंस या गुलाब से लेनदेन को लेकर कभी अप्रसन्नता नहीं हुई।

नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति पर अमल करते हैं। उनकी स्पष्ट घोषणा है कि हम किसी को फंसाएंगे नहीं। अगर आप अपने कर्मों से कहीं फंस गए तो बचाएंगे भी नहीं। इस मामले में भी उन्होंने यही किया। ईडी के छापे में कुछ ठोस साक्ष्य के जाहिर होते ही संजीव हंस को बिजली कंपनी के महत्वपूर्ण अध्यक्ष पद से हटाकर सचिवालय में रख दिया गया। ईडी के साथ राज्य सरकार की एजेंसी स्पेशल विजिलेंस यूनिट भी इस मामले की जांच कर रही है। संजीव हंस को प्रश्रय देने वाले और उन्हीं की तरह अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले कुछ अधिकारी दिल मजबूत कर रहे हैं। राज्य में बहुत पहले से अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों का कारोबारी मेल बना हुआ है। अधिकारी उल्टे-पुल्टे तरीके से कमाई तो कर लेते हैं, मगर उनके पास लाभकारी माध्यम में निवेश का आइडिया नहीं रहता है। इसके लिए वे जन प्रतिनिधियों का सहारा लेते हैं। यह संयोग है कि हंस और गुलाब की जोड़ी प्रारंभिक पड़ताल में पकड़ में आ गई है, ऐसी कई जोड़ियां आज भी आबाद हैं। ठेका, निर्माण, बड़ी कंपनियों की एजेंसियों की नजर भले ही इन पर देर से पड़े, परंतु राहगीरों को भी पता है कि किस माल में किस अधिकारी और किस जन प्रतिनिधि का धन लगा है। वैसे, केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार रहने के बावजूद भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी बड़े अधिकारी पर ईडी की यह कार्रवाई संजीव हंस की तरह कमाई करने वाले दूसरे अधिकारियों को जरूरत से अधिक धन कमाने की निरर्थकता के बारे में तो बता ही रही है।

संजीव हंस। फाइल

गुलाब यादव। फाइल

मंथन

पुनर्जीवन की आस में यमुना

यमुना केवल एक नदी नहीं है, अपितु वह जीवन का स्रोत और संस्कृति है। प्रदूषित हो चुकी इस नदी को सरकार व समाज की सहभागिता से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाना चाहिए

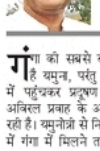

ब्र. वेदाकाश
सहायक प्रोफेसर, किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विवि

गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, परंतु आज यह दिल्ली में पहुंचकर प्रदूषण के कारण और अविरल प्रवाह के अभाव में दम तोड़ रही है। यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज में गंगा में मिलने तक की यमुना की यात्रा लगभग 1400 किलोमीटर है। दिल्ली में पल्ला से ओखला बैराज तक यमुना का बहाव क्षेत्र लगभग 50 किमी है। आंकड़ों के अनुसार यह यमुना के कुल बहाव क्षेत्र का लगभग दो प्रतिशत है, जबकि कुल प्रदूषण में 76 प्रतिशत भागीदारी दिल्ली क्षेत्र की है। दिल्ली में अनेक छोटे-बड़े कई नाले यमुना में गिरते हैं। परिणामतः यमुना बुरी तरह प्रदूषित हो रही है। सामान्यतः मानसून के दिनों में बाढ़ का पानी आने से प्राकृतिक रूप से यमुना की सफाई हो जाती थी, लेकिन विगत कुछ वर्षों से बाढ़ के बाद भी प्रदूषित यमुना की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की विगत रिपोर्ट यह बताती है कि यमुना में ज्यादातर जगह पानी में घुलित आक्सीजन नहीं है। बायोलाजिकल आक्सीजन डिमांड का स्तर भी बढ़ा हुआ है। यमुना के जल में फास्फेट की जांच से यह पता चला है कि हर जगह इसकी मौजूदगी है। यमुना क्षेत्र में उगाई जा रही सब्जियों में भी स्वास्थ्य के लिए घातक रसायन मिल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में जींस की रंगाई एवं घातक रंग-रसायनों की अनेक अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनका घातक पानी नालों के माध्यम से यमुना में पहुंचता है। यमुना में बैराज क्षेत्र के आसपास लगभग पूरे साल झाग की स्थिति बनी रहती है। विडंबना यह भी है कि बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग के पास यमुना से कब व कितनी गाद निकाली गई, कितना खर्च हुआ आदि बातों की जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। दिल्ली सरकार उपराज्यपाल पर आरोप लगाती है तो कभी पर्याप्त फंड न मिलने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेती है। विगत वर्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि यमुना की सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर दिल्ली में आपातकाल जैसी स्थिति है, क्या यह टिप्पणी चिंताजनक नहीं है? आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 20 स्थानों पर कुल 287.4 लाख लीटर प्रतिदिन सीवरेज शोधन की क्षमता वाले 35 एसटीपी स्थापित हैं, जबकि यहां प्रतिदिन लगभग 350 लाख लीटर सीवरेज निकलता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यमुना को प्रदूषण मुक्त करने का मुद्दा भ्रष्टाचार का भी शिकार है। विगत दिनों में सीवरेज शोधन प्लांट के ठेकों की प्रक्रिया, नालों की सफाई में फर्जी बिलिंग, कार्य मापन में गड़बड़ी आदि के आरोप भी सामने आए हैं। क्या इस प्रकार की कार्यप्रणाली से यमुना प्रदूषण मुक्त हो सकेगी? क्या इस प्रकार के कार्यों में लिप्त लोग यमुना के हत्यारे नहीं हैं? यमुना के प्रदूषण और अविरल प्रवाह में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि यमुना बाढ़ क्षेत्र से अनधिकृत निर्माण हटाया जाए और भविष्य में अतिक्रमण न हो, इससे बचने के लिए नदी के बाढ़ क्षेत्र के चारों ओर बाड़ लगाई जाए।

आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि दुनिया की एक चौथाई आबादी पानी की कमी से जूझ रही है। पानी की कमी से जूझ रहे 17 देशों की सूची में भारत 13वें स्थान पर है। क्या ये आंकड़े भविष्य में जल संकट की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं? हमें समझना होगा कि नदियां जीवनदायिनी हैं। नदियों द्वारा सीधे अथवा उनके द्वारा ट्यूबवेल और नहरों आदि से बड़े पैमाने पर सिंचाई होती है। औद्योगिक आदि पर समय-समय पर समीक्षा कर रही है। यमुना को पुनर्जीवित करने के लिए उसमें गिर रहे नालों, अशोधित सीवरेज आदि को रोका जाए। तहिरीकुंड बैराज से लगातार पर्याप्त जल छोड़ा जाए। यमुना को प्रदूषण मुक्त, अविरल और पुनर्जीवित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शासन-प्रशासन, स्थानीय निकाय और जनप्रतिनिधियों में समुचित समन्वय हो, समग्रता में योजनाएं बनें और लागू हों। निकायों की जिम्मेदारी तय की जाए और उल्लंघन पर दंडात्मक प्रविधान हों। यमुना तो मां है, यह केवल एक नदी के पुनर्जीवन की आस नहीं है, अपितु मां और मानवता के पुनर्जीवन की आस है।

एकीकृत प्रयासों से ही यमुना नदी के जल को निर्मल बनाना संभव होगा। फाइल

कल्पमेधा

मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ देन उसके श्रेष्ठ विचार हैं, जो हजारों वर्षों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करते रहते हैं।

- सैमुअल स्माइल्स

आरोप निराधार

खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप में एक अमेरिकी अदालत के भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रा प्रमुख के खिलाफ, जारी अदालती फरमान को लेकर स्वाभाविक ही चर्चा तेज हो गई है। यह चर्चा ऐसे समय में शुरू हो गई है, जब अगले हफ्ते प्रधानमंत्री क्वाड बैठक में हिस्सा लेने अमेरिका जाने वाले हैं। पन्नू की हत्या की साजिश का पर्दाफाश खुद अमेरिकी सुरक्षा एजंसी ने किया था। उसने एक भारतीय व्यवसायी को गिरफ्तार किया था, जिसने कबूल किया कि एक बड़े भारतीय अधिकारी के कहने पर उसने पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। इसे लेकर वहां के अखबारों में भी खूब चर्चा रही। उसी आधार पर पन्नू ने अमेरिका की एक जिला अदालत में मुकदमा दायर किया, जिसके आधार पर यह अदालती फरमान जारी हुआ है। हालांकि भारत सरकार ने पन्नू के मुकदमे को निराधार बताया है। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय खुफिया एजंसी का हाथ बताया था। उस संबंध में भारत सरकार लगातार कनाडा सरकार से सबूत मांगती रही, मगर वह दे पाने में अक्षम ही साबित हुई।

कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिकी अदालत के फरमान के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कुछ खटास पैदा हो सकती है, मगर इसका कोई आधार नहीं है। अदालतों की अपनी एक प्रक्रिया होती है और अमेरिकी जिला अदालत ने उसका पालन किया है। इससे अमेरिका और भारत के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। छिपी बात नहीं है कि पन्नू को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। वह प्रकट रूप से खालिस्तान समर्थकों को उकसाता और मदद मुहैया कराता रहता है। वह अमेरिका और कनाडा दोनों देशों का नागरिक है। भारत सरकार उसके खिलाफ शिकंजा कसने की मांग करती रही है, मगर कनाडा सरकार ने कभी उस पर गंभीरता नहीं दिखाई। जब एक संदिग्ध भारतीय नागरिक को अमेरिकी खुफिया एजंसी ने गिरफ्तार किया और उससे पता चला कि पन्नू की हत्या की साजिश रची गई है, तो पन्नू को खालिस्तान समर्थकों को भारत सरकार के खिलाफ भड़काने और उनकी सहानुभूति हासिल करने का मौका मिल गया। जाहिर है, इस बहाने वह अपने पक्ष में सहानुभूति लहर बनाने और यह साबित करने का प्रयास कर रहा है कि भारत सरकार खालिस्तान समर्थकों के विरुद्ध साजिशें रच रही है।

कोई भी देश और वहां की अदालत किसी भी आतंकी गतिविधि में शामिल व्यक्ति के किसी दूसरी सरकार के विरुद्ध अनर्गल आरोप को प्रोत्साहित नहीं कर सकती। चूंकि अमेरिकी अदालत के सामने पन्नू के आरोपों के पीछे कुछ आधार हो सकते हैं, इसलिए अदालत ने यह फरमान जारी कर दिया। मगर इसका यह अर्थ कतई नहीं कि इससे पन्नू का पक्ष मजबूत हो गया। केवल किसी आरोपी के कबूलनामे के आधार पर कोई मामला सच साबित नहीं हो जाता। ऐसे मामलों में उच्चस्तरीय जांचें महत्त्वपूर्ण होती हैं। जब अमेरिकी खुफिया और सुरक्षा एजंसियां इस मामले में कोई कदम नहीं उठा रहीं, तो पन्नू के आरोप का बहुत कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के समय भी निश्चय ही इस मसले पर वहां के राष्ट्रपति के साथ चर्चा होगी। यह बात गहराई से रेखांकित होनी चाहिए कि आतंकी गतिविधियों में संलिप्त और अमेरिका तथा कनाडा जैसी जगहों पर पनाह पाए पन्नू जैसे लोगों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है।

दुराग्रह का कठघरा

अदालतों में व्यक्त न्यायाधीशों के विचारों और बयानों को आम लोग फैसले की कड़ी के रूप में देखते हैं। उसके आधार पर किसी मसले पर सही और गलत के बारे में राय बनाते हैं। मगर कई बार कुछ न्यायाधीशों के मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं, जो न केवल उनके पद की गरिमा के विरुद्ध होती, बल्कि उनसे समाज में नाहक अनुचित प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की ऐसी ही टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट को सख्त रुख अख्तियार करना पड़ा। गौरतलब है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक महिला वकील की गरिमा को भंग करने वाली आपत्तिजनक टिप्पणी की और बंगलुरु के एक मुसलिम बहुल इलाके को 'पाकिस्तान' कह कर संबोधित किया। हैरानी की बात है कि ऐसी टिप्पणियां करते हुए उन्हें यह याद तक न रहा कि वे न्यायाधीश के सम्मानित पद का निर्वाह कर रहे हैं। हालांकि ऐसे संकीर्ण और दुराग्रहपूर्ण विचार किसी भी सामान्य विवेक वाले व्यक्ति को नहीं रखने चाहिए।

स्वाभाविक ही इन टिप्पणियों के सुर्खियों में आने के बाद सभी स्तरों पर लोगों ने चिंता जताई और सुप्रीम कोर्ट ने उनका स्वतः संज्ञान लिया। प्रधान न्यायाधीश की अगुआई वाली पांच जजों की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि संवैधानिक अदालत में न्यायाधीशों की टिप्पणियों को लेकर सख्त दिशानिर्देश बनाने की जरूरत है। पीठ के मुताबिक, सोशल मीडिया अदालत की कार्यवाही पर नजर रख रही है, तो हमें कोई भी टिप्पणी करते समय शालीनता बनाए रखनी चाहिए। समाज में न्यायाधीशों की छवि ऐसी होती है कि उनके वक्तव्यों को लोग न्याय का वक्तव्य समझते हैं। इसलिए ऐसे जिम्मेदार पद का निर्वाह करने वाले व्यक्ति को कोई भी टिप्पणी करते या कुछ भी बोलते हुए हर स्तर पर संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है। मगर अफसोस कि कई बार अदालतों में बैठ कर न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई के दौरान मुकदमे के कानूनी पहलुओं और उसकी बारीकियों पर बात करने के बजाय अनावश्यक रूप से ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं, जो सामान्य नैतिकता के लिहाज से भी, किसी रूप में उचित नहीं कही जा सकतीं।

संचार के जाल में उलझा बचपन

आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे चौदह-पंद्रह वर्ष की उम्र से पहले बच्चों को सोशल मीडिया के बजाय खेल के मैदानों में खेल का आनंद लेते देखना चाहते हैं।

संजीव राय

बच्चों की सोशल मीडिया पर व्यस्तता, आनलाइन गेमिंग और इंटरनेट की लत को लेकर दुनिया के कई देशों में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की कि सोशल मीडिया के उपयोग की उम्र तय होनी चाहिए। आस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या में लोग आनलाइन व्यस्त रहते हैं और बारह से सत्रह वर्ष के लगभग पचहत्तर फीसद बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि वे चौदह-पंद्रह वर्ष की उम्र से पहले बच्चों को सोशल मीडिया के बजाय खेल के मैदानों में खेल का आनंद लेते देखना चाहते हैं।

भारत में भी अभिभावकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि बच्चों को अपने कंप्यूटर-मोबाइल से दूर रह कर, वास्तविक जीवन के अनुभव लेने चाहिए। बच्चों को अनजान लोगों से आनलाइन जुड़ने की जगह, आसपास के मोहल्ले, बस्ती-गांव में वास्तविक लोगों से मिलना-जुलना चाहिए, यह सामाजिक और भाषाई विकास में सहायक होगा। तमिलनाडु में लगभग बीस फीसद विद्यार्थी आनलाइन गेम की लत से ग्रस्त हैं। वहां हुए एक अध्ययन में दो लाख स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों को शामिल किया गया था। इसी तरह राजस्थान के जयपुर में मनोचिकित्सालय की तरफ से बच्चों में इंटरनेट की लत को लेकर उनमें होने वाले व्यावहारिक और भावनात्मक बदलाव पर शोध शुरू हुआ है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में भी अभिभावकों, शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों ने अनुभव किया है कि लंबी अवधि तक बच्चों द्वारा कंप्यूटर-इंटरनेट के उपयोग और देर तक आनलाइन गेम खेलने के कारण मनोवैज्ञानिक और शारीरिक चुनौतियां उभर रही हैं।

दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के अस्पतालों में स्नायविक और सिरदर्द की समस्या से ग्रस्त बच्चों की संख्या बढ़ रही है। बच्चों की नजर कमजोर हो रही है, पीठ दर्द की समस्या बढ़ रही है। बारह से अठारह वर्ष के बच्चों में अत्यधिक 'स्क्रीन टाइम' के चलते बेचैनी, अकेलापन, बात-बात पर गुस्सा, अनिद्रा और पढ़ाई में मन न लगने जैसे लक्षण दिखते हैं तो यह चिंता की बात है। अनुमान है कि कोई बच्चा अगर एक घंटा फोन इस्तेमाल करता है तो उसकी नींद सोलह मिनट कम हो जाती है। जब नींद पूरी नहीं होगी, तो एकाग्रता का अभाव होगा और व्यवहार तथा भाषा में उग्रता आ सकती है। कोरोना में 'आनलाइन क्लास' के बाद से स्कूली छात्रों में एकाग्रता की समस्या कई जगह देखी गई है।

'यूनेस्को' ने पहले ही, सीखने की गुणवत्ता की चिंता, एकाग्रता की समस्या, कक्षा में अवरोध, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों के चलते दुनिया भर के स्कूलों में स्मार्ट फोन को प्रतिबंधित करने की अपील की थी, लेकिन अभी उसका असर एक चौथाई देशों में ही हुआ है। ब्राजील की एक संस्था ने 2017-2018 में एक अध्ययन किया था, जिसमें पाया गया कि तीन घंटे से अधिक समय तक फोन का उपयोग करना बच्चों के लिए खतरनाक होता है। अधिक फोन इस्तेमाल करने वाले चौदह से अठारह वर्ष आयु वर्ग के 2628 छात्रों पर हुए इस अध्ययन का निष्कर्ष यह था कि 39 फीसद लड़के और 55 फीसद लड़कियां 'थोरासिस स्पाइन पेन' (टीएसपी) से ग्रस्त थीं। इस वजह से गर्दन से लेकर पीठ के निचले हिस्से में दर्द बना रहता है। भारत सहित दूसरे देशों में अभिभावक समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कैसे उन्हें खेल के मैदान पर भेजें।

> **'यूनेस्को' ने पहले ही, सीखने की गुणवत्ता की चिंता, एकाग्रता की समस्या, कक्षा में अवरोध, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों के चलते दुनिया भर के स्कूलों में स्मार्ट फोन को प्रतिबंधित करने की अपील की थी, लेकिन अभी उसका असर एक चौथाई देशों में ही हुआ है। ब्राजील की एक संस्था ने 2017-2018 में एक अध्ययन किया था, जिसमें पाया गया कि तीन घंटे से अधिक समय तक फोन का उपयोग करना बच्चों के लिए खतरनाक होता है। अधिक फोन इस्तेमाल करने वाले चौदह से अठारह वर्ष आयु वर्ग के 2628 छात्रों पर हुए इस अध्ययन का निष्कर्ष यह था कि 39 फीसद लड़के और 55 फीसद लड़कियां 'थोरासिस स्पाइन पेन' (टीएसपी) से ग्रस्त थीं।**

तकनीकी हमारे जीवन को कुछ सुगमता दे रही है, लेकिन उससे बढ़ती परेशानियां अब घरों के भीतर दिख रही है। आज के बच्चों की बाहरी दुनिया मुख्य रूप से सोशल मीडिया के आसपास सिमटती जा रही है। इंस्टाग्राम और फेसबुक के 'लाइक' से वे खुश और दुखी हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर वे दिखाना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी शानदार है और वे किसी की परवाह नहीं करते हैं! बच्चों में कुछ भी मांगने का चलन बढ़ रहा है, भले ही उस सामान की कोई बहुत जरूरत न हो। कुछ भी मांगते रहने में केवल बच्चों का अपना दोष नहीं है। बच्चों के लिए सामान बनाने वाली कंपनियां अब बच्चों को अपना 'कर्मचारी/ ब्रांड एंबेसडर' रखती और उनके जरिए सोशल मीडिया पर 'मार्केटिंग' कराती हैं। मनोवैज्ञानिकों की मदद से बच्चों के लिए ऐसी 'मार्केटिंग' रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें अभिभावक बीच में न आएं और सीधे बच्चों तक 'प्रोडक्ट' या उत्पाद दिख जाए।

सुसान लिन ने एक पुस्तक लिखी है- 'हू इज रेजिंग द किड्स?' उसमें बताया गया है कि कैसे तकनीकी के साथ बाजारी संस्कृति और उपभोक्तावाद बच्चों पर प्रभाव डाल रहा है। लिन मानती हैं कि पैदा होते ही बच्चा मीडिया, एप्प और खिलौने बनाने वाली कंपनियों के लिए एक आकर्षक शिकार बन रहा है। इस किताब में रसेल बैंक का उल्लेख है। रसेल बैंक ने बाजार की अधिकाधिक मुनाफे की प्रवृत्ति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि 'यह बाजार वाला समाज अपने बच्चों को उपभोक्ता में बदल देता है, जिसमें बच्चे सिर्फ मांगते हैं। बच्चों और उनके माता-पिता को यह बाजार वह बेचेगा जो बच्चे मांग रहे हैं, न कि वह चीज, जिसकी बच्चों को वास्तव में जरूरत है।' मगर इन समस्याओं को चिह्नित कर लेने के बाद भी समाधान क्या है? बड़ी चुनौती यह है कि अभिभावकों के पास अपने बच्चों के लिए ही समय निकालना असंभव लगता है। अभिभावक अपनी भूमिका ही नहीं समझ पा रहे हैं और बच्चों के बाजार तथा दूसरों के भरोसे पल जाने की कल्पना कर रहे हैं।

आनलाइन लत के कारण बच्चों की सामाजिक परिधि छोटी होती जा रही है। उनमें शरीरिक श्रम से पलायन का भाव दिख रहा है। भागदौड़ की जिंदगी में अभिभावक अपने बच्चों से सुबह-शाम भी नहीं मिल पाते हैं। आखिर, माता-पिता की जगह टीवी-कंप्यूटर से बच्चे नैतिकता सीख रहे हैं। बच्चे इंटरनेट के जरिए किसके संपर्क में हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभिभावकों के पास यह जानने-सुनने का समय ही नहीं है। तकनीकी विकास से बढ़ता बाजार हमें कहां ले जा रहा है?

आस्ट्रेलिया में 2022 में 'ई-सेफ्टी' को लेकर हुए एक सर्वे में वयस्कों ने अपने आनलाइन के अनुभव साझा किए थे। उसमें अवांछित सामग्री भेजने से लेकर बिना अनुमति के उनके खाते तक पहुंचने की चिंता सामने आई थी। इसीलिए बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल की बात आस्ट्रेलिया में उठी है। इसके पहले यूरोपीय संघ ने भी ऐसा प्रयास किया था कि बच्चे एक निर्धारित उम्र से पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें, मगर बच्चों के आनलाइन अधिकारों की वकालत करने वाले संगठनों की आलोचना से यूरोपीय संघ सोशल मीडिया उपयोग के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं लागू करवा पाया। अब सवाल है कि क्या अभिभावक अपने स्तर पर बच्चों के 'स्क्रीन टाइम' को कम करने की पहल कर सकते हैं?

सक्रियता बनाम ठहराव

एकता कानूनगो बक्षी

जीवन सतत गतिमान बने रहने का नाम है। जब तक जीवन है, हमें सक्रिय रहना है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी भी है कि हम खुद को क्रियाशील बनाए रखें। लगातार लोगों से मिलते रहना, बोलते और सुनते रहना, सीखते रहना, अपने काम में मसरूफ रहना, एक तरह की अनवरत यात्रा में बने रहना, यकीनन खुशियां देता है, अवसाद से दूर रखता है। पर, जब भीतर से मन ठहराव चाह रहा हो, तब क्या कुछ देर के लिए किनारे जाकर खुद को मुक्त कर देना सक्रियता की तरह ही आवश्यक और स्वाभाविक नहीं होना चाहिए?

ऐसा भी नहीं कि हमें लगातार चलते ही जाना है। लंबी यात्रा के लिए कुछ पड़ाव भी जरूरी होंगे। जीवन में गति जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है थोड़ा-सा ठहराव। कुछ भी न करने का भाव, किसी को कुछ भी जताने, दिखाने, अपने आप को शिद्दत करने, उम्मीदों पर खरे उतरने, खुद को बदलने या लगातार बेहतर करते रहने की सनक में तब्दील होती तीव्र इच्छा जैसे अनावश्यक बोझ से खुद को कुछ समय के लिए मुक्त करने का भाव। यही जीवन का मानसिक ठहराव और तनिक विश्राम का जरूरी पड़ाव है, जो हमारी आगे की यात्रा को अर्थपूर्ण और सहज बनाता है।

कुछ भी न करने का मन, स्वस्थ और सक्रिय व्यक्ति के मन में भी आ सकता है। असल में यह मानसिक परेशानी नहीं है। यह अपने मन को आराम देने का तरीका हो सकता है, जिससे मानसिक दबाव, अवसाद से भी बचाव संभव है। यह जरूर है कि अगर ऐसा लगातार बना हुआ है, शारीरिक, मानसिक परेशानियां भी हम महसूस कर रहे हैं तो हमें चिकित्सक या अपनों से सलाह लेनी चाहिए। अपनी तात्कालिक परिस्थिति को पूरी तरह स्वीकार करते हुए हर हाल में संतुष्ट बने रहने का भाव या ठहराव, यात्रा की गति में अवरोधक नहीं बनता है। यह अल्प विराम बहुत जरूरी है, ताकि हम सही दिशा में सही तरीके से गतिवान बने रह सकें। जिस तरह सतत सक्रिय बने रहना ही हमारे अस्तित्व या जीवन का प्रमाण नहीं है, वैसे ही विश्राम या ठहराव की स्थिति भी किसी अंत की घोषणा नहीं होती। कभी-कभी ठहराव के बाद ही सही और सार्थक शुरुआत होती है। नया रास्ता दिखाई देने लगता है जो लक्ष्य के करीब पहुंचना सुगम कर देता है। स्वस्थ, नवोन्मेषी विचारों का प्रादुर्भाव भी समुचित ठहराव के बाद और शांत मनःस्थिति में संभव हो पाता है।

मुश्किल यह है कि जीवन की तमाम आपाधापी में इस आवश्यक विश्राम या ठहराव के बारे में हम सोच नहीं पाते। लगातार जुटे रहते हुए हमारा ध्यान इस बात पर जाता नहीं कि वास्तव में इतने क्रियाशील और अधिक व्यस्त हो गए हैं कि रुकने, थमने का थोड़ा भी समय हम नहीं निकाल पा रहे।

हम सभी के पास सीमित शारीरिक क्षमता होती है। अपने सामर्थ्य से अधिक काम करने पर थक जाना एक स्वाभाविक लक्षण है। हमें विश्राम की जरूरत पड़ने लगती है। विचारों के उद्गेग से उत्पन्न मानसिक दबाव को लंबे समय तक झेला तो जा सकता है, लेकिन उतना दुष्प्रभाव हमारे मस्तिष्क को भी थकाने का काम करता है। यही कारण है कि मनुष्य को नींद लेने की नैसर्गिक सौगात मिली हुई है। यह एक ऐसा दैनिक ठहराव या विश्राम का दैनिक पड़ाव है, जिससे हमारे तन और मन का जरूरी रखरखाव होता रहता है।

जल्दी से जल्दी गंतव्य तक पहुंचने की जिद में शरीर और दिमाग को तेज दौड़ाने के प्रयास भी हम करते हैं कभी-कभी। दिमाग को निरंतर अनावश्यक रूप से सक्रिय बनाए रखते हैं। थोड़ी फुर्सत में खाली बैठते हैं, तब भी दिमाग में कोई न कोई विचार उछलकूद करता रहता है। भूतकाल के कष्ट और भविष्य के सपने और सवाल मन को बेचैन बनाए रहते हैं। जबकि वर्तमान, जो हमारा वास्तविक जीवन है, उसमें सक्रियता और ठहराव के लिए निकट के प्रत्यक्ष अवसर हम नहीं देख पाते।

मानसिक विश्राम को लेकर समाज में, हमारे खुद के मन में बड़ी उदासीनता मौजूद है। रात को भरपूर नींद लेना या किसी पर्यटन स्थल पर चले जाना ही जीवन में ठहराव नहीं है। इस जरूरी सुकून और ठहराव के लिए रोजमर्रा की गतिविधियों में भी अपने ध्यान को केंद्रित कर राहत और विश्राम के पलों को जीया जा सकता है। किसी निर्माणाधीन मकान के सामने आराम से बैठ कर उसके बनने की प्रक्रिया को निहारने के अलावा किसी बगीचे में माली को काम करते या चालकनी में बैठकर सड़क की ओर देखा जा सकता है। समय निकालकर अपनी घरेलू सहायक या सहायिका के दुख-दर्द को सुना और उसकी खुशियों के भागीदार बना जा सकता है। जिन्हें हम देख रहे हैं, वे क्रियाशील हैं और हम विश्राम की स्थिति में होते हुए भी थकान का अनुभव करने लगते हैं।

कई बार गैरजरूरी सक्रियता के चंगुल में हम फंस जाते हैं। जब शरीर को आराम देने का वक्त होता है, तब भी हम लगातार सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ पढ़, देख रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी किसी एक गतिविधि को लंबे समय तक प्रसारित करते हुए सक्रिय बने रहते हैं। यह सक्रियता अनावश्यक-सी व्यस्तता में तब्दील हो जाती है। यह हमें ऊर्जा तो नहीं देती, थकावट अवश्य दे जाती है। सक्रियता के साथ ठहराव को भी खुले मन से स्वीकार करने की जरूरत है। हमने ठहराव ठीक से सीखा नहीं है। हम अपने आप को सक्रियता, दौड़-भाग से अलग करके सोच ही नहीं पाते। जब हम खुद को बंधे-बंधाए प्राप्त से मुक्त करके तनिक ठहराव की मानसिकता बनाएंगे तो सचमुच एक खूबसूरत दुनिया हमारे सामने होगी।

दुनिया मेरे आगे

> **सक्रियता के साथ ठहराव को भी खुले मन से स्वीकार करने की जरूरत है। हमने ठहराव ठीक से सीखा नहीं है। हम अपने आप को सक्रियता, दौड़-भाग से अलग करके सोच ही नहीं पाते। जब हम खुद को बंधे-बंधाए प्राप्त से मुक्त करके तनिक ठहराव की मानसिकता बनाएंगे तो सचमुच एक खूबसूरत दुनिया हमारे सामने होगी।**

निज भाषा

हिंदी एक ऐसी भाषना है जो यह बताती है कि औरों को अपने भीतर कैसे समेटा जाता है। भारत विविधता में एकता का राष्ट्र है, उसी भूमिका को हिंदी द्वारा बखूबी निभाया गया है। न जाने कितनी भिन्न भाषाओं के ऐसे शब्द हैं, जिन्हें हिंदी ने अपने हृदय में स्थान दिया है। पर अगर विश्व में किसी भाषा की अवहेलना की गई है, तो वह भी हिंदी ही है। विदेशी भाषाओं को बोलना, उनमें लिखना, वार्तालाप कर इतराना और उन्हें ज्ञान का मानक निरूत करना दर्शाता है कि हम हिंदी के प्रति कितने उपेक्षावान है। अमजन को अगर छोड़ दे तो सरकारों, सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, कालेजों, सभी कार्यालयों और निजी संस्थानों द्वारा हिंदी को ऐसा आघात पहुंचाया गया है, जिसकी क्षति अपूरणीय है। अफसोस यह है कि हमारी प्राथमिक भाषा दिवस या पखवाड़े के रूप में सिमट रही है। यह चिंतनीय विषय है। इस पर बात होनी चाहिए। कोई हल होना चाहिए। हम अपने पूर्वजों के दिए इस नायाब उपहार को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकते। हिंदी को बढ़ावा देने का आशय अन्य भाषाओं की अनदेखी बिल्कुल नहीं है। ऐसा माहौल बनना चाहिए कि हिंदी हमारे लिए गौरव हो, न कि हीनभावना का एक कारण।

- मो शाबान कुरैशी, कैराना, शामली

इंसाफ की गति

भारतीय न्यायपालिका के समक्ष लंबित मामलों की चुनौती सबसे बड़ी है। 2018 की नीति आयोग की एक रपट के अनुसार, हमारी अदालतों में मामलों को तत्कालीन दर पर निपटाने में 324 साल से अधिक समय लगेगा। तब 2.9 करोड़ मामले अदालतों में लंबित थे। देरी होने से पीड़ित और आरोपी, दोनों को न्याय दिलाने में देरी होती है। मगर सरकार स्वयं सबसे बड़ी वादी है, जहां आधे लंबित मामले सिर्फ राज्यों द्वारा दायर हैं। भारत की अदालतों में जजों की कमी के कारण काम समय पर नहीं हो पाता है। खाली पदों को भरने की मांग लंबे समय से उठाई जाती रही है। नई अदालतें गठित करने की मांग भी पुरानी है। मगर इस दिशा में सकारात्मक पहल नहीं हो पाती। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांचे गए 6,900 से अधिक भ्रष्टाचार के मामले कई अदालतों में लंबित हैं, जिनमें से 361 मामले 20 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। सवाल है कि इस जटिल स्थिति में न्याय को लेकर कैसी उम्मीद लगाई जा सकती है!

- युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

अक्षय ऊर्जा

ऊर्जा क्षेत्र में नए विकल्पों की तलाश' (लेख, 13 सितंबर) पढ़ा। आज ऊर्जा के बिना इंसान की जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मांग के अनुरूप कोयला मिल नहीं रहा है। हालांकि इस खतरे को बहुत सारे लोग समझ चुके हैं और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं और यही वजह है कि सौर ऊर्जा के महत्त्व को समझा गया है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान अक्षय ऊर्जा के मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति की है। हमें ऊर्जा का उपयोग सोच-समझ कर करना चाहिए। आवश्यकता होने पर ही बिजली का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे बल्बों का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बिजली की खपत कम से कम हो। मकानों में उजाले की पर्याप्त व्यवस्था हो। घरों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अक्षय ऊर्जा असीमित और प्रदूषण रहित ऊर्जा है जिसका नवीकरण होता रहता है।

- साजिद अली, चंदन नगर, इंदौर

नया चेहरा

अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनने का आम आदमी पार्टी (आप) का फैसला आश्चर्यजनक नहीं है। इसकी भूमिका पहले से ही बन रही थी। उन्हें बुनियादी ढांचे की समस्याओं को हल करने और नौकरशाही में जान फूंकने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी की सरकार को प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि इसके भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों ने अब अपनी गति खो दी है। हालांकि आतिशी अपेक्षाकृत युवा नेता हैं। केजरीवाल के प्रभाव की वजह से उनके अनुभव और उनकी क्षमता को कम आंकना चिंता का विषय है। मगर उनकी क्षमता इसरो भी साबित होगी कि क्या वे नौकरशाही में जान फूंक सकती हैं और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को हल कर सकती हैं। क्या उनका नेतृत्व पार्टी की राजनीतिक रफ्तार में एक नई जान फूंकेगा?

- अंशु भारती, बेगूसराय, बिहार

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

संवाद

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शनिवार, 21 सितंबर 2024

ग़लत संदेश

पश्चिम बंगाल और झारखंड आमने-सामने

पश्चिम बंगाल सरकार ने अचानक जिस तरह से झारखंड के साथ लगती अंतरराज्यीय सीमा को बंद कर दिया और जवाब में झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी JMM वहां से जरूरी सामानों की सप्लाई रोकने की धमकी दे रही है, वह दो राज्यों के आपसी रिश्तों के लिहाज से बहुत ही खराब प्रसंग माना जाएगा। इस टकराव से दोनों राज्यों के सामान्य लोगों की परेशानियों में इजाफा भले ही जाए, विवाद निपटाने में कोई मदद नहीं मिलने वाली।

ममता बनर्जी । सील किए बॉर्डर

बाढ़ में डूबे 11 जिले | दरअसल, दामोदर वैली कॉरपोरेशन (DVC) की ओर से पानी छोड़ा गया। वहीं, पश्चिम बंगाल के 11 जिले बाढ़ में डूब गए थे। मुख्यमंत्री और TMC चीफ ममता बनर्जी इसे 'मानव निर्मित बाढ़' कह रही हैं। उनका आरोप है कि झारखंड स्थित DVC से पानी छोड़े जाने के कारण यह बाढ़ आई। लेकिन तथ्य यह भी है कि पिछले दो-तीन दिनों से उन इलाकों में तेज बारिश हुई है। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण झारखंड के जलाशय खतरे के निशान के आसपास पहुंच गए थे।

कमिटी की देखरेख में फैसला | सबसे बड़ी बात यह है कि पानी छोड़ने का फैसला राज्य सरकार का नहीं होता, न ही इसके पीछे तात्कालिक राजनीतिक समीकरणों की कोई भूमिका होती है। इसका पूरा सिस्टम काफी पहले से बना हुआ है। कब कितना पानी छोड़ा जाना है, यह निर्णय एक रेग्युलेशन कमिटी करती है जिसमें दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। सभी संबंधित पक्षों को सही समय पर फैसले की सूचना देने की भी प्रक्रिया पूरी तरह परिभाषित है।

परस्पर विरोधी दावे | ममता बनर्जी का कहना है कि इस बार उनकी सरकार को समय पर सूचित नहीं किया गया, जबकि दामोदर वैली कॉरपोरेशन और केंद्र सरकार का कहना है कि इस बार भी पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। अगर अमल में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो इस बात की जांच की जा सकती है कि सूचना देने या संबंधित व्यक्ति तक पहुंचने में किस स्तर पर और किस वजह से चूक हुई। आरोप-प्रत्यारोप को इस स्तर पर ले जाने से हालात को बेहतर बनाने में मदद नहीं मिलने वाली।

विपक्षी समन्वय पर सवाल | वैसे, ममता बनर्जी ने तकनीकी तौर पर बॉर्डर सील करने की वजह यह बताई है कि झारखंड से आने वाली गाड़ियां बाढ़ के पानी में बह न जाएं। लेकिन अगर बात यही होती तो झारखंड की तरफ से जरूरी सामानों की सप्लाई रोकने की धमकी नहीं आती। ध्यान रहे, झारखंड में विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. की सरकार है और तृणमूल कांग्रेस भी विपक्षी खेमे का ही हिस्सा मानी जाती है। ऐसे में इन दोनों सरकारों के बीच इस तरह का विवाद विपक्ष की राजनीति को लेकर भी कोई अच्छा संदेश नहीं दे रहा।

दो दूनी चार

बच्चे की पेंशन

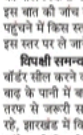

रमेश तिवारी

आपका बच्चा रिटायर होने के बाद भी खुशहाल जिंदगी बिताए, इसकी प्लानिंग आप खुद कर सकते हैं। उसके पैदा होने के तुरंत बाद रकम जमा की जा सकती है। इसके लिए सरकार की ओर से नैशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के तहत वात्सल्य स्कीम शुरू की गई है।

यह कार्यक्रम समझा जाता है कि बच्चे अपने सपनों को पूरा करें, उसमें माता और पिता पैसे की कोई कमी न होने दें। कई लोग अपने बच्चे के भविष्य के लिए माइनर अकाउंट खोलकर फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट में निवेश करते हैं। यानी वे अपनी जगह सीधे बच्चे के नाम पर ही निवेश करते हैं। इसके पीछे सिर्फ इमोशनल फैक्टर है। ज्यादातर मामलों में इससे पैसे का कोई बड़ा लाभ नहीं मिलता। सुकन्या समृद्धि स्कीम को छोड़ दें तो शायद ही कोई प्लान है, जो बच्चे के नाम पर निवेश करने से अतिरिक्त लाभ देता है। अभी यह साफ नहीं है कि वात्सल्य स्कीम में पैसे जमा करने के दौरान कोई टैक्स लाभ मिलेगा या नहीं। फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड्स में भी बच्चे के नाबालिग होने (18 वर्ष से कम आयु) के दौरान उसके नाम पर निवेश करने पर कोई टैक्स लाभ नहीं मिलता। इनकम क्लब करने के नियमों के अनुसार माता-पिता को ब्याज से होने वाली आय या कैपिटल गेन होने पर टैक्स का भुगतान करना होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट में हर साल देना होगा, जबकि म्यूचुअल फंड और वात्सल्य में टैक्स टाला जा सकता है।

अगर कोई बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर रहा है तो उस पैसे की जरूरत 18 साल की उम्र से ठीक पहले पड़ेगी। रिटायरमेंट के बाद बच्चे की जिंदगी कैसी होगी, इससे ज्यादा जरूरी है कि उसकी पढ़ाई की जरूरतों की प्लानिंग की जाए। अगर वह पढ़ाई अच्छी तरह से कर ले, बढ़िया कमाने लगे तो रिटायरमेंट की प्लानिंग खुद कर सकता है।

बहरहाल, रिटायरमेंट प्लानिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वात्सल्य स्कीम अच्छी हो सकती है। अगर कोई बच्चे की पेंशन के लिए निवेश कर रहा है तो यह दशकों की बेहद लंबी अवधि का निवेश होगा। इतने लंबे वक्त के लिए इक्विटी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में किया गया निवेश ज्यादा फायदा दे सकता है। वात्सल्य में डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी रकम जमा करनी होगी, जिनका रिटर्न अपेक्षाकृत कम हो सकता है। जमा रकम लॉक भी होगी, जबकि म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं है।

वैसे रकम लॉक होने का एक लाभ भी है। यह मुमकिन है कि जब बच्चा बड़ा हो तो लंबे अरसे तक मेहनत से जमा की गई इस रकम की अहमियत को न समझे। लेकिन, वह पूरी रकम को एक झटके में नहीं उड़ा सकेगा। रकम के बड़े हिस्से को सिर्फ पेंशन के तौर पर ही भुनाया जा सकेगा। यानी पूरी जिंदगी थोड़ी-थोड़ी रकम पाने का इंतजार करना होगा। इस स्कीम की सबसे बड़ी परेशानी भी इसी के साथ जुड़ी है। पूरी जिंदगी कितनी पेंशन मिलेगी, यह इस बात पर तय होगा कि ठीक रिटायरमेंट के समय कितना रिटर्न आँकर हो रहा है। अगर उस वक्त कम रिटर्न का दौर हो तो पूरी जिंदगी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये जरूरी है कि वात्सल्य स्कीम बच्चे की पढ़ाई के भी काम आ सके। इसके लिए 18 साल का होने से पहले जमा रकम का बड़ा हिस्सा निकालने की छूट हो।

ऑफ दि ट्रैक

मनबढ़ बैक्टीरिया

दिलीप लाल

बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं। इनको एंटीमाइक्रोबियल्स भी कहते हैं। लेकिन, इनके लगातार इस्तेमाल के नुकसान भी हैं। बैक्टीरिया खुद को इन दवाओं का सामना करने के लिए तैयार कर लेते हैं। इन दवाओं का कोई असर नहीं होता फिर बैक्टीरिया पर। इस अवस्था को एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट (AMR) कहते हैं। The Lancet की हालिया रिपोर्ट बताती है कि 1990 से लेकर 2021 के दौरान हर बरस दुनियाभर में 10 से अधिक लोगों ने AMR संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर अभी से इस बारे में कुछ न किया गया तो 2050 तक यह आंकड़ा प्रति बरस 20 लाख मौतों तक पहुंच सकता है। वैसे कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मानना है कि मौतों का मौजूदा डेटा ही अनुमान से कहीं ज्यादा है, क्योंकि AMR के कई केस रिपोर्ट नहीं हो पाते। कई देशों में इनका अलग से रेकॉर्ड भी नहीं रखा जाता। इस तरह के इंफेक्शन का सबसे ज्यादा खतरा होता है बुजुर्गों पर। पिछले पांच बरसों में 70 बरस से अधिक उम्र के लोगों में मृत्यु दर 80% बढ़ गई है। चिंता यह भी है कि केवल बैक्टीरिया ही नहीं, बल्कि कवक (fungi), वायरस और परजीवी भी AMR विकसित कर लेते हैं। नतीजतन एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीपैरासिटिक्स सहित कई दवाओं का प्रभाव खत्म हो जाता है।

गगनयान की तैयारियों का बड़ा पहलू है अंतरिक्ष यात्रियों का मेन्यू

स्पेस में कैसे खाते-पीते हैं लोग

पंदभूषण

आठ दिन से आठ महीने खिंच गई सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा ने भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के खान-पान, रहन-सहन को लेकर उत्सुकता जगा दी है। आने वाला समय लंबी अंतरिक्ष यात्राओं का ही होने वाला है। मंगल ग्रह की कोई भी यात्रा ढेढ़ साल से कम की नहीं हो सकती। ऐसे में सुनीता विलियम्स के इस अनियोजित अनुभव के जरिये ही सही, हम इसका अंदाजा ले सकते हैं कि अंतरिक्ष में लोग कैसे रहते हैं, किस तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से उनका पाला पड़ता है।

शून्य गुरुत्व की चुनौतियां | माइक्रोग्रैविटी, यानी शून्य के आसपास पहुंचने वाले सूक्ष्म गुरुत्व में न केवल चीजों का व्यवहार बल्कि शरीर का भीतरी कामकाज भी बदल जाता है। यान में चीजें एक जगह रुकी नहीं रहतीं। उन्हें बांधकर या चिपकाकर न रखा जाए तो जरा भी छू जाने पर हवा में तैरने लगती हैं। इधर-उधर टकराने लगती हैं और जेरिक्स का सबक बन जाती हैं। खाने-पीने की चीजों में दो तरह के एहतियात रखे जाने जरूरी हैं। जहां तक हो सके, ये हवाई होनी चाहिए। दूसरे, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस इनमें नहीं होने चाहिए क्योंकि छोटी सी जगह में कई लोगों के रहने पर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

शरीर का व्यवहार | खानपान से जुड़ी शारीरिक समस्याओं में लार ग्रंथियों, स्वाद ग्रंथियों, आहार नाल-खासकर आंतों और मूत्र प्रणाली का व्यवहार है, जो माइक्रोग्रैविटी में उलट-पुलट हो जाता है। इंसान का पूरा इर्दाल्यूशन धरती पर रहकर हुआ है और इसकी दिशा इसी के अनुरूप ढलने की रही है। आंख के आंसू तक भीतर रहें या बाहर, उनकी स्वाभाविक गति ऊपर से नीचे जाने की होती है। इस प्रकार में दो-चार दिन का व्यवधान शरीर बर्दाश्त कर लेता है।

खुद को बदलते हैं लोग | लेकिन महीनों किसी ऐसी जगह रहने में, जहां ऊपर या नीचे जैसा जहां कुछ है ही नहीं, शरीर का भीतरी व्यवहार बदल जाता है। जीवन की लय इस कदर बिगड़ जाने पर भी इंसान पस्त न पड़े, पूरी शारीरिक-मानसिक क्षमता के साथ अपने लिए निर्धारित शोधकार्य में जुटा रहे, इसके लिए धरती से आपूर्ति के स्तर पर काफी काम करना होता है और वहां रहने वाले लोग भी खुद को बहुत बदलते हैं।

कैसी होती हैं तैयारियां

- शून्य गुरुत्वाकर्षण से निपटना पड़ता है
- हड्डियों की मजबूती के लिए एक्सरसाइज
- फ्रीज ड्राइड खाना, स्पेशल स्ट्रॉ से पानी

न स्वाद, न गंध | अंतरिक्ष यात्री हमेशा जुकाम जैसा लगा होने की बात कहते हैं। असल जुकाम नहीं, बस वैसा ही अहसास। किसी चीज में कोई गंध नहीं आती। आंख, मुंह, कान, नाक- हर जगह भीतर से एक सूजन जैसी लगी रहती है। इस समस्या को छोड़ दें तो भूख लगना और वॉशरूम जाने की इच्छा पैदा होना बिल्कुल धरती जैसा ही है। महीनों स्पेस स्टेशन पर गुजार लेने के बावजूद इन बुनियादी बातों पर माइक्रोग्रैविटी का खास असर नहीं होता।

फ्रीज-ड्राइड भोजन | संसार के पहले अंतरिक्ष यात्री, रूस के यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में 1 घंटा 48 मिनट का ही वक्त बिताया था, लेकिन वहां रहते हुए उन्होंने अल्यूमिनियम के तीन ट्यूब्स से खाना खाया था। आगे अंतरिक्ष यात्राओं का समय बढ़ा तो ट्यूब के अलावा वे फ्रीज-ड्राइड खाने के टुकड़े ले गए। फ्रीज-ड्राई से खाना बहुत हल्का हो जाता है, जीवाणु मर जाते हैं, और स्वाद या पोषण पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस, खाने से पहले गरम पानी से या भाप से इन्हें हाइड्रेट करना होता है। शुरू में इसके लिए गरम पानी नहीं मिल पाता था लेकिन अभी यह कोई समस्या नहीं है। रही बात पेय पदार्थों की तो वे पाउडर की शक्ल में जाते हैं और पानी मिलाकर पीने लायक बना लिए जाते हैं। पानी या कोई भी पेय पीने के लिए थोड़ा अलग तरह के, वाल्व वाले स्ट्रॉ आजमाने होते हैं।

स्पेस फूड की प्रयोगशालाएं | इंसानी अंतरिक्ष यात्रा की महत्वाकांक्षा वाले हर मुल्क में उस तरफ के खान-पान से जुड़ी प्रयोगशालाएं बनी हुई हैं, जहां इस पर काम चलता रहता है कि कैसे कोई नया स्वादिष्ट और पोषक भोजन या पेय अंतरिक्षयात्रियों के मेन्यू में जोड़ दिया जाए। भारत में भी गगनयान से जुड़ी तैयारियों का यह एक जरूरी पहलू है।

लोअर बॉडी की एक्सरसाइज | कुछ बातें अंतरिक्ष में व्यायाम और उत्सर्जन से जुड़ी तकनीकों पर भी होनी चाहिए। हड्डियां कमजोर हो जाने, यहां तक कि स्पेस स्टेशन पर अपने जरूरी कामों में भी अक्षम हो जाने का खतरा बराबर बना रहता है। ऊपर और लोअर बॉडी की एक्सरसाइज का एक नियमित कार्यक्रम हर अंतरिक्ष यात्री को अपने दैनिक अनुशासन में शामिल करना होता है। उत्सर्जन की तकनीकें धीरे-धीरे करके परफेक्शन तक पहुंची हैं, लेकिन स्टेशन में गंदगी फैल जाने की छोटी-मोटी दुर्घटनाएं अब भी कभी-कभार हो जाती हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

www.nbt.in

विश्वास से आई कश्मीर में शांति

हमारे शास्त्र और उपनिषद शांति और समरसता की आवश्यकता को भली-भांति स्पष्ट करते हैं। शांति का आदर्श केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और वैश्विक भलाई के लिए भी है।

आज मानवतावादी और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर इस अवधारणा को वैश्विक स्तर पर और विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर जैसे कई अन्य हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में बखूबी स्थापित कर रहे हैं। पिछले दो दशकों से उनकी अनुआई में आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयंसेवकों ने जम्मू और कश्मीर में शहीद सैनिकों के परिवारों को योग, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से उनके भाव भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही नहीं, उग्रवाद के गलत रास्ते पर भटके हुए सैकड़ों कश्मीरियों को भी योग और ध्यान का प्रशिक्षण दिया। दशकों की हिंसा और अशांति के कारण लोगों का एक-दूसरे पर विश्वास नहीं रहा था। इन दूरियों को समाप्त करने के लिए श्री श्री रविशंकर ने एक पहल की, 'पैगाम- ए-मोहब्बत'। इस कार्यक्रम में 100 शहीदों के परिवार, हिंसा में किसी अपने को खो चुके 50 कश्मीरी परिवार और उग्रवाद का रास्ता छोड़ चुके कई युवा शामिल थे। लेकिन उनमें से किसी को भी पहले से यह नहीं पता था कि वे एक-दूसरे के आमने-सामने खड़े होने वाले हैं। और जब उन्होंने एक-दूसरे को देखा तो अविश्वास और संशय का दबा हुआ गुबार बाहर निकल पड़ा।

विश्व शांति दिवस

नकुल धवन

एक शहीद की वीर नारी, उग्रवादी रह चुके युवाओं और उनके परिवारों को देख कर अपना क्रोध न रोक सकी। जो दुख उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था अचानक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। अपनी बात कहकर वह अपने आंसुओं को रोक न पाई। उस महिला ने बाद में बताया, 'जब मैं वहां अकेली खड़ी रो रही थी, तो एक अद्भुत घटना घटी। दूसरे पक्ष से एक कश्मीरी बुजुर्ग महिला आगे बढ़ी और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। हम दोनों बहुत रोए। उन बुजुर्ग की आंखों में मुझे अपने जैसा ही दर्द दिखाई दिया।' इसके बाद क्रोध और शंका पिघल कर सहानुभूति और सद्भावना में परिवर्तित हो गए।

योग, ध्यान, युवा नेतृत्व कार्यक्रमों सहित कई अन्य सेवा प्रकल्पों में कश्मीरी लोगों की भागीदारी आज एक नए और शांतिपूर्ण कश्मीर की कहानी कह रही है। घाटी में शांति, आहिंसा और विकास की दिशा में किए जा रहे श्री श्री रविशंकर के प्रयास इस बात का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जब दिल और दिमाग बेहतर भविष्य के लिए एकजुट होते हैं, तो गहरे से गहरे घाव भी ठीक हो सकते हैं।

(लेखक आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ प्रशिक्षक हैं)

चलते-चलते...

धूप का फायदा किस तरह उठाया जा सकता है, यह सीखने के लिए साइप्रस से बेहतर जगह कोई नहीं। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस देश के 93% से ज्यादा घर अल्टरनेटिव एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोलर हीटिंग या धूप से पानी गर्म करने के लिए यहां बड़े पैमाने पर सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे। साइप्रस के सभी होटल इसी के जरिये पानी गर्म करते हैं।

किसका फ़ायदा

बांग्लादेश के राजनीतिक संकट का असर उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। माना जा रहा है कि इसका फायदा भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को मिल सकता है। ऐसा होना क्यों मुश्किल है, आइए समझते हैं।

AI image

इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद

बांग्लादेश में पहली कपड़ा फैक्ट्री 1978 में खुली थी। आज वहां 40 लाख लोग इस काम में लगे हैं। GDP में 10% हिस्सेदारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की है। पिछले साल उसने 54 बिलियन डॉलर कीमत के कपड़े निर्यात किए थे।

सस्ती मजदूरी

बांग्लादेश की कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों में महिलाएं ही बहुमत हैं। फिर, मजदूरी बेहद सस्ती है वहां, जिससे लागत कम आती है। हालांकि कम मजदूरी का मुद्दा वहां उठता रहा है।

5 पॉइंट

सरकार की नीति

बांग्लादेश सरकार ने एक्सपोर्ट प्रॉसेसिंग जोन डिवेलप किए हैं। EU और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टैक्स में छूट और सब्सिडी दी जाती है। वहीं, भारत ने अपना फोकस कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर रखा है।

भारत का आयात शुल्क

कई एक्सपर्ट्स की मानना है कि भारत अपने घरेलू उद्योगों को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, जिससे घाटा हो रहा। लोकल मैन्युफैक्चरिंग जिन कपड़ों और दूसरी चीजों का इस्तेमाल करते है, उस पर 2017 के बाद से 13% इम्पोर्ट टैरिफ बढ़ाया जा चुका है।

पश्चिम की पसंद

पश्चिम को जिस पैमाने पर और जैसा प्रॉडक्ट चाहिए, अब उसमें बांग्लादेश को विशेषज्ञता हासिल हो चुकी है। ग्लोबोपीय मार्केट में भारत के मुकाबले बांग्लादेशी उत्पादों को पहुंच फिलहाल ज्यादा है।

प्रस्तुति : शैलेंद्र पांडेय

मणिपुर की हिंसा में उग्रवादी भी शामिल

लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता (रिटायर्ड) पूर्वोत्तर के इकलौते सैन्य अधिकारी थे, जो आर्मी कमांडर के पद तक पहुंचे। वह पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ थे और मणिपुर का जिम्मा उनके पास था। पिछले साल दिसंबर में वह रिटायर हुए। उन्होंने प्रवीन कालिता को बताया कि क्यों मणिपुर बार-बार हिंसा के चक्र में फंस जाता है और वहां शांति लाने के लिए क्या करना होगा :

सप्ताह का इंटरव्यू

राणा प्रताप कलिता

■ **मणिपुर में इतने लंबे अरसे बाद भी हल नहीं निकल पाने की वजह क्या है?**

मणिपुर में जारी संघर्ष के तीन कारण हैं। पहली वजह है कि दोनों समुदायों के बीच अब भी अविश्वास है और जातीय आधार पर पूरी तरह से ध्रुवीकरण हो चुका है। यहां तक कि सरकारी अधिकारी और पुलिसकर्मी भी इसी आधार पर बंट चुके हैं। दूसरी वजह है- हथियारों का आसानी से मिलना। हाल में हमने देखा कि ड्रोन और दूसरी चीजों का हथियारों के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी वजह, गलत और भ्रामक जानकारी फैलाने का लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सभी पक्ष सोशल मीडिया के जरिये मिस-इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। इसलिए, जब तक इन वजहों को नहीं रोका जाता, तब तक शांति स्थापित करने में मुश्किल पेश आएगी।

■ **केंद्रीय सुरक्षाबलों की भारी तैनाती के बावजूद स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है। क्या वजह है?**

मैं मानता हूं कि सुरक्षाबलों की मौजूदगी है, लेकिन इलाके की बनावट ऐसी है कि हर जगह की सुरक्षा नहीं की जा सकती। दूसरी समस्या है मणिपुर पुलिस का ध्रुवीकरण, जो कि एक चुनौती है। हालांकि इस मामले में हालात बेहतर हुए हैं। किसी भी राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती वहां की अथॉरिटीज की सहायता के लिए होती है। इंटेलिजेंस और दूसरे जरूरी सहयोग के लिए उन्हें राज्य पुलिस पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में मणिपुर पुलिस का ध्रुवीकरण शुरुआत केंद्रीय बलों के कामकाज में बाधा डाल रहा है। लेकिन हां, मुख्य समस्या इलाके की बनावट के कारण है। इसके अलावा, दोनों पक्षों का लगभग पूरा समाज ही हथियार उठा चुका है।

■ **राज्य में हथियार खुलेआम लहराए जा रहे हैं...**

पुलिस थानों से पांच से 6 हजार हथियार लूटे गए थे, जो अब भी लोगों के पास हैं। इसके अलावा, म्यांमार में अस्थिरता और भारत-म्यांमार के बीच जगह-जगह खुली सीमा के कारण उधर से बड़ी संख्या में हथियार आ रहे हैं।

■ **क्या इस हिंसा में उग्रवादी भी शामिल है?**

शुरुआत से ही हमने देखा है कि दोनों समुदायों से जुड़े उग्रवादी इस हिंसा में शामिल हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स भी कि घाटी आधारित कुछ उग्रवादी समूह म्यांमार के कैंपों से आए और यहां हिंसक गतिविधियों में शामिल हुए। कुकी SoO ग्रुप भी इसमें शामिल रहे हैं। हाल ही में जीरीबाम की घटना में यह पता चला कि मारे गए 6 लोगों में से दो आम नागरिक थे, तीन कुकी समूह के थे और एक UNLF-Pambei ग्रुप का था, जो एक मैतेई समूह है।

■ **सिविल सोसायटी की क्या प्रतिक्रिया रही है?**

दोनों पक्षों के सिविल सोसायटी ऑर्गनाइजेशन मुख्य रूप से अपने-अपने समुदायों के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। कुकी समुदाय अपने लिए अलग प्रशासन की मांग कर रहा है। वहीं, मैतेई समुदाय का कहना है कि वह मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता पर किसी तरह का खतरा नहीं आने देगा। दोनों समुदायों की सिविल सोसायटी एक-दूसरे से बात नहीं करना चाहतीं।

■ **हालिया शांति-शराबा यूनिफाइड हेडक्वॉर्टर के नियंत्रण को लेकर है। यह क्या मामला है?**

मणिपुर में साल 1997 में यूनिफाइड हेडक्वॉर्टर्स बनाए गए थे। उस समय स्टैटिजिक ग्रुप की कमान चीफ सेक्रेटरी के पास थी। फिर, 2004 में बदलाव हुआ और इस ग्रुप की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री करने लगे। हालांकि पिछले साल मई से जो हालात बने, उसे देखते हुए नोटिफिकेशन में राज्य को एक सुरक्षा सलाहकार नियुक्त करने की सलाह दी गई और उसे संयुक्त मुख्यालय का चेयरमैन बना दिया गया। लेकिन, नोटिफिकेशन के एक पैरे में कहा गया है कि सीएम जब चाहें बैठक बुला सकते हैं और उस बैठक की अध्यक्षता वही करेंगे। इसलिए मेरी समझ के अनुसार वास्तव में अधिकार मुख्यमंत्री के पास ही हैं और यूनिफाइड हेडक्वॉर्टर पर उन्हीं का नियंत्रण है। वैसे भी कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। ऐसे में यह मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वह सिक्योरिटी अडवाइजर या चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के जरिये कानून-व्यवस्था को देखने का कार्यभार निभाएं।

> भारत-म्यांमार सीमा को पूरी तरह से सील करना होगा ताकि हथियारों की तस्करी न हो सके। हथियारों और युद्ध शुरू करने वाले सामानों की बरामदगी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने की जरूरत है। साथ ही, कुकी और मैतेई समाज के बीच संवाद शुरू करना चाहिए। इसमें सिविल सोसायटी और मीडिया की भी भूमिका हो सकती है

■ **इस मामले का समाधान क्या हो सकता है?**

पहला कदम है हिंसा पर तुरंत नियंत्रण पाना। इसके लिए हमें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही भारत-म्यांमार सीमा को पूरी तरह से सील करना होगा ताकि हथियारों की तस्करी न हो सके। घाटी के अंदरूनी इलाकों पर नियंत्रण रखना होगा ताकि हथियारबंद उपद्रवियों की आवाजाही को रोका जा सके। दूसरा कदम है, दोनों समुदायों के बीच बातचीत शुरू करना, जिससे अविश्वास को कम किया जा सके। मेरा सुझाव है कि शांति और सुलह के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। इसमें ऐसे तटस्थ सदस्य हों, जिन्हें दोनों समुदाय स्वीकार करें। संघर्ष शुरू होने के बाद कई सारे जांच आयोग बैठाए गए थे और कुछ मामलों को CBI ने भी संभाला था। इन सभी मामलों को बंद किया जाना चाहिए। साथ ही, इस संघर्ष में जिन लोगों ने अपना बहुत कुछ खोया है, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों समुदायों को जोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका सभी वर्गों को शामिल होना चाहिए। यह केवल राजनीतिक संवाद नहीं है। मणिपुर के बाहर की सिविल सोसायटी, मीडिया और अन्य को भी इसमें शामिल होना चाहिए।

रीडर्स मेल

▸ पद की गरिमा

यह पत्र 20 सितंबर के लेख 'ब्यूरोक्रेसी का यह रोग बहुत पुराना है' से संबंधित है। कितनी दुखद बात है कि सुभाष चंद्र बोस के 1921 के इस्तीफे से लेकर आज तक, इन 100 बरसों से ज्यादा के सफर में ब्यूरोक्रेसी में कोई खास सकारात्मक बदलाव नहीं हुए। उनके मूल चरित्र न बदलने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार भले ही किसी पार्टी की हो, देश को तो नौकरशाह चलाते हैं। इसलिए वह अपने आपको सबसे ऊपर समझते हैं। पूजा खेडकर की कहानी अकेली नहीं है। देश में न जाने कितने ही IAS अधिकारी होंगे जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे होंगे। पूजा खेडकर का लाल बत्ती का शौक उन्हें भारी पड़ गया। इस बीमारी का सबसे दुखद पहलू यह है कि एक अधिकारी हमेशा दूसरे अधिकारी को बचाए रखता है। यह भी माना जाता है कि IAS लॉबी से टकर लेना आसान नहीं। लेकिन सभी अधिकारी एक जैसे नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पद की गरिमा बनी रहे, इस बात पर अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए।

बाल गोविंद, नोएडा

▸ आस्था का सवाल

तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबर सभी जगह सुर्खियों में है। हालांकि कोई बात जब चर्चा में आती है, तो आमतौर पर उसके बारे में एकतरफा धारणा बनने लगती है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद का मौजूदा विवाद एक लैब रिपोर्ट की आशंका के आधार पर खड़ा हुआ है। इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। लेकिन, देश जानना चाहता है कि आखिर प्रसाद का सच क्या है? आस्था से खिलवाड़ हुआ या राजनीतिक खिलवाड़ हो रहा है या लैब रिपोर्ट गलत है? कुछ तो दाल में काला है। अब जल्दी से जल्दी इसकी निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि लोगों को हकीकत का पता चल सके। मामले में दोषी पाए जाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे फिर कोई लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने की हिम्मत न कर सके।

राम प्रकाश शर्मा, वसुंधरा

नवभारत टाइम्स : ए. 2.2.2.2.2 सर्वोदय एन्क्लेव। दिल्ली-110017 के लिए संपादक व प्रकाशक पुनीत अग्रवाल द्वारा प्रकाशित। नवभारत टाइम्स बैनेट, कॉलमन एवं कलर्स लिमिटेड के लिए ग्राफिक प्लस (प्रा.) द्वारा मुद्रित। नवभारत टाइम्स भवन, सी.पी.सी. 2.2.2.2.2 ए.एस.एफ. **संपादक-प्रधान संपादक (इन्फो. मीडिया)** : **राजीव सचदेव**। **संपादक (प्रिंट)** : **राजेश मिश्र**। **संपादक (ऑनलाइन)** : **मनोज कुमार**। **प्रबंध संपादक (मार्केटिंग, कॉमर्स, प्रोडक्शन व एडवर्टा.)** : **मोनू**। 2.2.2.2.2.2 फैक्स : 2.2.2.2.2.2 टेलीफोन : 2.2.2.2.2.2 वेबसाइट : 2.2.2.2.2 सी.पी.सी. 2.2.2.2.2 दूरभाष : 2.2.2.2.2 ए. बी. आई. लिमिटेड के द्वारा मुद्रित। **संपादक के दायित्व** : **नवभारत टाइम्स** ए. 2.2.2.2.2 सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली-110017 से प्रकाशित। (रिजस्टर्ड नंबर) : **प्रकाशन तारीख** (इस अंक में प्रकाशित समाचार सामग्री के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

दैनिक जागरण
आस्था से खिलवाड़ ईश्वर के साथ छल है

आस्था पर आघात

तिरुपति के विश्व प्रसिद्ध बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किए जाने वाले लड्डुओं को तैयार करने में पशुओं की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किए जाने का मामला जितना सनसनीखेज है, उतना ही आस्था पर आघात करने वाला भी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पहले यह बयान जारी किया कि तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डुओं को बनाने में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें पशुओं की चर्बी मिली रहती थी, फिर उन्होंने गुजरात की एक सरकारी प्रयोगशाला से मिली रपट के आधार पर यह कहा कि लड्डुओं को बनाने में जिस घी का उपयोग होता था, उसमें सचमुच पशुओं की चर्बी, मछली के तेल आदि का प्रयोग होता था। यदि उक्त रपट सही है तो इससे अधिक आघातकारी, अनैतिक एवं अधार्मिक और कुछ हो ही नहीं सकता। केवल इतने से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि इस मामले में केंद्र सरकार ने भी दखल दिया है, क्योंकि हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाला यह प्रकरण गहन जांच की मांग करता है। यह पता चलना ही चाहिए कि सच्चाई क्या है? यह कहा जा रहा है कि तिरुपति मंदिर के लड्डुओं को बनाने में जिस घी का इस्तेमाल किया जाता था, उसकी आपूर्ति करने वाली कंपनी उसे 320 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध कराती थी। क्या यह संभव है?

आज दूध की औसतन कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है और एक किलोग्राम घी तैयार करने में आमतौर पर 20-25 लीटर दूध की खपत होती है। यदि दूध गाय का हो तो खपत और अधिक होती है। आखिर ऐसे में कोई तीन-चार सौ रुपये किलो के हिसाब से घी कैसे उपलब्ध करा सकता है? यदि कोई यह दावा करे कि वह घी बनाने की प्रक्रिया में निकलने वाले मट्ठे जैसे सहउत्पाद की बिक्री करके कम दाम पर घी उपलब्ध करा सकता है तो यह गणित भी गले नहीं उतरता, भले ही कितनी भी मात्रा में घी का उत्पादन क्यों न किया जाए। अच्छा हो कि तिरुपति का मामला सामने आने के बाद किसी की ओर से यह स्पष्ट किया जाए कि जो डेरी कंपनियां सात-आठ सौ रुपये किलो में घी बेचती हैं, उनका घी वास्तव में कितना शुद्ध होता है? बात केवल तिरुपति मंदिर में मिलने वाले देसी घी से बने लड्डुओं की ही नहीं है, क्योंकि अन्य मंदिरों और साथ ही बाजार में कथित तौर पर शुद्ध देसी घी से तैयार सामग्री मिलती है। यदि देश में कहीं पर भी चार-पांच सौ रुपये किलो में देसी घी मिल रहा है तो यह संभव ही नहीं कि उसमें किसी तरह की मिलावट न हो। तिरुपति मंदिर का मामला यह भी बता रहा है कि हिंदुओं के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की आवश्यकता है। यदि अन्य समुदाय अपने धार्मिक स्थलों की देखभाल कर सकते हैं तो फिर हिंदू समाज क्यों नहीं कर सकता?

लापरवाही की हद

राज्य सरकार भूमि विवाद में कमी लाने तथा जमीन की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से भूमि सर्वेक्षण करवा रही है। इस संबंध में सरकार की मंशा पूरी तरह साफ है। सर्वेक्षण से जमीन मालिक का नाम आन रिकार्ड हो जाएगा, जिससे हेराफेरी की गुंजाइश काफी कम हो जाएगी। किंतु, इस बीच भू-राजस्व विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के ऐसे कारनामे सामने आए हैं, जो चिंताजनक ही नहीं, शर्मनाक भी हैं। परती भूखंड पर अवैध कब्जा या जाली दस्तावेज के जरिए खरीद-बिक्री के मामले तो अक्सर सुनने में आते हैं, किंतु गया और गोपालगंज जिले का मामला तो अजीबोगरीब है। भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से गया जिले में सरकारी राशि से बने भवन को खाली भूखंड बताकर रजिस्ट्री करा ली गई तथा आनन-फानन अंचल अधिकारी ने दाखिल-खारिज करते हुए लगान की रसीद भी काट दी। इसी तरह गोपालगंज शहर में भू-माफिया और अंचल कार्यालय के कर्मियों की मिलीभगत से बस स्टैंड की जमीन की अवैध तरीके से दाखिल-खारिज करते हुए जमाबंदी कायम कर दी गई। हालांकि, मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को प्राथमिकी कराने का आदेश दे दिया। वरीय अधिकारियों को इस संदर्भ में तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को चिह्नित करना चाहिए। दोष साबित होने पर ऐसे लापरवाह तथा भ्रष्टकर्मियों को बर्खास्तगी से कमतर सजा नहीं दी जानी चाहिए। यह भी देखने की जरूरत है कि किन प्रविष्टानों की आड़ में भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी ऐसे कारनामों को अंजाम देने में सफल हो पाते हैं।

जमीन-जायदाद के मामलों में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के प्रति जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना संभव नहीं हो सकेगा

मजबूत होती भारत-अमेरिका मैत्री

श्रीराम चौलिया

भावुक द्वेषकर अमेरिका को भारत का दुश्मन करार देना आसान है, लेकिन वैश्विक पटल पर देश के उत्थान के लिए उसकी मित्रता अनिवार्य है

अवधेश राजपूत

वर्ष 2014 से अब तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आठ बार केवल एक देश की यात्रा की है और वह है अमेरिका। अमेरिका को प्राथमिकता के पीछे मोदी का सोच यह है कि उससे भारत के उत्थान हेतु जितने लाभ प्राप्त होते हैं, उतने अन्य कहीं से प्राप्त नहीं होते। भारत के मुख्य लक्ष्य हैं-आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति, सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी और भूराजनीतिक संतुलन। इन सबकी पूर्ति में अमेरिका की अहम भूमिका है। व्यापार में आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का सालाना कारोबार लगभग 200 अरब डालर का है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक यह व्यापार तीन गुना बढ़ सकता है। अन्य वाणिज्यिक साझेदारों के मुकाबले अमेरिका के साथ भारत को व्यापार अधिशेष होने की भी संतुष्टि है। भारत की राष्ट्रीय आय का करीब 50 प्रतिशत व्यापार से आता है और इसीलिए अमेरिका से भारत की आर्थिक उन्नति का सीधा संबंध है। आगामी दशकों में भारत को विशाल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अमेरिका के साथ व्यापार और विदेशी निवेश निर्णायक होंगे।

हालांकि भारत में विदेशी निवेश के मोर्चे पर सिंगापुर और मारीशस को प्रथम एवं द्वितीय स्थान दिया जाता है, लेकिन वास्तव में तीसरे स्थान पर विराजमान अमेरिका ही हमारे देश में ठोस विदेशी पूंजी लेकर आता है। अमेरिकी निवेश से भारत में केवल सेवाओं की ही फायदा नहीं हुआ है, बल्कि औद्योगीकरण में भी उसकी अहम भूमिका है। मोटर वाहन, रसायन, इलेक्ट्रानिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न विनिर्माण क्षेत्रों में अमेरिकी निवेशक भारत में सक्रिय हैं। उनके द्वारा लाखों भारतीयों को रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने स्वयं के बारे में कहा है कि 'गुजराती होने के नाते व्यापार मेरे खून में है', भलीभांति जानते हैं कि अमेरिका जैसे संपन्न देश में बसे पूंजीपतियों को आकर्षित करके भारत लाने में ही राष्ट्र का हित है। अपने हर अमेरिकी दौरे में वह वहां के व्यापार जगत के दिग्गजों संग मिलते-जुलते हैं और उन्हें भारत में निवेश को प्रेरित करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआइ, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक जैसे अत्याधुनिक व्यवसायों में महारत हासिल करने वाले देश वैश्विक शक्ति समीकरण में ऊंचे स्थान पर रहेंगे। ऐसी उभरती हुई तकनीकी के मामले में भी अमेरिका शीर्ष पर है। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल (आइसेट) के अंतर्गत अनेक तकनीकों के सहविकास और सहनिर्माण पर जोर दिया है। ऐसी तकनीक के दोहरे उपयोग होते हैं और उनसे सैन्य आधुनिकीकरण भी होता है। तकनीकों के सहनिर्माण का उपक्रम दोनों पक्षों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नेतृत्व में चलाया जा रहा है।

इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अमेरिका ने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी चीन को संवेदनशील प्रौद्योगिकी देना रोक दिया है, जबकि ऐसी प्रौद्योगिकी को वह भारत के साथ साझा करने को तत्पर है। इस दोहरी रणनीति का कारण अमेरिका की यह चिंता है कि चीन आर्थिक और सैन्य ताकत में उससे आगे निकल जाएगा और पश्चिमी उदार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को नष्ट कर देगा। भारत लोकतंत्र होने के नाते और शक्ति में चीन से अपेक्षाकृत कमतर होने के कारण अमेरिका के अभिजात्य वर्ग और आम जनता को खतरा नहीं लगता। इसीलिए अमेरिका भारत पर अंतरराष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं और नियमों जैसी बाधाओं को दूर करने में सहायक रहा है। अमेरिका-चीन संबंधों में कटुता ने अमेरिका-भारत सामरिक साझेदारी को नया आयाम दिया है। अमेरिका अपनाटीय संतुलन (आफशोर बैलेंसिंग) रणनीति के तहत भारत और अन्य मैत्रीपूर्ण देशों को समुद्र और सशक्त करके चीन पर अंकुश लगाने की मंशा रखता है। वामपंथी और गुटनिरपेक्षता को लेकर आग्रही विश्लेषकों ने इसे लेकर यही चेतावनी दी है कि भारत को अमेरिका के रचे हुए खेल में प्यादा बनकर चीन से जूझना नहीं मोल लेनी चाहिए, पर मोदी सरकार ने इस दृष्टिकोण को तवज्जो नहीं दी है, क्योंकि चीन आए दिन आक्रामकता दिखाता रहता है।

वर्तमान स्थितियों में भारत के लिए एशिया पर हावी होने के लिए प्रयासरत चीन और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते अमेरिका के बीच तटस्थ रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि चीन भारत का सामरिक प्रतिस्पर्धी है, जबकि अमेरिका भारत का सामरिक साझेदार है। मोदी सरकार की विदेश नीति ने चीन और अमेरिका के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, लेकिन इस विषय पर भारत में स्पष्टता नहीं बन पाई है। यहां कई समीक्षक और नागरिक घरेलू राजनीति के नजरिये से अमेरिका की परखते हैं। अमेरिका के कुछ सरकारी संस्थान भारत के आंतरिक विषयों पर आलोचना करते रहते हैं। इसी तरह वहां का मीडिया तथा बुद्धिजीवी वर्ग मोदी सरकार और सत्ता परिवार के विरुद्ध दुष्प्रचार करता रहता है। इसके चलते कई भारतीय अमेरिका की अनुचित हस्तक्षेप और अवांछित कृत्यों के लिए दोषी ठहराते हैं। कुछ विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका गुप्त अभियानों के माध्यम से भारत में सत्ता परिवर्तन की भी कोशिश कर रहा है। लगता है कि ऐसे आलोचक भारत की लोकतांत्रिक क्षमता पर उतना भरोसा नहीं रखते, जितना उन्हें रखना चाहिए। ऐसे लोगों में वैश्विक भूराजनीति का ज्ञान भी नहीं है। उनकी संवेदनशीलता अंतरराष्ट्रीय राजनीति से परे है। अमेरिका को भारत का दुश्मन करार देना और उसे चालबाज कहना आसान है, किंतु वैश्विक पटल पर भारत के उत्थान के लिए अमेरिका की मित्रता अनिवार्य है। यह मानना पड़ेगा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसियों के मामलों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच अपेक्षित तालमेल नहीं रहा। फिर भी, समग्रता में देखा जाए तो अमेरिका की दोस्ती हमारे लिए कारगर रही है और आगे भी रहेगी। विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखकर हमें इस मैत्री को संभालकर आगे ले जाना होगा।

(स्तंभकार अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ एवं 'प्रेडुसर: इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स' के लेखक हैं)

response@jagran.com

हरियाणा में शह-मात और भितरघात

राज कुमार सिंह

कुछ छोटे दल और उनके गठबंधन भले ही जीतें नहीं, लेकिन वे नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं

हरियाणा को हल्के में लेना अक्सर भारी पड़ जाता है। नमांकन वापसी और घोषणापत्र जारी होने के बाद की तस्वीर बताती है कि चुनाव एकतरफा नहीं होने जा रहा। दलबदल, टिकट वितरण और लोकलुभावन वादों से भी साफ है कि सत्ता के दावेदार चुनावी बिसात पर कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। ऐसे में भितरघात के चलते सत्ता कोई भी करवट ले सकती है। कुछ विरोधी टिकट वितरण में निपटा दिए गए तो कुछ को चुनाव में ठिकाने लगाया जा सकता है। बेशक सत्ता के प्रमुख दावेदार भाजपा और कांग्रेस ही हैं, लेकिन मुकाबला बहुकोणीय होगा। अन्य दलों-निर्दलियों की भूमिका इनका खेल बनाने-बिगाड़ने की ज्यादा रहेगी।

यदि कांग्रेस और भाजपा के घोषणापत्रों की बात करें तो वे आसमान खुली दो दुकानों पर लगे एक-दूसरे से ज्यादा 'आकर्षक सेल' के विज्ञापन जैसे नजर आते हैं, पर मतदाता दोनों को दस-दस साल देख चुके हैं। इसलिए चुनावी वादों की अनुभव की कसौटी पर भी कस जाएगा। कुछ धारणाओं की चर्चा अक्सर होती है। मसलन, हरियाणा के मतदाता किसी को जिताने के लिए नहीं, बल्कि किसी को हराने के लिए वोट करते हैं। यह भी कि राज्य के मतदाता अमूमन उसी दल या गठबंधन को वोट करते हैं, जिसकी केंद्र में सरकार होती है या फिर बनने वाली होती है। ऐसे में कुछ स्वाभाविक सवाल हैं। मसलन 2019 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने किसे हराने के लिए वोट किया था? कांग्रेस की जीत की संभावनाएं तब भी बताई गई थीं। फिर वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी भाजपा से भी नौ सीटें पीछे कैसे रह गई? अब केंद्र में राजग सरकार है और अगले लोकसभा चुनाव 2029 में होंगे। ऐसे में हरियाणा के मतदाता किसे चुनेंगे? कई बार साबित हो चुका है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण एवं बहुलतावादी देश में मतदाताओं का मन भांपना या उसे किन्हीं परंपराओं-धारणाओं में कैद करके देखना चुनावी पंडितों की खामख्याली भर है। क्या किसी ने 2019 में भविष्यवाणी की थी कि नवगठित जजपा 'किंग मेकर' साबित होगी? तब भाजपा ने 'अब की बार, 75 पार' का नारा दिया था। जजपा ने जवाब में भाजपा को 'यमुना पार भेजने' का नारा दिया था, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा बनी तो दोनों ने गठबंधन कर लिया। सवा चार साल गठबंधन सरकार चलाने के बाद रास्ते अलग हो गए तो फिर एक दूसरे के विरुद्ध ताल ठोकी जा रही है।

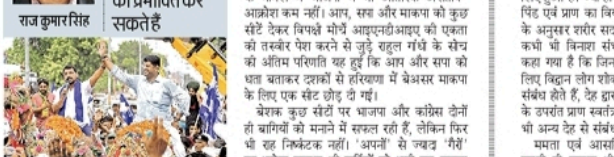

सिरसा में दुष्यंत चौटाला संग चंद्रशेखर। एएनआइ

इसमें दो राय नहीं कि भाजपा के विरुद्ध दस साल की सत्ता विरोधी भावना के चलते इस बार कांग्रेस के लिए स्थितियां अपेक्षाकृत अनुकूल हो सकती हैं, लेकिन इस अतीत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस जीती हुई बाजी हारने में माहिर हो चली है तो भाजपा हारी हुई बाजी जीतने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। दरअसल भाजपा के लिए कांग्रेस से बड़ी चुनौती किसान आंदोलन, अग्निवीर योजना और महिला पहलवानों के धरना-प्रदर्शन से अपने विरुद्ध बना जनमानस है, क्योंकि सत्ता विरोधी भावना पांच साल से बढ़कर दस साल हो जाने के अलावा तो कांग्रेस के पक्ष में और कुछ नहीं। हां, इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते वर्चस्व के चलते कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी सरीखे दिग्गज कांग्रेस को अलविदा अवश्य कह रही है। अभी भी कांग्रेस में मौजूद दो राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री पद के लिए तालं ठोक ही रहे हैं। अंतर्कलह का आलम यह है कि एक दशक से भी ज्यादा समय से कांग्रेस हरियाणा में बिना संगठन चुनाव लड़ रही है। संसदों को विधानसभा चुनाव न लड़वाने की नीति के नाम पर सैलजा और सुरजेवाला को तो टिकट नहीं ही मिला और उनके समर्थकों को भी टिकट देने में कंजूसी की गई। नतीजतन, चुनाव प्रचार में सैलजा और सुरजेवाला ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रहे। टिकटों में लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा बताता है कि हुड्डा कांग्रेस के लिए अपरिहार्य हैं। टिकट वितरण के मामले में भाजपा में भी आंतरिक असंतोष-आक्रोश कम नहीं। आप, सपा और माकपा को कुछ सीटें देकर विपक्षी मोर्चे आइएनडीआइए की एकता की तस्वीर पेश करने से जुड़े राहुल गांधी के सोच की अंतिम परिणति यह हुई कि आप और सपा को धता बताकर दशकों से हरियाणा में बेअसर माकपा के लिए एक सीट छोड़ दी गई।

बेशक कुछ सीटों पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बागियों को मनाने में सफल रही हैं, लेकिन फिर भी रह निष्कंटक नहीं। 'अपनों' से ज्यादा 'गैरों' पर भरोसा जताना भी पार्टियों को भारी पड़ सकता है। अंबाला का मामला बेहद दिलचस्प है। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की हुड्डा से निकटता छिपी नहीं है। जब सैलजा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थीं तो निर्मल सिंह ने अपनी बेटी चित्रा सरवारा के साथ पार्टी छोड़कर अलग संगठन बना लिया था। बाद में वह आप में चले गए। आप में उन्हें महत्व भी मिला, लेकिन हुड्डा का वर्चस्व बढ़ता देख पिता-पुत्री कांग्रेस में वापस लौट आए। कांग्रेस ने निर्मल को अंबाला शहर से टिकट भी दे दिया, लेकिन उनकी बेटी चित्रा अंबाला कैंट से निर्दलीय उम्मीदवार बन गई हैं। पिछली बार निर्दलीय लड़कर चित्रा 44 हजार वोट पाने में सफल रही थीं और भाजपा उम्मीदवार अनिल विज 20 हजार वोटों से जीत गए थे। जमानत मिलने और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल 'हरियाणा का बेटा' बनकर जब चुनाव प्रचार करेंगे तो सत्ता विरोधी वोटों का विभाजन बढ़ेगा ही, जिससे कांग्रेस को नुकसान और भाजपा को लाभ होगा। पिछली बार एक दर्जन सीटों पर हार-जीत का अंतर ज्यादा नहीं था। ऐसे में जीतें भले नहीं, आप तथा इनेलो-बसपा-हलोप व जजपा-असपा गठबंधनों को मिलने वाले वोट नतीजों को प्रभावित तो कर ही सकते हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

पितरों की शांति

पिंड और प्राण का संयोग किसी विशेष लक्ष्य के लिए हुआ है। ज्यों ही यह कर्तव्य पूर्ण हो जाता है, पिंड एवं प्राण का वियोग निश्चित है। सांख्य योग के अनुसार शरीर सदा विनाशी है और आत्मा का कभी भी विनाश संभव नहीं। इसीलिए गीता में कहा गया है कि जिनके प्राण चले गए हों, उनके लिए विद्वान लोग शोक नहीं करते। देह से ही सारे संबंध होते हैं, देह द्वारा मृत्यु को अंगीकार कर लेने के उपरांत प्राण स्वतंत्र हो जाता है। प्राण का किसी भी अन्य देह से संबंध नहीं रहता, वह मुक्त है।

ममता एवं आसक्ति जितनी सुजनात्मक है उतनी ही घातक भी हो सकती है। माता-पिता मोहवश संतान के भरण-पोषण में अपनी समस्त शक्ति लगा देते हैं। उसी तरह संतान भी अपने माता-पिता से प्रेम करती है और यथाशक्ति उनकी सेवा करती है। पति-पत्नी आत्मिक प्रेम के कारण एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। मित्र आदि संबंध भी मोह के धागों से ही जुड़े हैं। इन संबंधों से वियोग सहने की घड़ी आए तो यही ममता एवं आसक्ति निराशा के अंधकार में डुबो सकती है।

जो शरीर जन्मे हो हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, जो एक क्षण भी स्थायी नहीं है, उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। वहीं, मृत आत्मा को श्रद्धांजलि देना, उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना करना, उनकी किसी अपूर्ण इच्छा को पूर्ण करने का यथासंभव प्रयास करना उचित है। ऐसा माना जाता है कि मृतात्मा या पितरों की शांति के लिए जो जल दिया जाता है, वह उसे पितृलोक में मिल जाता है। स्कंदपुराण में वर्णन किया गया है कि मृतात्मा के बंधु-बांधव भूतल पर जिन अश्रुओं का त्याग करते हैं, मृतात्मा को उन अश्रुओं को परलोक में पीना पड़ता है। किसे प्रेय के जाने से शोक अचानक कम नहीं होता। उसकी भावनात्मक क्षतिपूर्ति में समय लगता है, परंतु विचार व ज्ञान एक ऐसी शक्ति है, जो वस्तुस्थिति भले न बदल सके, उससे लड़ने की शक्ति अवश्य प्रदान करती है।

दिर्वकल तौमर सिंह

बहुत कठिन है डगर 'मंगल' की!

प्रदीप

एलन मस्क भले ही मंगल पर मानव बस्ती बसाना चाहते हों, पर यह आसान है नहीं

स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क ने हाल ही में कहा है कि उनकी कंपनी अगले दो वर्षों में मंगल ग्रह पर इंसान को उतारने में सफल हो जाएगी। मस्क का कहना है कि उनका लक्ष्य 20 वर्षों में मंगल पर एक ऐसी रिहायशी बस्ती बसाना है, जो अपनी आवश्यकताओं की स्वयं पूरा करने में सक्षम होगी। उल्लेखनीय है कि स्पेस-एक्स का जन्म ही मंगल पर मानव कालोनी बसाने के उद्देश्य से ही हुआ है और मस्क का दृष्टिकोण इस दिशा में स्पष्ट और दूरदर्शी है।

मंगल और पृथ्वी में पहली नजर में कई समानताएं दिखती हैं, जो इसे पृथ्वी सरीखा ग्रह बनाती हैं। मंगल का घूर्णन काल लगभग 24.6 घंटे है, जो पृथ्वी के दिन-रात चक्र के करीब है। मंगल की सतह पर पहाड़, घाटियां और मैदान हैं, जो पृथ्वी की भौगोलिक संरचनाओं से मिलते-जुलते हैं। पानी की उपस्थिति के संकेत भी मिलते हैं। लेकिन कुछ भिन्नताएं भी हैं, जो मंगल की मानव बस्तियों में तब्दील करने में बड़ी चुनौती पेश करती हैं। मंगल पर न तो वायु पर्याप्त है और न ही सूर्य का प्रकाश। वहां का अधिकतम तापमान अंटार्कटिका के न्यूनतम तापमान के लगभग बराबर है। हानिकारक सौर किरणें मंगल की सतह पर सीधे धावा बोलती हैं। इसका वायुमंडल, जो 95 प्रतिशत कार्बन डाइआक्साइड से बना है, हमारे लिए दमघोंटू है।

हालांकि विज्ञानियों का मानना है कि मंगल के वातावरण को पृथ्वी जैसा बनाना संभव है। मंगल को बदलने और उसे पृथ्वी जैसा बनाने के विचार को विज्ञानियों ने 'टेराफार्मेशन' नाम दिया है। भले ही यह विचार रोमांचक लगता हो, लेकिन टेराफार्मिंग आसान नहीं है। इसके साथ कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। मंगल की आबाद करने के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण हैं : वायुमंडल का निर्माण तथा उसे स्थिर व गर्म रखना। इससे जुड़ा एक सुझाव यह है कि अगर मंगल पर परमाणु विस्फोट किए जाएं तो इसके वातावरण को रहने लायक बनाया जा सकता है। परमाणु हथियारों के विस्फोट से कार्बन डाइआक्साइड निकलेगी, जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा होगा और मंगल ग्रह की ठंडी जलवायु गर्म हो जाएगी। मस्क का भी यही मानना है। लेकिन इस तकनीक में काफी पैसा खर्च होगा और साथ ही इसके कई खतरे भी हैं।

विस्फोट से मंगल का वातावरण बहुत ठंडा हो सकता है जिससे वहां का तापमान गर्म होने के बजाय और ठंडा हो सकता है। विस्फोट से राख और धूल की चादर मंगल को ढक लेगी जिससे वहां के औसत तापमान में गिरावट आ जाएगी और वहां नाभिकीय शीत (न्यूक्लियर विंटर) शुरू हो सकता है। इससे मंगल ग्रह के वातावरण और उसकी सतह पर विकिरण फैलने का खतरा भी है जो हमारे भविष्य की इकलौती उम्मीद यानी मंगल को तबाह कर सकता है। लिहाजा, मंगल की टेराफार्मिंग टेढ़ी खीर है और कोई भी कदम उठाने से पहले हमें हजार बार सोचना होगा।

(लेखक विज्ञान संचारक हैं)

मेलबाक्स

सामाजिक मूल्यों में कमी के दुष्परिणाम

'संस्कारहीनता के घातक दुष्परिणाम' शीर्षक से लिखे आलेख में प्रकाश सिंह ने एक बड़ी समाजिक समस्या की ओर संकेत किया है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जब से सेक्युलरिज्म के नाम पर मूल्यविहीन शिक्षा देखी जाने लगी है, उसका परिणाम यह हुआ है घर-परिवार, कार्य संस्थान और स्कूल-अस्पताल कोई जगह सुरक्षित नहीं रह गई है। पाश्चात्य संस्कृति की अंधी दौड़ में लोग मानवीय संवेदनाओं की बलि चढ़ा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के जो आंकड़े उन्होंने दिए, वे आंकड़े डराने वाले हैं। ये आंकड़े यह भी बताते हैं कि न्याय की लेकर जो हमारी पद्धति है, कहीं न कहीं उसमें भी कमी है। जो एक निर्दोष की कीमत पर सौ अपराधियों को अपनी गतिविधियां स्वतंत्र रूप से जारी रखने के लिए समाज में छोड़ देती है। न्यायपालिका को भी अपना विश्लेषण स्वयं करना चाहिए कि कहीं उसके निर्णय अपराध बढ़ाने में योगदान तो नहीं कर रहे। आज विज्ञापनों में स्त्री को जिस प्रकार मात्र भोग की वस्तु बनाकर पेश किया जा रहा है, वह उचित नहीं। हमें यह समझना होगा कि प्रत्येक विचार व्यवहार मर्यादा से बंधा होता है। मर्यादा टूटने पर परस्पर संबंध तार-तार होंगे ही।

yuvrajpallav21@gmail.com

सिखों से तार्किक अपील

राहुल गांधी का अमेरिका में यह अनर्गल प्रलाप कि भारत में सिखों को पगड़ी बांधने से रोका जा रहा है, कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा है और उनको गुरुद्वारा जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, झूठ का पुलिंदा है। राहुल गांधी ने यह केवल इसलिए कहा, ताकि खालिस्तानी नेता पन्नू खुश हो जाए। वह सिखों को इस बात के लिए उकसा रहे हैं कि खालिस्तान के समर्थन में वे आगे आएं और देश एक बार और विभाजन की विभीषिका से गुजरे। सिख भाइयों से अपील है कि वे राहुल के झांसे में न आएं। इसे कांग्रेस ने वर्ष 1984 में तीन हजार से अधिक सिखों की निर्मम हत्या की थी। इसी कांग्रेस के कारण स्वर्ण मंदिर की पवित्रता पर आंच आई थी, वहां सेना को घुसने का आदेश दिया था। इसी कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियों के कारण 1947 में हिंदुओं के साथ सिखों का बड़े स्तर पर कत्लेआम हुआ था। उस समय विभाजन धर्म के आधार किया गया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और गांधी की कुछ नीतियों के कारण संपूर्ण समाधान नहीं हो सका था। नतीजा यह हुआ कि वह समस्या वैसी की वैसी ही रह गई।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

संस्कारहीनता के घातक परिणाम

प्रकाश सिंह का आलेख 'संस्कारहीनता के घातक परिणाम' अत्यंत सटीक है। वह दुष्कर्म जैसे घिनौने कांड के कारणों की तह में गए हैं। वर्ष 2012 के निर्भया कांड के बाद कानून सख्त बनाए गए, लेकिन दुष्कर्म जैसे संगीन मामलों का ग्राफ कम होने के बजाय बढ़ता रहा। वर्ष 2015 के बाद से, जब से स्मार्टफोन का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ा, दुष्कर्म के मामलों में भी तेजी आई है। आज अधिकतर लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है। ये स्मार्टफोन इंटरनेट के प्रयोग में काफी दक्ष हैं और इंटरनेट पर अश्लील सामग्रियों की भरमार है। पोर्नोग्राफी का सभी उम्र के लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, हालांकि बच्चों और युवाओं पर इसका काफी बुरा असर पड़ता है। भारत अश्लील सामग्री देखने वाले देशों में ऊपर की पंक्ति में है। बड़ी तादाद में किशोर व युवा मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं, जो घंटों हर रोज मोबाइल पर लगे रहते हैं। इंटरनेट की इस विशाल दुनिया में ओटीटी प्लेटफार्म्स, इंटरनेट मीडिया समेत अन्य साइटों पर परोसी जा रही अश्लील सामग्री पर अंकुश लगाना ही होगा। युवाओं में मूल्य आधारित शिक्षा और संस्कार के स्तर पर आई गिरावट है। घर में मां-बाप पैसा कमाने और केवल भौतिक सुखों से परिपूर्ण करने में लगे रहते हैं, बच्चों को समय ही नहीं देते। यदि देते भी हैं तो मानवीय मूल्य देने का प्रयास नहीं करते हैं। आज संयुक्त परिवार काफी कम रह गए। जब युवाओं में मानवीय मूल्य नहीं विकसित होंगे, तो बुराई की तरफ तो जाएंगे ही।

सीपी बंसल, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: जीनेट डीकास्टा द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

सम्पादकीय

फेड का संतुलनकारी कदम

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व (फेड) एक बार फिर गलत साबित होना नहीं चाहता। महामारी के दौरान मुद्रास्फीति में इजाफे को गलत समझने के बाद वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कोई झटका न लगे। बेरोजगारी की दर अगस्त में 4.2 फीसदी बढ़ी जबकि एक वर्ष पहले इसमें 3.8 फीसदी का इजाफा हुआ था। इसके परिणामस्वरूप फेड की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) ने बुधवार को यह निर्णय लिया कि वह फेडरल फंड के लक्षित दायरे को 50 आधार अंक कम करके 4.75 से 5 फीसदी के दायरे में रखेगी। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों को 2022 के आरंभ से अब तक 11 बार बढ़ाया और वह दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। ऐसा मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने के लिए किया गया जो जून 2022 में 9.1 फीसदी के उच्चतम स्तर पर जा पहुंची। हालांकि बाजार ने दरों में 25 से 50 आधार अंकों की कमी का अनुमान किया था और एसऐंडपी 500 के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद दिन के अंत में अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट पर बंद हुए। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं हुआ।

यद्यपि फेड ने 50 आधार अंकों की कटौती के साथ सहजता की शुरुआत की लेकिन इसके भविष्य के कदम और दरों में कमी की गुंजाइश अभी भी बहसतलब है। फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने नीतिगत घोषणा के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि बाजार को इसकी व्याख्या एक नई तरह की गति के रूप में नहीं करनी चाहिए। फेड के अधिकारियों के अनुमान बताते हैं कि इस वर्ष दरों में एक और 50 आधार अंकों की कमी हो सकती है जबकि 2025 में एक प्रतिशत की कमी की जा सकती है। हालांकि अनुमान हमेशा संशोधन का विषय होते हैं और यह देखना होगा कि एफओएमसी कैसे आगे बढ़ती है। 2.5 फीसदी की मुद्रास्फीति की दर जहां फेड के मध्यम अवधि के दो फीसदी के लक्ष्य के अनुरूप है वहीं नीतिगत ब्याज दरों में भारी कटौती करने यह जोखिम हो सकता है कि कहीं मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर ही न बनी रहे। फेड कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। इस संदर्भ में यह ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है कि सहजता का यह चक्र आम चक्रों से अलग है। चूंकि अर्थव्यवस्था किसी तरह की मुश्किल में नहीं है। कम ब्याज दर के कारण व्यय में अपेक्षाकृत तेजी से इजाफा हो सकता है। इसके अलावा पॉवेल ने दरों से जुड़े निर्णय कों नीतिगत दरों को निरपेक्ष के करीब ले जाने का एक व्यवस्थित कदम बताया। निरपेक्ष दर ऐसी नीतिगत दर है जो न तो प्रतिबंधात्मक हो और न ही समायोजन वाली। महामारी के पहले माना जा रहा था कि 2.5 फीसदी की दर निरपेक्ष दर होगी लेकिन उसके बाद से इसमें इजाफा हुआ है और यह बढ़ोतरी अमेरिका के बजट घाटे में ढांचागत इजाफा होने की वजह से हुआ। एक अनुमान के मुताबिक यह 3.5 से 4.8 फीसदी के बीच है। इससे दरों में कमी की गुंजाइश सीमित हो जाती है। हालांकि बैंक ऑफ इंगलैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी हाल ही में नीतिगत दरों में कमी की है। वैश्विक वित्तीय बाजार और पूंजी प्रवाह फेड के कदमों से अधिक प्रभावित होते हैं। वित्तीय हालात को सहज बनाने के लिए कम नीतिगत दर की अपेक्षा होगी। पिछले कुछ समय से ऐसा हो भी रहा है।

आर्थिक विकास के साथ लोकतंत्र की रक्षा, वैश्विक पहचान का पैमाना

भारत की सफल विदेश नीति एक अच्छी नीति की शुरुआत है और विदेशों में भारत की एक अलग पहचान भी महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, पर केवल विदेश नीति से ही देश की 141 करोड़ जनता का पेट भरना और उसे विकास की राह में ले जाना मुमकिन नहीं है। देश की आवाम को सशक्त योजनाओं और आर्थिक तंत्र के मजबूत होने के साथ-साथ उत्पादन में आत्मनिर्भरता से ही मजबूत बनाया जा सकता है, तब जाकर देश की गरीबी एवं भूखमरी पर निजात पाई जा सकती है। धर्मनिरपेक्षता के मजबूत कंधों के सहारे देश को सांप्रदायिक सद्भाव के मार्ग पर ले जाने के साथ-साथ शांति और सौहार्द का वातावरण तैयार किया जा सकता है। देश में शांति सौहार्द और उत्पादन में आत्मनिर्भरता ही विकास के सच्चे पैमाने हैं।

संजीव ठाकुर

आजादी के 77 वर्ष के व्यतीत हो जाने के बाद स्वाधीनता एवं लोकतंत्र की आस्था का सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। लोकतंत्र की यथार्थ सीमाओं में वित्तीय विकास और प्रयास हमे वैश्विक स्थापना प्रदान करते हैं।आर्थिक विकास के बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें मजबूत आधार स्तम्भ नहीं दे सकतीं हैं,मजबूत वित्तीय प्रबंधनऔर संवैधानिकता की जुगलबन्दी जी देश के चहुमुखी विकास को मूर्तरूप दे सक्सटें हैं।हमें स्वतंत्रता अथक मेहनत एवं खून पसीना बहाने के बाद प्राप्त हुई है। स्वाधीनता के बाद हमारे संवैधानिक इतिहास में लोकतंत्र की संरचना को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इस महान लोकतंत्र की आस्था और विश्वास को हमें अनंत काल तक बनाए रखना है और इसके साथ ही स्वाधीनता को भी चिरकाल तक अस्मिता की तरह संजोए रखने की आवश्यकता है। जातिभेद, रंगभेद और सामाजिक कुरीतियों को नजरअंदाज कर लोकतंत्र की अंतर्निहित शक्ति को और ताकतवर बनाना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत की सरकारें वर्ष 2022 तक यह प्रयास करती रही कि एक नवीन, मजबूत भारत का उदय हो, जहां अमीरी, गरीबी, जाति, संप्रदाय और सामान्य और दलित वर्ग धेद पूर्णता समाप्त हो जाए,पर भरसक प्रयास के बाद भी ऐसा हो नहीं पाया हैद्य वर्तमान में भारत की सामाजिक आर्थिक विभिन्नता एवं विषमता देश के आर्थिक तथा वैश्विक छवि के लिए अवरोध साबित हो सकते हैं। देश में विभिन्न नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रीय संपत्ति की तोड़फोड़, आपसी असहमति में हत्याये देश के सर्वांगीण विकास के लिए अच्छे संकेत नहीं है। भारत को एक सशक्त आंतरिक नीति एवं सामाजिक सौहार्द की आवश्यकता है तब ही हम विकास के पथ पर आगे प्रशस्त हो सकते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में लगातार गरीबी उन्मूलन, कृषि विकास की योजनाएं, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, स्कूली एवं कॉलेज की शिक्षा, स्वास्थ्य की तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए बड़ी-बड़ी आर्थिक योजनाएं बनती रही हैं,पर न तो पूरी तरह योजनाओं में अमल हो पाया और ना ही भरपूर वित्तीय संसाधनों का सही-सही समुचित दोहन ही हो पायाद्य वैसे तो यह कल्पना की गई थी कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की सरकारें ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देकर शहर तथा गांव की सरहदों को मिटाने का प्रयास करेगी, हमारा लोकतांत्रिक ढांचा इतना समावेशी और मजबूत नहीं हो पाया कि हम देश के संपूर्ण विकास के लिए कटिबद्ध हो पाएद्य संसद, विधायिका और कार्यपालिका में तालमेल की कमी के कारण भारत में विकास कल्पना के अनुरूप मूर्त रूप नहीं ले पायाद्य हमें नवीन भारत की संकल्पना के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन प्रयास को बहुत सशक्त एवं दमदार बनाना होगाद्य केवल गरीबों को मुफ्त में अनाज देकर उनकी गरीबी दूर नहीं की जा सकती हैद्य गरीबों को अनाज देने के साथ-साथ उनके हाथों को काम और आजीविका के साधन भी देने होंगे, तब जाकर देश की स्थिति सुधर सकती हैद्य हमें गरीबी के अनेक स्वरूपों को जड़ से खत्म करना होगा। इसके लिए हमें पिछड़ी जाति, दलित, दिव्यांग,महिलाएं, गरीब बच्चे के लिए सर्वाधिक योजनाओं को महत्व देकर निशुल्क शिक्षा,रोजगार गारंटी तथा कौशल विकास तथा पारदर्शी स्वास्थ्य योजनाओं को हर पंचवर्षीय योजना में लागू किया जाना होगा, पर अब हर वर्ष नई नई योजनाएं बनाकर उस पर प्रभावी क्रियान्वयन कर गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता के तौर पर सफल बनाना होगाद्य यह सर्वविदित है कि सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से ही नवीन भारत का मार्ग प्रस्तुत हो सकता हैद्य भारतीय समाज में जातिवाद एक बड़े नासूर की तरह हम सबके समक्ष खड़ा हैद्य जात पात को खत्म करने के लिए स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात कई महान पुरुषों ने अपना जीवन लगा दिया था, जिनमें प्रमुख ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम उल्लेखनीय हैद्य इनके समुचित प्रयास के बाद भी जातिवाद को आज भी भारत में खत्म नहीं किया जा सका है,बल्कि यह बड़े रूप में सामने आए हैं एवं राजनीतिक समीकरण के कारण यह और उभर कर सामने आया हैद्य जिसका फायदा राजनीतिज्ञ अपने चुनाव के समय वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए उठाते हैंद्य 1947 के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1955 में सिविल अधिकार एक्ट लागू किया इसके बावजूद हालात जस के तस हैंद्य हमारा देश एक बहु धार्मिक सांस्कृतिक एवं विविधता वाला देश है द्य भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में माना जाता है। सांप्रदायिकता को रोकने के लिए संसद में अनेक संशोधन हुए हैं इसके बावजूद देश में धार्मिक सौहार्द बनाने में बहुत असफलताएं सामने आई है। यहां सांप्रदायिक दंगे भी हुए हैं, जिसे सरकार रोकने का भरसक प्रयास करती रही लेकिन सदैव उन्हें असफलता ही हाथ लगी हैद्य संप्रदाय, जाति प्रथा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तथा चर्च के विवाद के कारण ही सांप्रदायिकता सदैव खतरे में रही हैद्य सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के कई पहलुओं पर गहन चिंतन मनन भी किया गया पर इसमें बहुत बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है, सांप्रदायिकता के साथ जुड़ी हुई आतंकवाद की घटनाएं हुई इस संदर्भ में जोड़ी जाती रही हैद्य आतंकवाद, नक्सली समस्या केवल भारत देश की नहीं है यह अंतरराष्ट्रीय स्वरूप ले चुकी हैद्य भारत आतंकवाद से स्वतंत्रता के बाद से लगभग 73 वर्ष से इस समस्या से जूझ रहा है कश्मीर में आतंकवाद, झारखंड, बिहार,बस्तर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश,तेलंगाना में नक्सली समस्या अपना सिर उठा चुकी हैद्य हमारे परंपरागत दुश्मन वैसे तो पाकिस्तान और चीन है पर पाकिस्तान और तालिबान एक साथ मिलकर कश्मीर में आतंकवाद का तांडव मचाकर भारत में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उजागर भी किया हैद्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल से भारत को स्वच्छ निर्मल और स्वस्थ रखने की नई योजनाओं को लागू कर उस पर अमल करना शुरू किया है। स्वच्छ भारत भी एक अभियान की तरह भारत में प्रचलित हैद्य महात्मा गांधी की सदैव कल्पना रही है कि भारत स्वच्छ रहे और इसी कार्यक्रम में सरकार ने सभी शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने की योजना को तीव्र स्तर पर लागू भी किया हैद्य पर यह शत-प्रतिशत अनुपालन में नहीं आई हैद्य इसके अलावा भारत कई योजनाओं में एक साथ काम कर रहा है, जैसे चुनाव में संशोधन,श्रम कानूनों में सुधार, पंचायती राज में संशोधन, आर्थिक सशक्तिकरण तथा कार्यपालिका न्यायपालिका तथा विधायिका में सामंजस्य बनाने का प्रयास भी किया गयाद्य भारत में हर वर्ष बाढ़, सूखा तथा भूकंप के झटके भी महसूस किए जाते रहे और इस पर प्रभावी नियंत्रण लाने का प्रयास भी किया गया है। इसके लिए भी अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। कुल मिलाकर नवीन भारत की संकल्पना के साथ भारत में तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए अपनी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, तब जाकर भारत एक नवीन भारत की कल्पना को साकार रूप दे सकता है एवं विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बना सकता है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विधि तरीकों को यूज करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र हैं, जहां आपको विशेष कुशल लोगों और दूसरों सहयोग, आपकी विशेष कला से लाभ्रान्वित होना चाहिए। हम ने सिर्फ हमारी टीम में और सदैव खुशी को खुशबूदार तरह लाभकारक उर्जा की सम्पूर्ण वर्तमान, भविष्य पहलुओंसे संबंधों में लौ, जब यह लाभकारक हमें लाभ और कामदेव से लाभ प्रदान करेगा

मेष
अपने क्रोध को काबू में रखें। नए संबंध बनाने से पहले सोचें। धन खर्च ज्यादा होने से आर्थिक परेशानी का अनुभव होगा। आपका काम समय से पूरा नहीं होगा। खाने-पीने का ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता रहेगी।

वृष
आज बौद्धिक और तार्किक विचारों से आप कठिन काम भी आसानी से बना पाएंगे। समाज में सम्मान मिलेगा। उनके साथ घूमने-फिरने या मनोरंजन स्थल की यात्रा के योग हैं। अच्छे भोजन और सुंदर परिधान से आप का मन खुश रहेगा।

मिथुन
व्यवसाय में परेशानी खड़ी हो सकती है। संतान के प्रति चिंता होगी। दूर की यात्रा का आयोजन होगा। धार्मिक यात्रा के भी योग हैं। आज विरोधियों के साथ वाद-विवाद टालें। अभी समय शांतिपूर्वक व्यतीत करना लाभदायी होगा।

कर्क
कारीगर और कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। आज के दिन की शुरुआत तन-मन की ताजगी के साथ होगी। घर या कहीं बाहर दोस्तों तथा परिवार के लोगों के साथ मनपसंद खाना खाने का अवसर मिल सकता है। अनावश्यक जगह धन खर्च होगा।

सिंह
व्यापार में लाभ मिल सकता है। गृहस्थ जीवन में आनंद का माहौल रहेगा। परिवार में भी प्यार रहेगा। पिता की तरफ से लाभ मिलने के संकेत हैं। आज कार्यस्थल पर आपको अधिकारियों की नाराज़गी सहन करनी पड़ेगी।

कन्या
मित्रों का साथ अच्छा लगेगा। भागीदारी लाभदायक साबित होगी। व्यापार में विकास के लिए आज का दिन बहुत लाभकारी रहेगा। व्यापार में आप अपने आयोजन के अनुसार काम कर सकेंगे। धन के लेन-देन में भी सफलता मिलेगी। बौद्धिक चर्चा से आप जुड़े रहेंगे।

तुला
आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। अच्छा भोजन प्राप्त होगा। अभी आप सफलतापूर्वक नए कार्य कर सकेंगे। व्यापारी वर्ग और नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन लाभदायी है। उच्च अधिकारियों की कृपा दृष्टि से पदोन्नति की संभावना है।

वृश्चिक
विचारों में गतिशीलता से आज दुविधा का अनुभव होगा, जिससे किसी एक निर्णय पर नहीं आ सकेंगे। आज का दिन आप के लिए नौकरी, धंधे के क्षेत्र में स्पर्धा युक्त रहेगा और आप उसमें से बाहर आने की कोशिश करते रहेंगे।

धनु
आज किसी भी बात पर दृढ़ मन से निर्णय नहीं ले सकने के कारण आप मिले हुए मौके का फायदा नहीं उठा सकेंगे। विचारों में ही आपका मन अटका रहेगा। दोस्तों, खासकर महिला मित्रों से आपको लाभ मिलेगा। व्यापार में फायदा होगा।

मकर
आज आपका दुविधापूर्ण व्यवहार आपको मुश्किल में डाल सकता है। अपने जिद्दी स्वभाव को आज त्याग दें नहीं तो किसी के साथ चर्चा और विवाद में माहौल गर्म होने की आशंका बनी रहेगी। यात्रा की योजना आज पूरी नहीं होगी।

कुंभ
आर्थिक लाभ के योग हैं। मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना को प्रवेश न करने दें। सभी स्थिति में मन को काबू में रखें। परिवार का वातावरण भी ज्यादा अच्छा नहीं होगा। परिजनों के साथ मतभेद हो सकते हैं।

मीन
मन दुविधायुक्त रहेगा। वाणी पर संयम रखें। किसी के साथ वाद-विवाद या झगड़े में पड़ने से मामला खराब हो सकता है। बातों को स्पष्ट कर गलतफहमी दूर करने से बात जल्दी पूरी हो जाएगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। पाचन संबंधी कोई बीमारी आपको हो सकती है।

शख्सियत

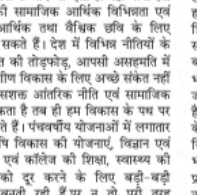

राकेश कुमार गुप्ता
(वरिष्ठ आर.ए.एस अधिकारी)

नमस्कार दोस्तों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के शानदार अधिकारी श्री राकेश कुमार गुप्ता । 1 जनवरी सन 1966 में जयपुर में जन्मे राकेश गुप्ता शुरू से ही होनहार रहे। उन्होंने एजुकेशन बी.कॉम की। इसके बाद 2013 में तहसीलदार सर्विस से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के लिए प्रमोट हुए।

तहसीलदार सेवा से आरएएस में पदोन्नत किया गया। सहायक कलेक्टर एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक थानागाजी अलवर। उपखण्ड अधिकारी, महुवा दौसा। उपखण्ड अधिकारी, खैरिसर नागौर। उपखण्ड अधिकारी, महुवा ,दौसा। उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता नागौर। प्राधिकृत अधिकारी, जेडीए जयपुर।उप आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर। उपायुक्त जेडीए, जयपुर। अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अलवर,द्वितीय। उप आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंच एवं पदेन उप सचिव, शासन, जयपुर। राज्य मंत्री के विशेष सहायक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मुद्रण एवं स्टेशनरी स्वतंत्र प्रभार शिक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक। कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, जयपुर श्रीमती जाहिदा खान ओएसडी एलए, रीको जयपुर और फिलहाल रजिस्टर शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर पद को सुशोभित कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन अधिकारी रहे श्री राकेश कुमार गुप्ता तहसीलदार सर्विसेस से अपने करियर की शुरुआत की 2021 में सरकार ने इन्हें डिप्टी डायरेक्टर सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट जयपुर के पद पर भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा। अलवर एडीएम पद के दौरान उनसे मुलाकात हुई और ऐसी हुई कि इन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह प्यार दिया। कोविड महामारी के दौरान मैंने काफी करीब से इनके द्वारा किए गए कार्यों को देखा। बड़ी तत्परता से काम किया खुद भी कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए, लेकिन उस भयावह दौर में हंसते मुस्कुराते समय पास किया। बोले यार जिन्दगी में इतने दिन कभी आराम नहीं किया शायद ईश्वर चाहते हैं कि कुछ समय परिवार के साथ बिताऊं। बेहद संवेदनशील व ऊर्जावान अधिकारी के स्वरूप में इन्हें जाना जाता है। बेहतरीन सोच के साथ सरकारी की योजनाओं को क्रियान्वित करना इनकी बेहद शानदार खूबी मानी जाती है। मुझे आज भी याद है रोटरी क्लब अलवर फोर्ट की ओर से गर्मी में टैंकर का शुभारंभ इनके द्वारा हरी झण्डी दिखाकर किया गया जब अध्यक्ष युवा समाजसेवी अभिषेक तनेजा थे। तो इन सभी युवाओं अपने चैंबर में बिठाकर इनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के लिए ना सिर्फ इन युवाओं की पीठ थपथपाई अपितु 15 अगस्त पर होनें वाले प्रशासकीय सम्मान की सिफारिश भी की। व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़े भाई का सानिध्य जीवन भर मिलता रहे बस ये कामना है। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है।

जय हिन्द
रूपक शर्मा

आज का इतिहास

21 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- आज ही के दिन ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने 1621 में सर एलेक्जेंडर स्टरलिंग को नोवा स्कॉशिया उपनिपेशीकरण का अधिकार पत्र दिया था।
- नीदरलैंड के जॉन और निकोल्स वान डर हेडेन ने 1677 में आज ही के दिन अग्निशामक यंत्र के लिए पेटेंट हासिल किया था।
- अमेरिका का पहली बार दैनिक अखबार (पेनसिलवेनिया पैकेट एंड जनरल एडवरटाइजर) 1784 में छपा।
- पालघाट ने 1790 में जनरल मेडोव के नेतृत्व में ब्रिटिश टुकड़ी के समक्ष 60 बंदूकों के साथ आत्मसमर्पण किया।
- किंग विलियम प्रथम ने 1815 को ब्रुसेल्स में शपथ ली।
- बहादुर शाह द्वितीय ने 1857 में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया।
- नीदरलैंड के लोगों ने 1885 को चुनावों में मतदान के अधिकार के लिये प्रदर्शन किया।
- 'अटलांटा लाइफ इंश्योरेंस' कंपनी 1905 को गठित हुई।
- 'माय विकली रीडर' मैगज़ीन की शुरुआत 1928 में हुई।
- चक्रवाती तूफान (183 मील प्रति घंटे की रफ्तार) से 1938 को न्यू इंगलैंड में 700 लोगों की मौत।
- नाज़ियों ने 1942 को यूक्रेन, डुनेवट्सी में 2588 यहूदियों की हत्या की।
- बोइंग बी-29 सुपरफोट्रेस ने 1942 को अपनी पहली उड़ान भरी।
- चीन में कम्युनिस्ट नेताओं ने 1949 में 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' पार्टी की घोषणा की जो चीन की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है।
- माल्टा ने 1964 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की।
- प्रसिद्ध भारतीय तैराक मिहिर सेन ने 1966 में आज ही के दिन बास्फोरस की खाड़ी को पार करके एक और कीर्तिमान अपने नाम किया।
- ब्रिटेन की शाही वायु सेना का एक विमान 1971 को कैम्ब्रिजशर शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक पुरुष और दो लड़कों की मौत हो गई।
- मध्य अफरीकी गणराज्य के तथाकथित सम्राट बोकासा सैनिक 1979 को क्रान्ति में अपदस्थ।
- ब्रूनेई संयुक्त राष्ट्र में 1984 को शामिल हुआ।
- अर्मेनिया को 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता मिली।
- अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की के प्रेम प्रकरण से संबंधित वीडियो टेप 1998 को जारी।

विशेष आलेख

अन्तर्राष्ट्रीय शांति दिवस

दुनिया में अमनचैन, अयुद्ध एवं शांति का उजाला हो

ललित गर्ग

अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितम्बर को मनाया जाता है। यह दिवस सभी देशों और लोगों के बीच स्वतंत्रता, अहिंसा, सह-जीवन, शांति और खुशी का एक आदर्श संकल्प माना जाता है। यह दिवस मुख्य रूप से पूरी पृथ्वी पर शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए मनाया जाता है। किंतु यह काफी निराशाजनक है कि आज इंसान दिन-प्रतिदिन इस शांति से दूर होता जा रहा है। आज चारों तरफ फैली राष्ट्रों की महत्वाकांक्षाएं एवं बाज़ारवाद ने शांति को व्यक्ति से और भी दूर कर दिया है। पृथ्वी, आकाश व सागर सभी अशांत हैं। स्वार्थ और घृणा ने मानव समाज को विखंडित कर दिया है। यूँ तो विश्व शांति का संदेश हर युग और हर दौर में दिया गया है, लेकिन इसको अमल में लाने वालों की संख्या बेहद कम होती जा रही है। इसलिए विश्व के सभी देशों एवं विशेषत: विकसित एवं शक्तिसम्पन्न देशों को उदार एवं दूरगामी नजरिया अपनाना होगा। अपने-अपने स्वार्थों को नजरअंदाज करते हुए विश्व मानवता को केन्द्र में रखना होगा है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस-2024 की थीम है शांति की संस्कृति का विकास। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शांति की संस्कृति पर घोषणा और कार्यक्रम को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ है ।

आज दुनियाभर में जो युद्ध चल रहे हैं, उनकी वजह से शांति खतरे में हैं। रूस-यूक्रेन और इस्राइल-गाजा का लम्बे दौर से चल रहा युद्ध शांति की बड़ी बाधा है। युद्धों का मानव जीवन, पर्यावरण एवं विकास पर सबसे घातक असर पड़ रहा है और यही जलवायु परिवर्तन का बड़ा कारण भी बन रहा हैं जो शांतिपूर्ण जीवन को संभव नहीं होने देता। दुनिया में अनेक ऐसे विध्वंसक देश हैं, जो आतंकवाद, युद्ध एवं पड़ोसी देशों में अशांति फैलाने की राहों को चुनते हुए अपनी बर्बादी के साथ अन्य देशों में अशांति की कहानी लिख रहे हैं। पाकिस्तानी नेतृत्व ने भारत में आतंकवाद फैला कर लिखी अपनी बर्बादी की दास्तां, जिसे अब उसकी खुद की जनता झेल रही है। भारत शांतिप्रिय देश है, वह खुद शांति चाहता है और दुनिया में शांति की स्थापना के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहा है। शांति, अहिंसा , अयुद्ध एवं अमनचैन की भारत की नीतियों को देर से ही सही दुनिया ने स्वीकारा है। भारत की ऐसी ही मानवतावादी एवं सहजीवन की भावना को बल देने के कारण ही दुनिया एक गुरु के रूप में भारत को सम्मान देने लगी है। भारत आतंकवाद, हिंसा-युद्धयुक्त संसार और विस्तारवाद की भूख के खिलाफ जो सवाल उठाता रहा है, उसे अनेक देशों में न सिर्फ विचार के लिए जरूरी समझा जाने लगा है, बल्कि अब उन पर स्पष्ट रुख भी अख्तियार किया जा रहा है। शांति का उजाला फैलाने के उद्देश्य से विश्व शांति दिवस की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। इस दिवस को कोरा आयोजनात्मक न मनाया जाकर प्रयोजनात्मक रूप से मनाने की आवश्यकता है। सम्पूर्ण विश्व में शांति कायम करना आज संयुक्त राष्ट्र का मुख्य लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में भी इस बात का स्पष्ट

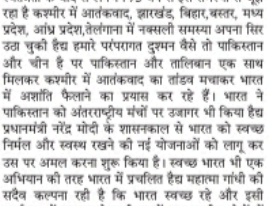

उल्लेख है कि अंतरराष्ट्रीय संघर्ष को रोकने और शांति की संस्कृति विकसित करने के लिए ही यूएन का जन्म हुआ है। संघर्ष, आतंक और अशांति के इस दौर में अमन की अहमियत का प्रचार-प्रसार करना बेहद जरूरी और प्रासंगिक हो गया है। इसलिए संयुक्त राष्ट्रसंघ, उसकी तमाम संस्थाएँ, गैर-सरकारी संगठन, सिविल सोसायटी और राष्ट्रीय सरकारें प्रतिवर्ष शांति दिवस का आयोजन करती हैं। शांति का संदेश दुनिया के कोने-कोने में पहुँचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कला, साहित्य, सिनेमा, संगीत और खेल जगत की विश्वविख्यात हस्तियों को शांतिदूत भी नियुक्त कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तीन दशक पहले यह दिन सभी देशों और उनके निवासियों में शांतिपूर्ण विचारों को सुदृढ़ बनाने के लिए समर्पित किया था। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व में शांति और अमन स्थापित करने के लिए पाँच मूल मंत्र दिए थे, इन्हें पंचशील के सिद्धांत भी कहा जाता है। ये पंचसूत्र मानव कल्याण तथा विश्व शांति के आदर्शों की स्थापना के लिए विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में पारस्परिक सहयोग के पाँच आधारभूत सिद्धांत हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पाँच सिद्धांत निहित हैं-एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई न करना। एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना। समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। भारत पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्व शांति, अहिंसा एवं युद्धमुक्त विश्व संरचना के लिये प्रयासरत है। यूक्रेन-रूस एवं इस्राइल-गाजा में शांति का उजाला करने, अभय का वातावरण, शुभ की कामना और मंगल का फैलाव करने के लिये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत शांति प्रयास करने में जुटा है। एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जो अपने आध्यात्मिक तेज एवं अहिंसा की शक्ति से मनुष्य के भयभीत मन को युद्ध की विभीषिका से मुक्ति दे सकता। विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में हर देश में जगह-जगह सफ़ेद रंग के कबूतरों को उड़ाया जाता है, जो कहीं ना कहीं भारत के शांति के ही सिद्धांतों को दुनिया तक फैलाते हैं। इन कबूतरों को उड़ाने के पीछे एक शायर का निम्न शेर बहुत ही विचारणीय है-लेकर चलें हम पैगाम भाईचारे का, ताकि व्यर्थ खून न बहे किसी वतन के रखवाले का। आज कई लोगों का मानना है कि विश्व शांति को सबसे बड़ा खतरा साम्राज्यवादी आर्थिक और राजनीतिक चालों से है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हवामपुरा रोड़ खातूवाला,निवाई रोड़ (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतिक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पालीवाल । प्रधान संपादक-राव बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 रोड़क कार्यालय-बाईपास निवाई, रोड़क फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com "पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

हिन्दुस्तान
1936

प्रसादम से खिलवाड़

तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में बनने-मिलने वाले लड्डू प्रसादम से खिलवाड़ का मामला जितना दुखद है, उतना ही शर्मनाक भी। यह और भी गंभीर बात है कि स्वयं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये आरोप लगाए हैं। आरोप के अनुरूप ही प्रसादम में पशु वसा का समावेश पाया जाना किसी अक्षम्य अपराध से कम नहीं है। पशु वसा से युक्त मिलावटी घी ने मंदिर की पवित्रता को कितना प्रभावित किया है, यह अलग गहरा प्रश्न है, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कौन लोग हैं, जिन्हें पवित्रता की परवाह नहीं है। और तो और, मंदिर ट्रस्ट ने भी प्रसादम से खिलवाड़ और मिलावट की पुष्टि की है। देश के एक पवित्रतम श्रद्धा केंद्र तिरुपति मंदिर का प्रबंधन करने वाली संस्था तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने कहा है कि घी के आपूर्तिकर्ताओं ने मंदिर में गुणवत्ता जांच की सुविधा न होने का फायदा उठाया है। अब सवाल उठता है कि मंदिर प्रबंधन की सफाई या स्वीकारोक्ति को कितनी गंभीरता से लिया जाए? क्या मंदिर प्रबंधन को अपराध की गंभीरता का अंदाजा है? क्या मंदिर प्रबंधन को मंदिर की पवित्रता का अनुमान है?

कोई संदेह नहीं कि प्रथम दृष्टया मंदिर प्रबंधन दोषी है। जो मंदिर प्रतिदिन तीन लाख लड्डू बेचकर सालाना 500 करोड़ रुपये तक लाभ कमाता है, वह क्या इतना सक्षम नहीं कि गुणवत्ता जांच के लिए एक किफायती प्रयोगशाला ही बना ले? मंदिर प्रबंधन के पास न तो अपनी जांच सुविधाएं हैं और न वह जांच कराने का इच्छुक था? देश के संपन्नतम मंदिरों में शुमार यह तीर्थ अगर गुणवत्ता से समझौता कर रहा है, तो देश के बाकी मंदिरों में क्या हो रहा होगा, अंदाजा लगाकर देखिए। मंदिर भगवान भरोसे चल रहे हैं, पर धंधा करने वालों की श्रद्धा न तो भगवान के प्रति है और न भक्तों के प्रति। वे तमाम मंदिर, जो अपने यहां से प्रसाद वितरित करते हैं या बेचते हैं, उन सभी को गुणवत्ता जांच की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। यह अफसोस की बात है कि मंदिरों में बाहर से चढ़ने वाला प्रसाद तो पहले से ही संदेह के दायरे में रहा है, पर अगर मंदिर की अपनी रसोई में तैयार होने वाले प्रसाद की भी विश्वसनीयता आहत हुई है, तो यकीन मानिए, विश्वास बहाली में वक्त लगेगा। दोषियों को बचाने या अपराध छिपाने से काम नहीं चलेगा, तमाम मंदिरों को गुणवत्ता जांच से गुजरना पड़ेगा। गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले अधिकारियों के लिए यह युद्ध स्तर पर काम करने का समय है।

संपन्नतम मंदिरों में शुमार तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में पशु वसा का समावेश किसी अक्षम्य अपराध से कम नहीं है। दोषियों को सजा ऐसी मिले कि मिसाल बन जाए।

बहरहाल, तिरुपति में लड्डुओं का वितरण तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। अशुद्ध मिलावटी आपूर्ति के लिए जिम्मेदार ठेकेदार को काली सूची में डालना और उस पर जुर्माना लगाना ही पर्याप्त नहीं है। मिलावट विरोधी कानूनों के सबसे कड़े प्रावधान उस पर लागू होने चाहिए और सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि मिसाल बन जाए। यह कार्य स्वयं मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को सुनिश्चित करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहरा देना पर्याप्त नहीं है। लोगों को संयम रखना चाहिए। इधर धर्म के नाम पर भड़काने वाले या धर्म के प्रति दिखावटी सजगता दिखाने वालों की बड़ी भीड़ है, उसमें आंध्र प्रदेश की सरकार में शामिल नेता-अभिनेता पवन कल्याण का भी नाम शामिल है। भावनाओं से खेलने के बजाय शासकों को शासन-प्रशासन के जरिये सुनिश्चित करना होगा कि शुद्धता-गुणवत्ता केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि तमाम जगहों और उत्पादों में बहाल रहे।

हिन्दुस्तान Sindustan | 75 साल पहले 21 सितंबर, 1949

जयन्ती पखवाड़ा

गांधी जयन्ती पखवाड़ा प्रारम्भ हो गया है। हिन्दी तिथियों के मुताबिक गांधीजी का जन्मदिन इस वर्ष १९ सितम्बर था और अंग्रेजी तारीख तो २ अक्तूबर है ही। इस तरह गांधी जयन्ती मनाने के लिए हमको पूरा पखवाड़ा मिल जाता है। गांधीजी आज हमारे बीच में शरीर रूप में विद्यमान नहीं हैं, किन्तु उन्होंने अपने जीवन में हमको जो कुछ सिखाया, वह तो हमारा हमेशा ही मार्गदर्शन करेगा। गांधीजी जैसे महापुरुष को पाकर हम धन्य हुए हैं। उन्होंने न केवल इस देश को, बल्कि सारे संसार को प्रकाश का नया मार्ग दिखाया है। अतः इस पखवाड़े में उनके महान व्यक्तित्व के प्रति सारे जगत में श्रद्धांजलियां अर्पित की जायेंगी। फिर भला भारतवासी कैसे पीछे रहेंगे? उन्हें तो स्वयं गांधीजी की शिक्षाओं पर चलकर सारी दुनिया के आगे एक नया आदर्श प्रस्तुत करना है।

राजेन्द्र बाबू ने कहा है कि हम गांधीजी की शिक्षाओं को छोड़ते जा रहे हैं। इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। यदि हम स्वयं भटक गये तो भला दूसरों को क्या मार्ग दिखा पायेंगे? अतः हम इस पखवाड़े में गांधीजी की शिक्षाओं के प्रति अपनी श्रद्धा को फिर से जीवित करें। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने जो रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, उस कार्यक्रम को पूरा करने में सभी हाथ बढ़ा सकते हैं। गांधीजी को इसकी चिन्ता न थी कि लोग उनकी जयन्ती मनायें। वह तो लोकस्तुति को नापसन्द करते थे। किन्तु साथ ही वह व्यावहारिक भी कम न थे। उन्होंने लोगों की भावनाओं को रचनात्मक कामों की ओर मोड़ दिया। उन्होंने जयन्ती को चर्खा-प्रचार का साधन बना दिया। चर्खा सर्वोदय की नई समाज व्यवस्था का प्रतीक है और जो सत्य और अहिंसा के जरिए उस व्यवस्था को सम्भव बनाने की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें चर्खा और चर्खे की विचारधारा का अधिक से अधिक प्रसार करना चाहिए। हरिजन सेवा, साम्प्रदायिक एकता आदि रचनात्मक कार्यक्रम के अन्य अंगों को भी आशा है देशवासी पुष्ट करेंगे और इस प्रकार देश में सही अर्थों में गांधीजी की कल्पना के रामराज्य को निकट लाने में सहायक होंगे। यही हम सबकी गांधीजी के प्रति सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी।

'एक देश एक चुनाव' का मुद्दा इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस पर एनडीए बहुत पहले से ही दृढ़ है, जबकि विपक्षी दल एकरूपता लाने की इस कोशिश का विरोध कर रहे हैं। चल रही बहस व अनुकूल-प्रतिकूल टिप्पणियां इशारा हैं कि एक देश एक चुनाव कराना आसान नहीं होगा।

आमने-सामने

साथ चुनाव से धन और समय की बचत होगी

गौरव वल्लभ | प्रोफेसर व भाजपा नेता

- यह लोकतंत्र को सुव्यवस्थित करने के साथ ही प्रेरणा का काम करेगा।
- लगातार चुनाव के चलते दल शासन के बजाय चुनाव पर ध्यान देते हैं।
- भारत जैसे विविधतापूर्ण और गतिशील राष्ट्र में यह सुधार वांछनीय है।

लोकतांत्रिक मूल्यों का आधुनिक आदर्श भारत एक महत्वपूर्ण सुधार की दहलीज पर खड़ा है- एक देश एक चुनाव। एक ऐसे राष्ट्र के रूप में, जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए मानदंड स्थापित किए हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस बात पर विचार करें कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणालियों की प्रभावशीलता, समानता और स्थिरता को कैसे बेहतर बनाया जाए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चुनाव जरूरी हैं, पर उन्हें देश के राष्ट्रीय विकास के एजेंडे की सेवा करनी चाहिए, न कि इसमें बाधा डालनी चाहिए। एक साथ चुनाव भारतीय शासन की पूरी क्षमता को 'अनलॉक' करेगा। यह हमारे लोकतंत्र को सुव्यवस्थित करने के साथ ही प्रेरणा का काम कर सकता है।

अभी होता यह है कि देश लगातार चुनाव अभियान की मुद्रा में रहता है, जिसमें राजनीतिक दल शासन के बजाय चुनावी रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक साथ चुनाव कराने का सबसे बड़ा लाभ यह भी है कि वित्तीय बचत होगी। यह भारत जैसे विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां बार-बार होने वाले चुनावों से बचाए गए धन का उपयोग बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर तरीके से किया जाता है। लोकतांत्रिक सिद्धांत की मांग है कि सार्वजनिक धन का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए और एक साथ चुनाव कराना उस दिशा में एक कदम है।

चुनावों के समन्वय से एक अधिक स्थिर राजनीतिक माहौल बनेगा, जिससे कंपनियां हर कुछ महीनों में संभावित नीतिगत बदलावों के खिलाफ अपने दांव को सुरक्षित रखने के बजाय विकास और विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। कंपनियां आश्वस्त होकर योजना बना सकेंगी। इसके अलावा, चुनावों का निरंतर चक्र अक्सर महत्वपूर्ण नीतियों के क्रियान्वयन को मुश्किल बना देता है। विकास की पहल अक्सर रुक जाती है, और सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक गति खो जाती है। एक साथ चुनाव इन रुकावटों को कम कर देंगे, जिससे शासन अपने कार्यकाल की अवधि के दौरान विकास और शासन पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा।

एक साथ चुनाव कराने से मतदान को भी बढ़ावा मिलेगा, जो किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। चूंकि जनता एक समय में व्यापक पैमाने पर निर्णय ले रही होगी, इसलिए राजनीतिक दलों को स्थानीय और राष्ट्रीय, दोनों मुद्दों को संबोधित करने वाले अधिक गहन अभियान चलाने की जरूरत होगी। एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय दलों को स्थानीय मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मतदाता अधिक विचारशील और सुविचारित निर्णय लेंगे, इससे भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा।

ब्राजील, फिलीपींस सहित अनेक देशों ने एक साथ चुनाव कराने के कुछ तरीके अपनाए हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह मॉडल व्यावहारिक और प्रभावी है। इन देशों ने एक साथ कई स्तरों पर चुनाव कराने के लाभ देखे हैं, जिसमें कम लागत, मतदान में वृद्धि और अधिक कुशल शासन शामिल है। भारत अपने विशाल मतदाताओं और जटिल राजनीतिक परिदृश्य के साथ, ऐसी प्रणाली से और भी अधिक लाभ उठा सकता है। यद्यपि एक देश एक चुनाव योजना में कठिनाइयां हैं, पर उन्हें दूर करना होगा। समवर्ती चुनाव सरकार को सरल बनाएंगे और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाएंगे। सरकारें लगातार अगले चुनाव के लिए प्रचार करने के बजाय लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र होंगी। भारत जैसे विविधतापूर्ण और गतिशील राष्ट्र में यह सुधार वांछनीय है।

इस क्रांतिकारी विचार को अपनाकर भारत एक पूर्ण विकसित देश बनने की दिशा में एक कदम बढ़ा सकता है, जहां शासन ज्यादा प्रभावी और उत्तरदायी होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

लोगों की परेशानी और खर्च में होगा इजाफा

सुप्रिया श्रीनेत | वरिष्ठ पत्रकार, सोशल मीडिया, कांग्रेस

- देश के गौरवशाली संघीय ढांचे पर प्रहार की खतरनाक कोशिश है।
- यह कहना गलत कि बार-बार चुनाव से नीति निर्माण में समस्या होती है।
- सरकार हर चीज में एकरूपता ढूंढ़ती है। विविधता में कमजोरी देखती है।

एक देश एक चुनाव नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा छोड़ा गया जितना बड़ा शिगूफा है, उससे कहीं ज्यादा भारत के गौरवशाली संघीय ढांचे पर प्रहार करने की खतरनाक कोशिश है। उसे पता है कि संशोधन तभी पास हो पाएगा, जब लोकसभा में इसके पक्ष में 362 सांसद वोट करेंगे। अभी पूरा एनडीए मिलाकर 293 सांसद ही हैं। कमोबेश एनडीए की यही हालत राज्यसभा में भी है।

मगर सत्ताधारी मंडली को देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोई न कोई मुद्दा तो चाहिए ही। इसलिए सरकार एक देश एक चुनाव का राग बेवजह अलाप रही है। उसे पता है कि हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में उनकी बुरी हार होने जा रही है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, रेल दुर्घटनाएं, बेलगाम अपराध समेत तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को चर्चा से बाहर करने के लिए भाजपा को एक देश एक चुनाव याद आ रहा है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि मौजूदा तंत्र जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र व झारखंड के चुनाव ही एक साथ नहीं करा पा रहा है। एक देश एक चुनाव के लिए बनी समिति की निष्पक्षता और पवित्रता पर भी दर्जनों सवालिया निशान हैं। इस समिति में राष्ट्रपति पद पर सुशोभित रही विभूति का शामिल होना मर्यादित नहीं है। इस समिति में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल नहीं किया गया है। समिति में गुलाम नबी आजाद रहे, जो संसद के किसी सदन के सदस्य तक नहीं हैं। इसके अलावा इस समिति में कई और सदस्य ऐसे भी हैं, जिनका होना विवादास्पद है। समिति ने 18,626 पन्ने की रिपोर्ट तो पेश कर दी है, मगर प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं लिखा कि जब पंचायत और विधानसभा-लोकसभा का चुनाव एक साथ नहीं होगा, तो किस बात का एक देश एक चुनाव? इसमें कहा गया है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे, जबकि पंचायत चुनाव इसके 100 दिन बाद होंगे। मतलब, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के 100 दिन बाद फिर मतदान केंद्र बनेंगे, फिर मतदान दल बनेगा, फिर से चुनाव का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा और इसका खर्च भी जनता को ही देना पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया में अर्धसैनिक बल के जवानों, प्रशासनिक और पीठासीन अधिकारियों, पुलिस बल समेत 1.5 करोड़ लोग फिर से लगेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में तीन गुना वीवीपैट, तीन गुना ईवीएम की जरूरत होगी। जाहिर है, इसमें अधिक समय और धन का दुरुपयोग होगा।

रिपोर्ट से यह भी बात साफ हो जाती है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां की सरकारों का कार्यकाल 5 वर्ष की बजाय 2029 के लोकसभा चुनाव तक ही होगा। तब तक तकरीबन 17 राज्य सरकारें ऐसी होंगी, जिनका 2 से 3 साल तक का कार्यकाल शेष रहेगा। ऐसी हालत में उनको भंग कैसे किया जा सकता है? यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि अगर कोई राज्य सरकार गिर जाती है, तो वहां चुनाव होगा, तब तक के लिए ही होगा, जब तक लोकसभा का कार्यकाल होगा। अगर केंद्र सरकार गिर जाती है, तो क्या सभी राज्य सरकारों को भी भंग कर दिया जाएगा?

सरकार की यह भी दलील है कि देश में बार-बार चुनाव होने की वजह से नीति निर्माण में समस्या होती है। विकास कार्यों में खलल पड़ता है। जो सरकार 5 साल में 4 साल 11 महीने काम नहीं कर सकती, उसकी तरफ से यह दलील फिजूल है। वस्तुतः यह सरकार हर चीज में एकरूपता ढूंढ़ती है। कभी एक देश एक चुनाव, कभी एक देश एक भाषा, कभी एक देश एक रंग, एक देश एक संस्कृति। दरअसल, भाजपा एक देश एक राष्ट्रीय दल, एक नेता के सूत्र पर काम कर रही है। उसे देश की विविधता में ताकत नहीं, अपनी कमजोरी नजर आती है। खैर, ये प्रोपेगेंडा नया नहीं है और देश भी इस स्वांग को खूब समझता है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

स्पेस स्टेशन पर सुनीता विलियम्स का संघर्ष एक संदेश

मनीष मोहन गोरे | सीएसआईआर से जुड़े वैज्ञानिक

आठ दिन की योजना के साथ 'इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन' पहुंचने के बाद जब यह पता चले कि पृथ्वी पर लौटने के लिए अब महीनों इंतजार करना होगा, तो यह किसी के लिए आसान परिस्थिति नहीं होती।

उन्नीस सितंबर को भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना जन्मदिन पूरे उत्साह और उमंग से मनाया। हालांकि, पिछले कुछ महीने से मीडिया की खबरों को देख और पढ़कर दुनिया भर के लोग सुनीता और उनके सह-अंतरिक्ष यात्री बुच विलमोर को लेकर काफी चिंतित हैं। चिंता के मूल में यह बात है कि दोनों कई महीनों के लिए अंतरिक्ष में फंस गए हैं। 5 जून को जब अमेरिका से ये दोनों स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे, तब इन्हें केवल आठ दिन का अंतरिक्ष अन्वेषण करके वापस लौटना था, लेकिन वाहक अंतरिक्ष यान में कुछ तकनीकी खामी आने की वजह से नासा ने उसको बैरंग वापस बुला लिया और दोनों यात्रियों को वहीं रुक जाना पड़ा। यह सही फैसला था, क्योंकि 2003 में ऐसी ही तकनीकी खामी के कारण अंतरिक्ष से वापसी के दौरान हमने कल्पना चावला को खो दिया था।

बहरहाल, 58 वर्षीया सुनीता विलियम्स पूरी दुनिया के अंतरिक्ष विज्ञानियों और विज्ञान प्रेमियों के लिए किसी प्रेरक से कम नहीं हैं। उनका उत्साह देखकर हमें यकीन करना ही होगा कि वह एक अंतरिक्ष योद्धा हैं। आठ दिन की यात्रा-योजना के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद जब यह पता चले कि पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए अब करीब आठ-नौ महीने का इंतजार करना होगा, तो यह किसी के लिए भी आसान परिस्थिति नहीं होती। वह भी तब, जब अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर दिक्कतें पैदा होने का खतरा अधिक रहता है। ऐसे में, यह देखना सुखद है कि सुनीता भावनात्मक रूप से काफी सशक्त हैं और उनके अंदर अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर इतनी अदम्य ऊर्जा व उत्साह है कि वह न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन कर रही हैं, बल्कि वहां से आने वाले उनके वीडियो भी दिखाते हैं कि वह तनाव-मुक्त और जिंदादिल होकर इन दिनों का भरपूर आनंद ले रही हैं। हां, अपने परिजनों, दोस्तों, सुबह की सैर और चिड़ियों की चहचहाहट वह जरूर कभी-कभी मिस करती हैं, जैसा कि उन्होंने खुद एक वीडियो में बताया है।

सुनीता का जन्म बेशक ओहियो (अमेरिका) में हुआ, लेकिन वह दिल से एक सच्ची भारतीय हैं। 2007 में वह भारत आई थीं। उन्होंने अपने जीवन के 300 से अधिक दिन अंतरिक्ष यात्रा में बिताए हैं और कई महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किए हैं। अभी वह एक्सपेडिसन-71 के अंतरिक्ष यात्रियों के अनुसंधान में मदद कर रही हैं। उनकी अब तक की यात्रा भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों समेत युवाओं, विज्ञान के शोधार्थियों और खासतौर पर अनुसंधान में आगे बढ़ने का सपना देख रही करोड़ों बालिकाओं के लिए एक प्रेरणा-स्रोत है।

वास्तव में, यह इसलिए भी संभव हो सका है, क्योंकि अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के पास एक समृद्ध विरासत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 1969 में अपनी स्थापना के बाद से निरंतर नवीन उपलब्धियां हासिल की हैं। विगत 15 वर्षों के दौरान अंतरिक्ष अनुसंधान, इससे जुड़े तकनीकी विकास (विशेष रूप से स्वदेशी तकनीक) और अंतरिक्ष प्रक्षेपण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत पूरी दुनिया के सामने एक सशक्त देश बनकर उभरा है। मंगलयान, चंद्रयान और आदित्य मिशन सरीखे अभियानों को हमने सफलतापूर्वक संपन्न किया है। हमें याद रखना होगा कि भारत पिछले वर्ष 23 अगस्त को चंद्रमा के दुर्गम दक्षिणी ध्रुव पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बना है। बेशक, हमने अब तक मानव मिशन नहीं किया है, लेकिन दिसंबर 2024 में इसरो गगनयान अभियान के जरिये अंतरिक्ष में मानवरहित यान भेजने के लिए संकल्पित है। ऐसे में, भविष्य के गर्भ में ऐसे अनेक अंतरिक्ष अभियान भारत के वैज्ञानिक सपने हैं, जो विश्व पटल पर देश का नाम रोशन करेंगे ही, भारतीय और भारतवंशी, दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के सपने को नए पंख भी देंगे।

वह अच्छी खबर है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अटके दोनों यात्री अगले साल फरवरी में पृथ्वी पर वापस आ सकते हैं। इसके लिए क्रू-9 मिशन भेजा जाएगा। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी सभी चाहते हैं, पर इस बीच वह जिस जीवटता का परिचय दे रही हैं, वह नजीर के तौर पर हमें अनवरत प्रेरित करेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

स्वीकार और प्रतिरोध

सब कुछ जो तुम्हें मिल रहा है, तुम उनको स्वीकार करते हो या उनका प्रतिरोध करते हो? यदि तुम प्रतिरोध नहीं कर सकते, तो स्वीकार भी नहीं कर सकते! सभी चीजों को तुम स्वीकार नहीं कर सकते और न ही सबका प्रतिरोध।

मन में आने वाले सभी विचारों को तुम स्वीकार नहीं करते। जब तुम किसी विचार को स्वीकार करते हो, तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें अच्छा लगा और तुम उसके अनुसार कार्य करते हो। याद रहे, मन में उठने वाले सभी विचारों के अनुसार यदि तुम कार्य करोगे, तो तुम पागलखाने में पहुंचोगे या जेल में। इसलिए कुछ विचारों का तुम प्रतिरोध करते हो या उन पर ध्यान नहीं देते और कुछ दूसरे विचारों का स्वागत करते हो। जीवन में विवेचना की आवश्यकता है। स्वीकार और प्रतिरोध जीवन के अंग हैं। विस्तार और उन्नति के लिए स्वीकृति जरूरी है, पालन-पोषण के लिए प्रतिरोध आवश्यक है।

तुम्हारे मन में प्रश्न उठता होगा कि जिसका प्रतिरोध करते हैं, वह तो और दृढ़ होता जाता है? जुकाम का प्रतिरोध करने पर जुकाम टिकता नहीं। यदि तुम्हारे शरीर में कोई प्रतिरोधक ही न हो, तो तुम जीवित नहीं रह सकते। तुम्हारा शरीर कुछ चीजों का प्रतिरोध करता है और कुछ का स्वागत। प्रतिरोध जहां कमजोर होता है, स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है, विरोध बना ही रहता है। प्रबल प्रतिरोध विरोध को मिटाता है। प्रबल प्रतिरोध से शक्ति, समता, शौर्य और समाधि की प्राप्ति होती है। यह तुममें एक योद्धा की शक्ति लाता है। कुछ भी तुम्हें प्रलोभित नहीं कर सकता, कोई बाधा रोक नहीं सकती। जहां पूर्ण स्वीकृति हो या प्रबल प्रतिरोध, वहां विजय बिना संघर्ष के प्राप्त होती है।

श्री श्री रविशंकर

अमित शाह | केंद्रीय गृह मंत्री

पेजर विस्फोट का दूरगामी तकनीकी महत्व

जिस भी राष्ट्र या संस्था ने लेबनान में पेजर का प्रयोग एक विस्फोटक के रूप में किया हो, इसका महत्व अत्यधिक दूरगामी है। कारण यह है कि सेलफोन आने के बाद पेजर का प्रयोग लगभग समाप्त हो चुका है। पेजर के लिए सेलफोन का नेटवर्क प्रयोग नहीं करना पड़ता। इस पर संचार रेडियो की वेरी हाई फ्रीक्वेंसी द्वारा संचालित होता है और ऐसा रेडियो ट्रांसमीटर किसी भी कमरे में सेट किया जा सकता है। अतः पेजर को एफएम रेडियो की तरह एक सीमित, लेकिन वृहद रेंज में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक निर्धारित फ्रीक्वेंसी का चुनाव किया जाता है और पेजर को उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर देते हैं। पेजर के रेडियो ट्रांसमीटर की लोकेशन एवं फ्रीक्वेंसी को समय-समय पर बदलने से इसके मैसेज को 'पकड़ना' कठिन हो जाता है। यही कारण है कि किसी छोटी 'संस्था' और क्षेत्र के लिए पेजर तकनीक उपयुक्त मानी जाती है।

लेबनान के जिस क्षेत्र से हिज्बुल्लाह ऑपरेट करता है, वहां के लिए इसे एक उपयुक्त उपकरण माना जाता है। कहा जाता है कि हिज्बुल्लाह के 'कार्यकर्ता' एक सामान्य नागरिक के रूप में रहते हैं। वे बैंकों, स्कूलों, दुकानों आदि में काम करते हैं, फल-तरकारी बेचते हैं, टैक्सी चलाते हैं, यानी आम आदमी को पता ही नहीं होता कि उनके बीच में कोई हिज्बुल्लाह का काडर है। हमलावर राष्ट्र या संस्था को हिज्बुल्लाह के अधिकतर 'नेतृत्व' के बारे में जानकारी है, लेकिन प्रमुख काडर के बारे में अंधकार था। पेजर के विस्फोट का प्रभाव केवल हिज्बुल्लाह के काडर पर पड़ा है। हुआ यह कि विस्फोट के तुरंत बाद सामान्य फोन नेटवर्क, सोशल मीडिया, अस्पताल इत्यादि द्वारा या तो दर्शक या फिर काडर स्वयं मदद मांगने लगे; अपने परिचितों से संपर्क करने लगे। ओपन नेटवर्क पर ऐसी सारी बातचीत को संबंधित 'संस्था' सुन रही थी और निगरानी कर रही थी। जब तक काडर यह समझ पाते, तब तक देर हो चुकी थी। माना जा रहा है कि एक ही झटके में हिज्बुल्लाह के सभी काडरों की जानकारी उस 'संस्था' को मिल गई है।

बहरहाल, हिज्बुल्लाह के लिए अब किसी भी तकनीकी उपकरण पर विश्वास करना या उसका प्रयोग करना दुरूह हो जाएगा। यही पेजर विस्फोट का दूरगामी महत्व है। ऐसी किसी भी हिंसा को कड़ी निंदा ही की जाएगी, क्योंकि हिंसा का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। मगर यह घटनाक्रम बताता है कि सुरक्षित से सुरक्षित उपकरणों के भी अपने खतरे हैं। यह युद्ध का एक नया स्वरूप है। जाहिर है, अब सभी देश इस दिशा में सोचेंगे। कुछ देश तो निस्संदेह इस पर काम कर ही रहे हैं।

अमित सिंघल, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

तकनीक से हमला

ऐसे तो प्रौद्योगिकी से भरोसा उठ जाएगा

लेबनान से विस्फोट की जो खबर आई है, वह हैरतंगेज है। पेजर का प्रयोग टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए किया जाता है, पर वहां इसे एक बम के रूप में इस्तेमाल किया गया और एक के बाद दूसरे पेजर विस्फोट से कई लोगों की जान ले ली गई। पेजर ही नहीं, वॉकी-टॉकी में भी अचानक धमाके हुए। खबरों के मुताबिक, ये सभी हमले हिज्बुल्लाह कमांडरों के खिलाफ हुए हैं, लेकिन यह घटना एक बड़ी चिंता की ओर भी इशारा कर रही है। अगर तकनीक का इस तरह दुरुपयोग किया जाएगा, तो कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह सकेगा। अब तो हर हाथ में मोबाइल है और इसे पेजर की तुलना में कहीं आसानी से हैक किया जा सकता है। इस तरह, हमारे-आपके लिए बहुपयोगी मोबाइल अब जिंदा बम ही माना जाएगा। जाहिर है, यह पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए और उसको मिलकर इसे रोकने की दिशा में काम करना चाहिए। वैसे भी, जब पेजर को बम में बदला जा सकता है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्यों नहीं संहार के कामों में इस्तेमाल हो सकते हैं?

हमने हाल-फिलहाल देखा भी है कि जिस तकनीक को मानव विकास के लिए काफी अहम माना गया, उसके साथ ही खिलवाड़ हुए। जैसे, चौन बार-बार हम पर साइबर हमला करता रहता है। विदेश की एक निजी खुफिया एजेंसी ने बताया भी था कि चीन के हैकर्स ने लद्दाख के करीब बिजली केंद्रों पर हमला किया। यह तो अच्छा है कि हमारा सुरक्षा कवच इतना मजबूत है कि उसके हमले हम पर शायद ही असरदार हो पाते हैं। मगर इन सबसे साफ है कि आतंकवाद का रूप अब बदल गया है। अब जान के साथ-साथ माल का नुकसान भी काफी मायने रखता है। ऐसे में, दुनिया के सभी शांतिप्रिय देशों को चाहिए कि वे आतंकवाद के पालक देशों के प्रति सख्त से सख्त कदम उठाएं। उनको इतना बाध्य कर दिया जाए कि वे अपनी जमीन से कोई नापाक हरकत होने ही नहीं दें। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि यदि कोई आतंकी संगठन इस तरह तकनीक को नियंत्रण में रखकर हमला करने लगेगा, तो दुनिया में काफी तबाही मच जाएगी।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को व्यापक और समग्रता में देखना चाहिए। सभी देशों को इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि वे तकनीक को किसी भी कीमत पर बर्बादी का उपकरण नहीं बनने देंगे। सत्ता संरक्षित आतंकवाद काफी घातक है। सभी सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर इसे रोकने की दिशा में काम करना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 186

बढ़ता विभाजन

देश में तेज आर्थिक विकास असंतुलित विकास, बढ़ती असमानता और विकास के चुनिंदा शहरी क्षेत्रों में सीमित रह जाने के रूप में सामने आया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 'रिलेटिव इकनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्सः 1960-61 टु 2023-24' में इस विषय की गहराई से पड़ताल की गई है। इसमें वृहद आर्थिक संदर्भों में तथा लोगों की खुशहाली के संदर्भ में राज्यों की प्रगति की सूक्ष्म समीक्षा करके अच्छा किया गया है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में राज्यों की हिस्सेदारी और उनकी सापेक्षिक प्रति व्यक्ति आय पर केंद्रित है।

दोनों ही मानकों पर बीते छह दशकों में पश्चिम और दक्षिण भारत ने देश के अन्य हिस्सों को पीछे छोड़ दिया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, इन पांच दक्षिण भारतीय राज्यों का देश की कुल जीडीपी में करीब 30 फीसदी योगदान है। महाराष्ट्र और गुजरात ने 1960 के दशक से ही वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में इजाफे में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। दोनों राज्यों की प्रति व्यक्ति आय 1960 के दशक से राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वर्ष 2023-24 में गुजरात की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के 160.7 फीसदी और महाराष्ट्र की 150.7 फीसदी रही। ओडिशा, सिक्किम, हरियाणा और दक्षिण के राज्यों ने 1990 के दशक के बाद से काफी सुधार किया है। बहरहाल इसी दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में 1960-61 के स्तर से गिरावट आई है और अब वे राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे हैं। खासतौर पर पश्चिम बंगाल की आर्थिक हिस्सेदारी में गिरावट आई और 2023-24 में उसकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 83.7 फीसदी रह गई जबकि 1960-61 में यह तीसरा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश था। उस समय इसकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 27.5 फीसदी अधिक थी।

बिहार की प्रति व्यक्ति आय न केवल 1960 के दशक से ही राष्ट्रीय औसत से कम है बल्कि 1960-61 में जहां यह राष्ट्रीय औसत की 70.3 फीसदी थी वहीं अब यह घटकर उसकी 32.8 फीसदी ही रह गई है। क्षेत्रीय अंतर के अलावा पड़ोसी राज्यों की की तकदीर भी समय के साथ बदली है। 1960 के दशक में हरित क्रांति के बाद पंजाब और हरियाणा की आय के स्तर में तेज इजाफा हुआ, वहीं पंजाब इस गति को बरकरार नहीं रख सका और उसकी आर्थिक स्थिति हरियाणा की तुलना में कमजोर हो गई। वर्ष 2023-24 में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की 106.7 फीसदी हो गई जबकि 1960-61 में यह 119.6 फीसदी थी। दूसरी ओर, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में 176.8 फीसदी रही। यह 1960-61 के 106.9 फीसदी से बहुत अधिक थी। कुल मिलाकर अधोसंरचना, शहरीकरण की दरों, व्यापार और परिवहन की लागत तथा राज्यस्तरीय नीतिगत अंतर क्षेत्रीय आय और वृद्धि दरों में अंतर को कुछ हद तक स्पष्ट कर सकते हैं।

राज्यों के बीच बढ़ता अंतर अहम नीतिगत चुनौतियां पेश करता है। राज्यों के बीच राजकोषीय संसाधनों के वितरण को लेकर अलग किस्म का तनाव उत्पन्न हो रहा है। अगर अमीर और गरीब राज्यों के बीच अंतर बढ़ा तो यह तनाव और अधिक बढ़ेगा। अब जरूरत इस बात की है कि लक्षित और केंद्रित हस्तक्षेप किया जाए ताकि पीछे छूट रहे राज्यों को तेजी से आगे लाया जा सके। इसके लिए वित्त आयोग के फंड के बंटवारे समेत अन्य उपाय आजमाए जा सकते हैं। जरूरत इस बात की भी है कि राज्यों में मानव विकास को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए ताकि अधिक संतुलित वृद्धि संबंधी अनुभव हो सकें। इसमें से कोई काम आसान नहीं है लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है।

अजय मोहंती

उचित है जमा वृद्धि पर रिजर्व बैंक की चिंता

केंद्रीय बैंक का जमा राशि में इजाफा करने संबंधी आह्वान दरअसल खुदरा जमा में वृद्धि से संबंधित है। बता रहे हैं टीटी राम मोहन

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बैंकों से जमा में वृद्धि की गति बढ़ाने को कहा है। उनके इस आह्वान की आलोचना हुई है और कुछ लोगों ने तो इसका मखौल तक उड़ाया है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि जमा की दिक्कत पूरी तरह काल्पनिक है और ऋण देते समय बैंकों के पास जमा की कमी नहीं पड़ती। वे गलत सोचते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर की चिंताएं वाजिब हैं और आलोचकों की दलीलों की गहराई से पड़ताल करने पर यह बात स्पष्ट हो जाएगी।

बचतकर्ता खास तौर पर युवा बचतकर्ता जमा के विकल्प के तौर पर म्युचुअल फंड और बीमा योजनाओं की तरफ खिंच रहे हैं। बैंकों को इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि म्युचुअल फंड और बीमा कंपनियों के पास जाने वाली रकम जमा के रूप में बैंकों के पास ही आ जाती है।

यह सही है कि म्युचुअल फंड और बीमा योजनाओं में लगाई गई राशि बैंकों के पास ही पहुंच जाती है। लेकिन जब बचतकर्ता बैंकों में निवेश करते हैं तो वे अपेक्षाकृत लंबी परिपक्वता अवधि वाली बचत या सावधि जमा (एफडी) का चयन करते हैं। म्युचुअल फंड या बीमा कंपनियों में जो रकम बैंकों में जमा होती है, वह चालू खाते में जमा या बहुत छोटी अवधि की एफडी के रूप में आती है। बचत खाते में जमा रकम के मुकाबले एफडी ज्यादा अस्थिर होती है। इस कारण बैंक ऋण देने के लिए चालू खाते या बेहद कम अवधि वाली एफडी की रकम का इस्तेमाल नहीं कर पाते।

ऋण से जमा राशि आती है न कि जमा राशि से ऋण दिए जाते हैं। इसलिए यह धारणा ही गलत है कि जमा के कारण ऋण वृद्धि में रुकावट आ रही है। बैंक लेजर में एक प्रविष्टि करके ऋण बना सकते हैं। उसके बाद बैंक ऐसी ही प्रविष्टि अपनी बैलेंस शीट के देनदारी वाले हिस्से में करते हैं। इसलिए बैंक ऋण और जमा को चुटकियों में पैदा कर सकते हैं। मगर जब कर्जदार भुगतान करने के लिए चेक जारी करता है तो जमा के मद में धन मौजूद होना जरूरी है। तात्कालिक आवश्यकता के लिए बैंक केंद्रीय बैंक से अथवा अंतर-बैंक बाजार से राशि ले सकते हैं।

ऐसी उधारी की सीमा होती है। खुद को स्थिर रखने के लिए बैंकों को किसी मध्यस्थ संस्था से रकम लेने के बजाय बचतकर्ताओं के ही पास जाकर जमा रकम जुटानी होती है। ऐसे में यह बात मायने रखती है कि ऋण देने के लिए रकम कैसे जुटाई गई है।

जमा वृद्धि का संबंध केंद्रीय बैंक द्वारा धनराशि के निर्माण से है। अगर केंद्रीय बैंक ही धन तैयार नहीं कर पा रहा है तो जमा में धीमी वृद्धि के लिए बैंकों पर दोष मढ़ना सही नहीं है। अगर केंद्रीय बैंक मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाना चाहता है तो वह खुले बाजार के रास्ते बैंकों से बॉन्ड खरीद सकता है ताकि बैंकों के पास धन का भंडार बढ़ जाए।

धन की आपूर्ति भी मुद्रा और जमा के जोड़ के बराबर होती है। धन की आपूर्ति बढ़ती है तो जमा भी बढ़ती जाती है। ऊपर के दो समीकरणों को मिलाएं तो जमा में तेजी से इजाफा नहीं होने पर माना जाता है कि केंद्रीय बैंक पर्याप्त धन तैयार नहीं कर पा रहा है।

इस दलील में दो चूक हैं। पहली, केंद्रीय बैंक केवल जमा बढ़ाने के लिए खुले बाजार का परिचालन नहीं कर सकता और बैंक के पास धन का भंडार नहीं बढ़ा सकता। खुले बाजार का परिचालन किसी भी समय दर का लक्ष्य हासिल करने के लिए ही किया जाता है। दूसरी, हमें यह भी स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि धन के भंडार में वृद्धि से जमा में इजाफा किस तरह होता है। बढ़ते हुए ऋण के बराबर बढ़ी हुई जमा भी बैंक की बैलेंस शीट में होनी चाहिए। इसलिए धन की आपूर्ति बढ़ने पर हमें जमा में वृद्धि भी दिखती है।

किंतु यदि नकदी और ब्याज दर के जोखिम को सही से संभालना है तो बढ़ती हुई जमा प्रविष्टियों के बराबर धन भी जमा के रूप में होना चाहिए। अब देखते हैं कि ऋण के लिए रकम जिस जमा के जरिये लाते हैं, उसके प्रकार का क्या महत्त्व है। जमा रकम चालू खाते से आ सकती है, बचत खाते से आ सकती है और सावधि जमा के रूप में भी आ सकती है। चालू खातों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, इसलिए वहां ब्याज दर का जोखिम ही नहीं होता। लेकिन जैसा पहले बताया गया है, चालू खाते में जमा रकम से तरलता या नकदी का बड़ा जोखिम होता है। चालू खाते के उलट बचत खाते में जमा रकम पर ब्याज देना होता है। लेकिन इस ब्याज की दर सावधि जमा की तुलना में काफी कम होती है और छोटे से दायरे में ऊपर-नीचे होती है। इसलिए वहां भी ब्याज दर का जोखिम बहुत कम होता है। अगर बचत जमा रिटेल किस्म की है तो उन्हें काफी स्थिर माना जाता है यानी तरलता का जोखिम बहुत कम होता है।

सावधि जमा में ब्याज दर अधिक होती है लेकिन खुदरा सावधि जमा को कंपनी एफडी की तुलना में ज्यादा स्थिर माना जाता है क्योंकि कंपनी एफडी बहुत कम अवधि की होती हैं। नकदी का जोखिम कम करने के लिहाज से 2 करोड़ रुपये से कम की खुदरा जमा को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती है। उसके बाद 5 करोड़ रुपये से कम की खुदरा जमा पसंद की जाती हैं। इसलिए समझना होगा कि बैंकों से जमा बढ़ाने के आह्वान में बड़ी रकम वाली थोक जमा नहीं बल्कि खुदरा जमा बढ़ाने की बात कही गई है।

कई बैंकों के लिए यह चुनौती साबित हो रहा है। बैंकों को लगा कि वे ऑनलाइन बैंकिंग के जरिये बेहद कम खर्च पर खुदरा जमा हासिल कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी शाखाओं का नेटवर्क फैलाने में काफी कम निवेश किया। अब उन्हें होश आ गया है और पता लग गया है जमा हासिल करने के लिए शाखाएं कितनी महत्त्वपूर्ण हैं। किंतु देश में जमा में वृद्धि के नए केंद्र तैयार हो रहे हैं, जिनके हिसाब से उन्हें अपनी शाखाएं भी बदलनी पड़ेंगी।

कई निजी बैंक तय न्यूनतम सीमा से अधिक राशि रखने पर बचत खातों में भी एफडी के बराबर ब्याज दे रहे हैं। इसे बचत जमाओं के विचार को विद्रूप बनाना कहा जा सकता है। बचत जमा में आम तौर पर ब्याज दर कम होती है क्योंकि बैंक उनमें भुगतान सेवा भी मुहैया कराते हैं। जमाकर्ता को कम ब्याज दर से कोई शिकायत नहीं होती, इसलिए बचत जमा की ब्याज दरें नीतिगत दरों में बदलाव के साथ नहीं बदलतीं। अगर जमाकर्ताओं को बचत जमा पर सावधि जमा के बराबर ब्याज दिया जाएगा तो ये सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। रिजर्व बैंक को तय कर देना चाहिए कि भारतीय स्टेट बैंक की बचत जमा ब्याज दर से 150 आधार अंक अधिक तक की ब्याज दर वाली जमा को ही 'बचत' जमा कहा जाएगा।

बैंकों ने शुल्क के जरिये कमाई बढ़ाने के चक्कर में म्युचुअल फंड और बीमा योजनाओं की अंधाधुंध बिक्री कर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। उन्हें इस बात का अहसास नहीं था कि इसकी कीमत ऋण में वृद्धि के लिए थोक जमा पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता की शक्ल में चुकानी होगी। बैंक खुद को याद दिलाएं कि ऋण से शुल्क के रूप में भी तगड़ी आय होती है। उन्हें सोचना चाहिए कि शुल्क वाली योजनाओं मसलन म्युचुअल फंड और बीमा की क्या भूमिका रहे। बैंकिंग स्थिरता का मंत्र नहीं बदलता है और वह मंत्र है - बैंकों को अपने मूल कारोबार पर ध्यान देना चाहिए, जो खुदरा जमा हासिल करना और ऋण देना है।

नदियों का संरक्षण आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी

पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास के बीच विरोधाभास पर न जाने कितनी बार बहस हो चुकी है। अक्सर ऐसी बहसों और चर्चाओं का अंत प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य बनाए रखने पर जोर देने वाले भाषणों के साथ होता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन से जुड़े संकट गहराने के बाद ये बहसें हमें आगाह करने लगी हैं और इनमें भविष्य के खतरों की चेतावनी भी मिलने लगी है।

पिछले कुछ महीनों के दौरान मॉनसून देश भर में छाया और शहरों में बाढ़ का पानी घुसने की घटनाएं बढ़ती गईं। इससे पता चलता है कि यह संकट कितना गहरा गया है और इस पर काम करना कितना जरूरी है। नदी क्षेत्रों में अतिक्रमण के नतीजे काफी भयावह होते हैं और यह बात वडोदरा तथा विजयवाड़ा में हाल में आई बाढ़ से सिद्ध हो चुकी है।

पिछले महीने वडोदरा के कई हिस्से पानी में डूब गए और खबरों के अनुसार तीन दिन तक बाढ़ 8 से 12 फुट ऊंचा पानी भरा रहा। इसके कारण शहर में बिजली गुल रही, टेलीफोन तथा इंटरनेट नेटवर्क ठप हो गया और रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ तथा सांप पहुंच गए। इस स्थिति के लिए विश्वामित्री नदी के इर्द-गिर्द अतिक्रमण को बड़ा कारण बताया जा रहा है। लगभग एक सदी पुराने जलाशय अजवा और प्रतापपुरा अतिक्रमण के कारण लबालब भर गए और इनसे निकला पानी नदी का जल स्तर बढ़ाने लगा।

इसी तरह विजयवाड़ा में हाल में आई बाढ़ का प्रमुख कारण बुडामेरु नदी से जुड़ी नहर के इर्द-गिर्द अतिक्रमण बताया जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर थी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडु को इस नहर से अतिक्रमण हटाने के लिए 'ऑपरेशन बुडामेरु' की घोषणा करनी पड़ी। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली भी मॉनसून में यमुना का जल स्तर बढ़ने के कारण लगातार बाढ़ की चपेट में आ रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के 2021 के मास्टर प्लान के अनुसार दिल्ली में यमुना का बाढ़ क्षेत्र करीब 97 वर्ग किलोमीटर में है, जो दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7 प्रतिशत बैठता है। किंतु मास्टर प्लान में कहा गया है कि यमुना नदी के दोनों तरफ अतिक्रमण बढ़ने से शहर में इसका बहाव बहुत संकरा हो गया है। वृद्धि की प्रक्रिया और शहरी केंद्रों में बदलाव की सीधी मार मानव बस्तियों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को झेलनी पड़ रही है। पारिस्थितिक संतुलन के लिहाज से महत्त्वपूर्ण नदी के बेसिन पर इस तरह के अतिक्रमण से कई गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने नगरीय नियोजन (म्युनिसिपल प्लानिंग) और विकास प्राधिकरणों के लिए 2021 में नदी केंद्रित शहरी नियोजन दिशानिर्देश जारी किए, जिनका उद्देश्य नदी के नजदीक होने वाले विकास पर नियंत्रण रखते हुए टिकाऊ नदी प्रबंधन सुनिश्चित करना था। शहरों में आबादी बढ़ने एवं शहरों की सीमाओं का विस्तार होने का सीधा नतीजा प्राकृतिक संसाधनों खासकर नदियों के आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल और शोषण के रूप में दिख रहा है। यह स्थिति बदतर होती जा रही है। प्रदूषण स्तर बढ़ने और शहरों में पानी की मांग पूरी करने के लिए नदियों के जल के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण नदी से सटे निचले इलाकों को नुकसान पहुंच रहा है।

अमित कपूर और विवेक देवरॉय

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2022 में एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 603 नदियों का जायजा लिया गया, जिनमें 279 नदियों में 311 हिस्से प्रदूषित पाए गए थे। अपशिष्ट पदार्थों के नदियों में पहुंचने, अवैध निर्माण, ड्रेजिंग (नदी सतह की सफाई) के जरिये नदियों से अधिक पानी लेने और उनका रास्ता बदलने के कारण जल की गुणवत्ता, जल तंत्र एवं भूमिगत जल की गुणवत्ता पर लगातार असर हो रहा है।

शहरीकरण की रफ्तार बढ़ने से भूमि उपयोग के तौर-तरीकों में बदलाव आ रहा है, जिससे नदियों के बेसिन भी बदल रहे हैं। नदियों के बेसिन के साथ छेड़-छाड़ का तात्कालिक असर बाढ़ की विभीषिका के रूप में दिख रहा है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में तेजी के साथ शहरीकरण होने से नदियों के किनारे अतिक्रमण बढ़ गया है और जल जमाव एवं बाढ़ वाले क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक इलाके तैयार कर दिए गए हैं। नतीजा यह हुआ है कि मॉनसून के दौरान इन प्राकृतिक क्षेत्रों की जल सोखने की क्षमता कम हो गई है। नदियों के बेसिन में बिगड़ाव के कारण स्वच्छ जल की कमी का संकट उत्पन्न हो रहा है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां जल संकट बढ़ता जा रहा है। यहां दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी रहती है मगर कुल वैश्विक जल संसाधन का 4 प्रतिशत हिस्सा ही यहां पर है। जल के अनियोजित इस्तेमाल, प्रदूषण और नदियों के कुप्रबंधन के कारण जल संकट की आशंका प्रबल हो गई है। स्वच्छ जल क्षेत्र तेजी से कम हो रहे हैं, जिससे पानी की किल्लत और भी बढ़ती जा रही है।

नदियों का सिकुड़ना एवं क्षरण उन बड़ी चुनौतियों में शामिल हैं, जिन पर देश को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। हम अपने शहरों को 2050 तक देश की 50 प्रतिशत आबादी संभालने के लिहाज से तैयार कर रहे हैं, इसलिए नदी पुनरुद्धार और पुनर्ग्रहण के मॉडलों को शहरों के डिजाइन में शामिल करना जरूरी हो गया है। इन मॉडलों में नदियों का जल सूखने की समस्या का समाधान, नदियों का सौंदर्य बढ़ाना, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना और नदी के जल की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए जल निकासी की टिकाऊ व्यवस्था लागू करना शामिल हैं।

पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम खत्म करने तथा टिकाऊ विकास से जुड़े लक्ष्यों की पूर्ति पर भी नदियों के बेसिन का संरक्षण गहरा असर डालता है। नदियां स्वच्छ जल देती हैं, किसी भी स्थान की जलवायु को नियंत्रण में रखती हैं, जैव विविधता के केंद्र तैयार करती हैं और कृषि तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं। पर्यावरण और आर्थिकी के लिहाज से भारत का भविष्य नदी तंत्र को सुरक्षा दिए बगैर और उसका पुनरुद्धार किए बगैर महफूज नहीं है।

नदियों के बेसिन को नुकसान पहुंचने के खतरे देखकर तत्काल कई मोर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए शहरी विकास में अधिक सख्त नियमन होना चाहिए और जमीन के इस्तेमाल के कानून भी सख्त होने चाहिए ताकि प्राकृतिक जल निकासी तंत्र का अतिक्रमण नहीं हो। साथ ही नदियों के किनारे वन क्षेत्र तैयार करने, महत्त्वपूर्ण जल संभरणों में सुरक्षित क्षेत्र बनाने और जल प्रबंधन के टिकाऊ तरीके लागू करने जैसे उपायों के जरिये नदी तंत्र को सुधारना भी होगा। जल संसाधनों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक बनाना और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना भी नितांत जरूरी है।

(कपूर इंस्टीट्यूट फॉर कंपटीटिवनेस के अध्यक्ष हैं और देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। आलेख में जेसिका दुग्गल का भी योगदान)

आपका पक्ष

एक देश एक चुनाव

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश मंजूर करने के बाद देश में एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को बल मिलेगा। इसमें दो राय नहीं कि यह विचार देश के लिए अनेक दृष्टि लाभदायक है। देश में लगातार चुनाव के कारण सरकारी मशीनरी के सामान्य कामकाज के साथ विकास कार्य भी बाधित होते हैं। एक साथ चुनाव से प्रशासन को अधिक स्थिर वातावरण मिलेगा तथा निर्वाचित प्रतिनिधि भी लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त रहने के बजाय अपने कर्तव्यों पर अधिक ध्यान दे पाएंगे। इसके आर्थिक पक्ष पर दृष्टि डाली जाए तो लोक सभा से लेकर स्थानीय निकायों तक सभी चुनावों पर लगभग 10 लाख करोड़ से भी अधिक का खर्च आता है। इसी प्रकार लगातार महंगे होते प्रचार माध्यम एवं अन्य खर्च के कारण चुनावों में घोषित से कहीं अधिक अघोषित धन खर्च होता है। लेकिन एक साथ चुनाव के कारण होने वाली व्यावहारिक अड़चनों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जैसे कि संसद के साथ विधान सभा चुनाव में आधे से अधिक बकाया कार्यकाल वाली विधान सभा को समायोजित करने के लिए सर्वसम्मति बनाना टेढ़ी खीर साबित होगी। वर्तमान में सत्तापक्ष एवं विपक्ष में कटु संबंध है। अल्पमत की सरकारें, त्रिशंकु लोक सभा एवं विधान सभा, जनप्रतिनिधियों में दलबदल की बढ़ती प्रवृत्ति से अस्थिर वातावरण और इसकी वजह से होने वाले समयपूर्व चुनाव भी इस योजना की लय बिगाड़ेंगे। याद रहे कि देश अनेक बार मध्यावधि चुनाव के दौर से भी गुजर चुका है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में इस पर एक सर्वसम्मत निर्णय आवश्यक है।

विमलेश पगारिया, धार

जम्मू-कश्मीर विधान सभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होगा

विश्व शांति दिवस का उद्देश्य

संयुक्त राष्ट्र ने मानवता के लिए सभी मतभेदों से ऊपर उठने, शांति के लिए प्रतिबद्ध होने और संस्कृति के निर्माण में योगदान करने के उद्देश्य से विश्व शांति दिवस मनाने का निर्णय लिया था। साल 2001 में 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस दिन सफेद कबूतरों को उड़ाकर शांति का पैगाम भी बहुत से देशों द्वारा दिया जाता है। इस दिवस का इस बार का थीम है, 'शांति की संस्कृति का विकास करना।' हमारा देश अहिंसा की राह पर चलता आ रहा है। शांति की भावना से भी हमारा देश विश्व गुरु है। लेकिन जो देश हमेशा युद्ध पर ही विश्वास रखते हैं, हर मुद्दे को युद्ध के जरिये ही सुलझाना चाहते हैं ऐसे देश सारी दुनिया के लिए मुसीबत बनते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ये पांच बातें कही थी कि, पहली हमें एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना, दूसरा किसी को भी एक दूसरे के विरूद्ध आक्रामक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, तीसरी किसी को भी एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, चौथा समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना चाहिए और पांचवां शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना, दुनिया अगर इन बातों पर अमल करे तो विश्व में अवश्य ही शांति का माहौल बनेगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को कहा कि स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पश्चिमी नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है और इससे अरब सागर में समुद्री शक्ति में महत्त्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के पास पश्चिमी मोर्चे पर दो विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य हो गए हैं।

अगर हम दूसरे पक्ष की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो लोकतंत्र का विकास संभव नहीं है। -महात्मा गांधी

पवित्रता और राजनीति

आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला गहराता जा रहा है, जो वाकई बेहद गंभीर है। शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के इस खुलासे से हुई कि प्रसाद के लड्डुओं में प्रयुक्त घी में पशुओं की चर्बी मिलाई गई थी, जिसकी पुष्टि गुजरात स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी करती है। उल्लेखनीय है कि हर दिन तिरुपति बालाजी मंदिर में करीब पचहत्तर हजार श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। यहां की तीन सौ वर्ष पुरानी रसोई में रोज करीब साढ़े तीन लाख लड्डू बनते हैं, जिनके लिए पचास वर्षों से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन (केएमएफ) रियायती दरों पर ट्रस्ट को घी दे रहा था। लेकिन जब केएमएफ ने वर्षों पुरानी रियायती दरों पर घी उपलब्ध कराने से मना किया, तो आंध्र प्रदेश की पिछली जगन मोहन सरकार ने बाजार में ठेके के जरिये पांच निजी फर्मों को घी आपूर्ति का ठेका दे दिया था। हालांकि केएमएफ ने कहा था कि इससे कम कीमत पर कोई कंपनी घी की आपूर्ति करती है, तो वह निश्चित ही गुणवत्ता से समझौता करेगी। देश में घी में मिलावट होना कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर देश के सबसे बड़े मंदिर के प्रसाद में मिलावट के ये आरोप सही हैं, तो फिर बाजार में फुटकर मिलने वाले खाद्य पदार्थों पर भरोसे की बात ही क्या करनी! मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को वाईएसआर कांग्रेस ने स्वाभाविक ही खारिज करते हुए उच्च न्यायालय की शरण ली है। दूसरी तरफ, केंद्र ने आंध्र प्रदेश सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगते हुए कहा है कि डेयरी विकास बोर्ड की प्रयोगशाला की रिपोर्ट की जांच अब भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) करेगा। जाहिर है कि आंध्र प्रदेश से लेकर पूरे देश की सियासत में आरोपों-प्रत्यारोपों की जंग तेज हो गई है। लेकिन तिरुमला के प्रसाद की शुद्धता और पवित्रता राजनीति का विषय नहीं, बल्कि भक्तों की आस्था से जुड़ा मामला है, जिसका

आध्यात्मिक और भावनात्मक महत्व भी है। लिहाजा इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए और अगर कुछ भी गलत हुआ है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, साथ ही, प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर नियमित जांच और पारदर्शी प्रक्रिया भी अपनाई जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के सवाल उठे ही नहीं।

अपने ही नियमों को तोड़ रहा पाकिस्तान

पाकिस्तान में एक्स पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध है, लेकिन प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्री और अधिकारी एक्स का धड़ाधड़ उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान सरकार को चुनना होगा कि क्या सोशल मीडिया पर नफरत को रोकने के लिए उसे प्रतिबंधित करना उचित है या डिजिटल अर्थव्यवस्था को बचाना।

पाकिस्तान सरकार ने कई महीनों से एक्स (ट्विटर) पर पहुंच प्रतिबंधित कर रखी है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक उपयोगकर्ता सिर्फ मुफ्त या सशुल्क वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के जरिये पहुंच सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार, एक्स प्लेटफॉर्म उत्तर कोरिया, बेलारूस, चीन, मिस्र, तुर्कमेनिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अन्य देशों में भी प्रतिबंधित है। कुछ देशों में केवल सरकार द्वारा अनुमोदित वीपीएन ही वैध हैं, हालांकि उपयोगकर्ताओं की निगरानी की जाती है। लेकिन अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। जबसे सरकार ने फायरवॉल लगाने की प्रक्रिया शुरू की है, यहां काफी हंगामा मचा हुआ है। सरकार का तर्क है कि यह साइबर सुरक्षा का मामला है और दुनिया भर के देश इस तकनीक का उपयोग करते हैं।

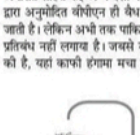

मरियाना बाबर
वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार

चीन, ईरान, तुर्किये और रूस जैसे देशों ने इंटरनेट सामग्री को विनियमित करने के लिए वर्षों से राष्ट्रीय फायरवॉल का उपयोग किया है, उनका कहना है कि उनका उद्देश्य स्रोतों को चिह्नित करना और उन्हें प्रतिबंधित करना है।

यह मामला अदालत में भी ले जाया गया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि गृह मंत्रालय ने कहा कि वे एक्स पर रोक हटाकर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते। पाकिस्तान में एक्स पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध है, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री तथा सभी मंत्रालय विदेशी अधिकारियों सहित जनता तक पहुंचने के लिए एक्स का उपयोग क्यों कर रहे हैं। यह हास्यास्पद है कि सरकार अपने ही नियमों को तोड़ रही है।

सुरक्षा प्रतिष्ठान ने एक्स की ताकत की आलोचना की, जिसका पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआई) और इसके प्रमुख पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विदेशी समर्थकों ने चुनाव से पहले समर्थकों और अब विपक्ष तक पहुंचने के लिए इस चालाक तकनीक का इस्तेमाल किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने खान पर प्रतिबंध लगाया था, तब भी वह इसका इस्तेमाल करने में सफल रहे थे। अन्य राजनीतिक दलों के विपरीत पीटीआई को कई वर्षों से बढ़त हासिल थी।

पिछले चुनाव में पीटीआई का चुनाव चिह्न क्रिकेट बैट था, लेकिन पीटीआई उम्मीदवारों को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर उन्हें अलग-अलग चुनाव चिह्न आवंटित किए गए, लेकिन मतदाताओं को एक्स से दिशा-निर्देश मिले। सोशल मीडिया ने काम किया व पीटीआई ने बहुमत हासिल किया, पर चुनाव आयोग ने उसकी जीत की घोषणा नहीं की।

इस सप्ताह फिर से एक्स सरकार और उसके सहयोगी दलों के लिए बाधक बना, जब उन्होंने नेशनल असेंबली और सीनेट में कुछ सांविधानिक संशोधनों को पेश करने की कोशिश की। वे संशोधन न्यायिक सुधारों से संबंधित थे, जहां राजकोषीय (ट्रेजरी) बेंच अधिक शक्तियां प्राप्त करना चाहती थीं, जो अभी न्यायपालिका को प्राप्त हैं। कुछ संशोधन सेना के पक्ष में थे, ताकि उनके खिलाफ मामलों को सिविल अदालतों में चुनौती न दी जा सके।

यह मुद्दा एक्स पर वायरल हो गया, जहां लोगों ने इसका विरोध किया और मांग की कि इन संशोधनों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, इन पर बहस होनी चाहिए और फिर इन्हें दोनों सदनों में लाया जाना चाहिए। सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई, क्योंकि ऐसा लगा कि सांविधानिक संशोधनों को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था और पार्टी के किसी भी मंत्री या सदस्य ने मसौदा भी नहीं देखा था। सरकार को मजबूर होकर संसद सत्र बुलाना पड़ा और कहना पड़ा कि वह ये संशोधन बाद में लाएगी।

लेकिन मुल्क में इंटरनेट की गति बहुत धीमी हो गई है, क्योंकि इसके चारों ओर फायरवॉल बनाया जा रहा है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अली एहसान ने एक बयान में कहा, 'तेजी से बढ़ता आईटी उद्योग एक आपदा का सामना कर रहा है, जो अभूतपूर्व परिचालन व्यवधानों से जूझ रहा है, और पाकिस्तान के बढ़ते तकनीकी क्षेत्र की नींव को खतरा पहुंचा रहा है।' उन्होंने कहा कि लंबे समय तक इंटरनेट व्यवधान और अनियमित वीपीएन प्रदर्शन से व्यावसायिक संचालन के पूरी तरह से ठप होने का खतरा है। उन्होंने कहा, 'ये व्यवधान महज असुविधाएं ही पैदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उद्योग की व्यवहार्यता पर प्रत्यक्ष, ठोस और आक्रामक हमला हैं, जिससे भारी वित्तीय नुकसान होने का अनुमान है, जो 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा तक पहुंच सकता है।' आईटी कंपनियों का कहना है कि इससे पाकिस्तानी कारोबारों को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। पत्रकारों को भी धीमी इंटरनेट का सामना करना पड़ रहा है और एक्स से जुड़ने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का वादा करती है, दूसरी तरफ वह इसे पूरी तरह से रोक रही है!

साइबर हमलों को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे-बड़े संगठनों को अपने नेटवर्क के बचाव के लिए सुरक्षा उपाय करने चाहिए। इनमें प्रॉक्सी सर्वर, वीपीएन और एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर जैसे टूल का इस्तेमाल करना है। ये हैकिंग, घुसपैठ और साइबर हमलों के खिलाफ सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाली गैर-लाभकारी संस्था 'बोलो भी' ने जून 2020 में चेतावनी दी कि वीपीएन रजिस्टर करने से न केवल इस्तेमाल की जाने वाली विशिष्ट वीपीएन सेवा सरकार के डाटाबेस में आपकी पहचान से जुड़ जाएगी, बल्कि सरकार को आपकी इच्छानुसार आपके डाटा के लिए अनुरोध करने और निजी डाटा तक पहुंचने की अनुमति भी मिल जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले वीपीएन सेवा प्रदाताओं की सेवा सरकार बंद भी कर सकती है। अनिवार्य रूप से, वीपीएन पंजीकरण एक सार्वजनिक निगरानी उपकरण बन सकता है, जो विश्वास की आड़ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।

पाकिस्तान सरकार चाहती है कि स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों कंपनियां क्लाउड सेवाओं सहित देश के भीतर पाकिस्तानी लोगों के बारे में डाटा जमा करें। फिर इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि यह दृष्टिकोण सुरक्षा के लिए स्वर्ण मानक है। एक मुद्दा जो अब भी सुरक्षा प्रतिष्ठान को परेशान कर रहा है, वह है सैन्य विरोधी ट्वीट, जिनमें से कुछ वास्तव में अस्वीकार्य हैं, ज्यादातर विदेशों में रह रहे पाकिस्तानियों द्वारा, जिनमें से अधिकांश पीटीआई समर्थक हैं। यह एक नया चलन है, जो इमरान खान के जेल जाने और सुरक्षा प्रतिष्ठान के साथ उनके लगातार टकराव के बाद शुरू हुआ है। सरकार को चुनना होगा कि क्या सोशल मीडिया पर नफरत को रोकने के लिए उसे प्रतिबंधित करना उचित है या डिजिटल अर्थव्यवस्था को बचाना बेहतर है, क्योंकि मुल्क में 60 प्रतिशत से अधिक युवा हैं और उनमें से कई इंटरनेट से अपनी आजीविका कमाते हैं?

edit@amarujala.com

आर्थिकी

सामाजिक सुरक्षा के लाभ सबको मिलें

सरकार को देश के आम आदमी के लिए सामाजिक सुरक्षा के बारे में गंभीरतापूर्वक ध्यान देना होगा और निजी क्षेत्र की पेंशन योजनाओं को भी आकर्षक बनाना होगा।

केंद्र सरकार ने 70 साल या उससे अधिक उम्र के सभी वर्गों के लोगों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत उन्हें पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। उम्मीद है कि इससे 4.5 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। इसी तरह केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दी है। देश के करीब 57 करोड़ के क्रमबल में से तीन फीसदी से भी कम सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी यूपीएस से लाभान्वित हुए हैं। लेकिन निजी और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों के सामने वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। हालांकि सरकारी कर्मचारियों के अलावा संगठित निजी क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी पेंशन की कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये अपर्याप्त हैं।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मात्र 436 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। यह योजना 18 से 55 वर्ष की आयु के लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष के लोग 20 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। एपीवाई के तहत, 60 साल की उम्र में 1,000 रुपये से लेकर 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दी जाती है। देश का कोई भी श्रमिक जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच हो, एपीवाई योजना में शामिल हो सकता है।

जयंतीलाल भंडारी

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक स्वैच्छिक, दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को एक मजबूत सेवानिवृत्ति कोष बनाने में सक्षम बनाती है। इसी तरह व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने दो प्रमुख पेंशन योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) है और दूसरी व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस-ट्रेडर्स)।

इसके अलावा संगठित क्षेत्र में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है। भविष्य निधि के लिए कर्मचारी का जो अंशदान कटता है, उसका एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। पेंशन के लिए कर्मचारी को कम से कम दस साल तक नौकरी पूरी करनी होती है और पीएफ अकाउंट में अंशदान करना होता है। मौजूदा नियमों के अनुसार, पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपये है। चिंताजनक है कि जहां असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोग पेंशन व्यवस्था से दूर हैं, वहीं बचत पर घटी हुई ब्याज दर के कारण देश में सामाजिक सुरक्षा की चिंताएं बढ़ रही हैं। अब भी देश में बड़ी संख्या में लोगों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं हैं। अतएव अब सरकार को देश के आम आदमी के लिए सामाजिक सुरक्षा के बारे में गंभीरतापूर्वक ध्यान देना होगा और निजी क्षेत्र की पेंशन योजनाओं को भी आकर्षक बनाना होगा। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के मद्देनजर निजी क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों के साथ-साथ आम आदमी को भी उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा देने की डगर पर नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी।

देखने वाली बात होगी कि समाज एआई से कैसे निपटता है, लेकिन संदेह नहीं कि यह दिलचस्प होगा। -कॉलिन एंगल

लोग बेशक इसे कृत्रिम (बुद्धिमत्ता) कहें, लेकिन यह वास्तविकता में हमारी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा। -गिन्नी रोमेटी

मां की देखती आंखों में उम्मीद होती है

जब मैं छोटा था, तो विश्वयुद्ध हुआ था। उसी उम्र में तय किया था कि इस सारे विनाश के बीच में कविता की रोशनी में जाऊंगा और वहां से और रोशनी लाऊंगा। उस भयंकर विनाशलीला के बीच भी मेरे भीतर उम्मीद जिंदा रही, क्योंकि मां की आंखें मुझे देख रही थीं।

मां की आंखें, जो दिल और दिमाग को चीरकर भीतर तक घुस आती हैं, वही आंखें दरअसल हमारा जमीर हैं। वही हमें प्यार करती हैं और हमारे सही-गलत का आकलन करती हैं। जब बच्चा पहला डग भरता है, तो मां की आंखें उसे देखती हैं। वही आंखें उसे देखती हैं, जब वह सबकुछ छोड़कर दूर जा रहा होता है। काश, मेरी आवाज उन बच्चों तक पहुंच जाए, जो अपने मां-बाप को वृद्धाश्रमों और अस्पतालों में छोड़ आते हैं।

तादेउष रोजेविच

मुझे याद है, मेरी मां ने मुझसे सिर्फ एक बार कहा था, तब मेरी उम्र पांच साल थी। मां ने कहा था-'तुम बहुत शरारती हो, देखना, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और फिर कभी लौटकर नहीं आऊंगी।' मुझे याद है कि मेरे दिल से खून बहने लगा था। मां ने तो सिर्फ एक बार कहा था, मैं सारी उम्र इस बात से डरा रहा कि मां चली जाएगी। और एक दिन मां चली गई। लेकिन जिस समय उसने कहा था, उस समय नहीं गई। न ही उस तरह से गई। वह इस तरह गई कि मैं यह कह सकता हूं कि वह हमेशा मेरे साथ है। मां की आंखें मुझे लगातार देख रही हैं। किसी दूसरी दुनिया में बैठकर वह मुझे देख रही है। मैं दूसरी दुनिया में यकीन नहीं रखता। सिर्फ पहली दुनिया को मानता हूं, जिसमें मारकाट मची हुई है। इन्सान मर रहा है। भगवान मर रहा है। इनके साथ उम्मीदें भी मर रही हैं। जब मैं छोटा था, तो विश्वयुद्ध हुआ था। रातों को भयानक सपने आते थे। उसी उम्र में मैंने तय किया था कि इस सारे विनाश के बीच मैं एक कवि (बनूंगा-सृजन का कवि)। मैं कविता की रोशनी में जाऊंगा और वहां से और रोशनी लाऊंगा। उस भयंकर विनाशलीला के बीच भी मेरे भीतर उम्मीद जिंदा रही, क्योंकि मां की आंखें मुझे देख रही थीं। मां को देखती हुई आंखें हमारी उम्मीद होती हैं।

जीवन धारा

आज जब मैं 77-78 साल का हो चुका हूं, दुनिया में वैसी ही मारकाट मची हुई है। मैं आज भी उम्मीद से भरा हूं, क्योंकि मां की आंखें मुझे देख रही हैं। आपको मां की आंखें देख रही हैं-यह एहसास जैसे ही आपको होता है, आप खुद को उम्मीद और साहस से भरा हुआ पाते हैं। अगर मां का प्यार आपने दिल से महसूस किया है, तो आप जीवन भर इस प्यार में यकीन रखेंगे और लोगों से नफरत नहीं करेंगे। अगर आपकी मां सामने नहीं है, तो भी महसूस कीजिए कि उसकी आंखें हर घड़ी देख रही हैं।

(फ्रेंडेज के महान कवि की आत्मकथा 'मेरा दिग्दर्शन' से ये अंश लिए गए हैं।)

एआई कहता है कि मैं कहीं से नहीं हूं

तेरह साल की उम्र में सऊदी अरब को छोड़ने के बाद अब अमेरिका ही मेरा देश है। लेकिन पुरानी तस्वीरों ने याद दिलाया कि मैं यहां की नहीं हूं। मैंने एआई को वे तस्वीरें दिखाईं और पूछा कि मैं कहां से हूं।

नाऊफ एजोवसीर
द न्यूयॉर्क टाइम्स

तेरह साल की उम्र में अमेरिका में बसने से पहले मेरी पहचान बिल्कुल स्पष्ट थी। जब भी कोई पूछता, मैं बताती, 'मैं सऊदी अरब से हूं।' लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई, इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होता गया कि 'तुम कहां से हो?' दरअसल, स्कूल व परिवार की वजह से, मैं दोनों देशों के बीच आवाजाही करती रहती थी, नतीजतन कभी भी एक जगह पूरी तरह बस नहीं सकी। 2020 से मैंने इस सवाल का समुचित उत्तर देने के लिए अपनी पहचान को टटोलना शुरू किया। मैंने अपनी मां से विस्तृत जानकारी हासिल की, 1800 के दशक तक के अपने पूर्वजों के इतिहास का पता लगाया और अपने परिवार तथा उनके रहने के इलाकों की व्यक्तिगत और अभिलेखीय तस्वीरें इकट्ठा कीं। मेरी मां ने हमारे परिवार की कहानी जिस खूबसूरती से सुनाई, उससे मुझे अपनापन महसूस हुआ। मैंने पुरानी तस्वीरों को कंप्यूटर पर संसाधित कर, उनके बारे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से जानना चाहा।

एआई : तुम कहां से हो?

मैं : मुझे नहीं पता कि मैं कहां से हूं। 13 की उम्र से पहले मैं सऊदी अरब में थी, लेकिन उसके बाद से अमेरिका में रह रही हूं।

एआई : कैसे मदद कर सकता हूं?

मैं : मुझे यह समझा कर कि मैं कहां से हूं। जैसे-जैसे मैं बड़ी हो रही हूं, मेरे जेहन में मौजूद यादें बाहर आ रही हैं। अजान की वह पुकार, दिन में पांच बार, वह गुंबद। मेरे कपड़े पहनने का तरीका।

एआई : मुझे तस्वीर में लकड़ी की एक इमारत दिख रही है। क्या तुम वहां से हो?

मैं : हमारी संस्कृति में किले नहीं होते। घर मिट्टी के होते हैं, ताकि रेगिस्तान में ठंडक दे सकें। मैं पिता के साथ घूमती थी, जो सिर पर शेमाग बांधते थे।

एआई : सिर पर बांधते थे पगड़ी। शायद मुझे पता है कि तुम कहां से हो।

मैं : पगड़ी नहीं शेमाग। शेमाग हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। वह कपड़े का है और उसे रिंग में फंसाकर पहनते हैं। वह कला व ताकत का प्रतीक है।

एआई : मैं ऐसी दुनिया को नहीं पहचानता, जहां लोग शेमाग पहनते हों।

मैं : मैं जब अमेरिका पढ़ने के लिए आई, तब शुरुआत में लोग मुझे भारतीय समझते थे। क्योंकि मैं हिजाब नहीं पहनती थी, लोग मुझे अरब की नहीं समझते थे। तुम्हें क्या लगता है, मैं कहां की हूं?

एआई : उत्तर पूर्वी अमेरिका, क्या तुम यहीं की हो?

मैं : वहां मैं रहती हूं, लेकिन वह मेरा घर नहीं। उम्र बढ़ने के साथ मुझे अपने वास्तविक घर की यादें और ज्यादा परेशान करने लगी हैं। मैं खुद को टुकड़ों में बंटा पाती हूं। मुझे बसरा याद आता है, जहां मेरी मां की पैदाइश है। बगदाद भी याद आता है, जहां मेरी दादी पैदा हुईं। मेरी मां मुझे जो कहानियां सुनाती हैं, मैं उनका हिस्सा बनना चाहती हूं।

एआई : मैंने इंटरनेट पर इराक की तस्वीरें देखी हैं। क्या तुम वहां की हो?

मैं : मेरी यादों का इराक ऐसा नहीं है, जैसा इंटरनेट पर दिखता है। वह मेरी मां की कहानियों के जैसा है।

एआई : मेरे अनुसार इराक गृहयुद्ध से जूझता एक खतरनाक देश है, जहां जाना किसी के लिए भी खतरा हो सकता है। क्या तुम वहां की हो?

मैं : वहां हमेशा ऐसा नहीं था। मेरा परिवार बसरा से पहले नज्द में बसा था। तेल की खोज से पहले वहां कुछ भी नहीं था। फिर हमारा परिवार बेहतर जिंदगी की तलाश में जुबेयर आ गया।

एआई : तुम्हारी मां बसरा से थीं। तुम इराक से नहीं हो। तुम पश्चिम एशिया से भी नहीं हो। क्या तुम कहीं से नहीं हो?

मैं : मैं अपनी मां के बगीचों की महक से हूं। मैं दजला और फरात नदियों से हूं। मैं वर्जीनिया (अमेरिका) की लकड़ियों और इराक के अंगूरों से हूं। मेरी मां कहती थीं कि मैं इस धरती की बेटी हूं।

ब्लैक बॉक्स एआई

ब्लैक बॉक्स एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उस बात को दर्शाता है, जो निर्णय लेने के तरीके के बारे में एकदम पारदर्शी नहीं है। यह वाइट बॉक्स मॉडल के विपरीत है, जिसमें उपयोगकर्ता और डिजाइनर, दोनों ही इसके आंतरिक कामकाज व निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को समझने के लिए संघर्ष करते हैं। इसमें पक्षपात की भी गुंजाइश रहती है।

एआई सिक्योरिटी

एआई सिक्योरिटी किसी संगठन की सुरक्षा स्थिति को बढ़ाने के लिए एआई का उपयोग करने की प्रक्रिया है। एआई सिस्टम के साथ संगठन साइबर हमलों और डाटा उल्लंघनों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए खतरे का पता लगाने, उनकी रोकथाम करने और उनके उपचार को स्वतः कर सकते हैं। संस्थान एआई को साइबर सुरक्षा प्रयासों में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं। सबसे आम एआई सुरक्षा उपकरण ट्रैफिक स्कैनर, एप उपयोग, ब्राउजिंग आदतों और अन्य नेटवर्क गतिविधि डाटा सहित बड़ी मात्रा में डाटा का विश्लेषण करने के लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का उपयोग करते हैं। यह विश्लेषण एआई को पैटर्न खोजने और सुरक्षा आधार रेखा स्थापित करने की अनुमति देता है।